मेरी खेती

PAGE NO. 1-85, JUNE, 2023

किसान समाचार

खेत खलियान
सरकारी नीतियां
मौसम व अन्य कृषि सुझाव
सब्ज़ी
फूल
औषधीय खेती
पशुपालन - पशुचारा
प्रगतिशील किसान

MERIKHETI

संपादकीय

इस राज्य सरकार ने किसानों के हित में जारी किया बलराम ऐप, कृषि क्षेत्र को मिलेगी नई दिशा

मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार की तरफ से बलराम एप जारी किया है। किसानों को कृषि विशेषज्ञों, भूमि की उर्वरकता की सलाह के साथ बाकी जानकारियां भी हांसिल हो पाएंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, कि भारत का कृषि क्षेत्र निरंतर रूप से प्रगति कर रहा है। केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार किसानों के डिजीटलीकरण पर विशेष जोर दे रही है। किसानों को ऑनलाइन सिस्टम के साथ जोड़ने की मुहिम चल रही है। दरअसल, पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजनाओं की भांति विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन माध्यम से संचालन हो रहा है। किसान स्वयं अपने दस्तावेज अपडेट भी करा रहे हैं। वर्तमान में एक और राज्य की तरफ से ऐसी ही एक पहल की गई है। प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा ही ऐप जारी किया गया है। यह ऐप खेती-बाड़ी में किसान भाइयों की काफी सहायता करेगा।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को डिजीटल करने की बड़ी पहल की गई है। मध्य प्रदेश ने एक खास प्रकार का मोबाइल ऐप जारी किया है। इस ऐप में टू वे कम्यूनिकेशन फीचर्स हैं। यह ऐप किसानों को कृषि संबंधित जानकारी मुहैय्या कराता है। साथ ही, कृषि विशेषज्ञों के साथ संपर्क बढ़ाना भी उद्देश्य है।बलराम ऐप को विशेष रूप से किसानों को मिलने वाली प्रत्येक सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है।

मीडिया खबरों के मुताबिक, इंडो जर्मन तकनीक के कंबाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जारी बलराम ऐप के संचालन की जिम्मेदारी जवाहर लाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है। जो भी किसान अपनी जमीन या खेत की मृदा की सेहत के विषय में जानना चाहता है। यह ऐप उन किसानों के लिए अत्यंत सहयोगी है। इस ऐप की सहायता से कृषि एडवाइजरी प्राप्त हो जाएगी और ऐप पर कृषि विशेषज्ञों द्वारा अपने सुझाव भी दिए जाएंगे। इस ऐप को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपयोग किया जा सकता है। किसान अपनी इच्छा के मुताबिक हिंदी अथवा अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस ऐप को राज्य के 10 जनपदों में जारी कर दिया गया है। यह खरीफ सीजन में कृषकों को काफी सहायता प्रदान करेगा। छतरपुर, जबलपुर, सागर, शहडोल, दमोह, बालाघाट, मंडला, सिंगरौली, रीवा और कटनी के अंदर प्रथम चरण में जारी किया गया है। ऐप में जिला स्तरीय, पंचायत स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय जानकारी मुहैय्या कराई जाएगी। इस एप्लीकेशन से किसानों को राज्य, जिला, विकासखंड के अतिरिक्त ब्लॉक स्तर की कृषि संबंधित जानकारियां उपलब्ध की जाएंगी। राज्य सरकार के अधिकारियों के कहने के मुताबिक, पहले चरण में 25 हजार किसानों को इस ऐप से जोड़ा जाएगा।

संपादक
दिलीप यादव

सलाहकार मंडल

श्री छेदालाल पाठक
संरक्षक मार्गदर्शक

डॉ. एमसी शर्मा,
सेवानिवृत्त निदेशक एवं कुलपति
आईवीआरआई इज्जतनगर

प्रो. ए पी. सिंह
पूर्व कुलपति वेटरनरी विश्वविद्यालय
मथुरा

डॉ. एस. के. गर्ग
कुलपति राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी
एंड एनिमल साइंस

डॉ. ओमवीर सिंह
निदेशक बीज प्रमाणीकरण (सेवानिवृत)
उत्तर प्रदेश

डॉ. उदय भान सिंह
डीन कृषि महाविद्यालय कुम्हेर भरतपुर
राजस्थान

डॉ. उदय भान सिंह

डॉ.हरी शंकर गौड़
साइंटिस्ट, गलगोटियास विश्वविद्यालय

दिलीप यादव
विशेषज्ञ, मेरीखेती

तेजपाल सिंह
प्रगतिशील किसान

कृष्ण पाठक
विशेषज्ञ, मेरीखेती

वोट करने से पहले जानिए अपने पसंदीदा नेता के बारे में सिर्फ NETAHUB पर

netahub.com

इस राज्य में कृषि वैज्ञानिकों ने परवल की 3 बेहतरीन किस्में विकसित की हैं

इस राज्य में कृषि वैज्ञानिकों ने परवल की 3 बेहतरीन किस्में विकसित की हैं

झारखंड राज्य के रांची में मौजूद भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूर्वी प्रक्षेत्र पलांडू के वैज्ञानिकों द्वारा परवल की 3 नई प्रजातियों को विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने इन प्रजातियों का नाम स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण सुरुचि रखा है।

बतादें, कि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई परवल की इन तीन किस्मों से झारखंड के अंदर सब्जी का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एक खुशखबरी है। वैज्ञानिकों द्वारा परवल की ऐसी प्रजाति को विकसित किया गया है, जिसके उपरांत अब पहाड़ों पर भी इसकी खेती करना संभव हो गया है। विशेष बात यह है, कि परवल की यह प्रजाति कम वक्त में ही तैयार हो जाएगी और उत्पादन भी बेहतरीन मिलेगा। साथ ही, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत वर्तमान में राज्य के बहुत से जनपदों में परवल की खेती भी चालू की जाएगी। इसके लिए किसान भाइयों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

किसान तक के अनुसार, रांची में मौजूद भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूर्वी प्रक्षेत्र पलांडू के वैज्ञानिकों द्वारा परवल की 3 नई प्रजातियों को विकसित किया गया है। वैज्ञानिकों ने इन प्रजातियों का नाम स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक एवं स्वर्ण सुरुचि रखा है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने परवल की एक और प्रजाति को विकसित किया है, जिसकी खेती भारत के अन्य दूसरे राज्यों में भी की जा सकती है।

राज्य के 11 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के अनुरूप परवल की खेती का शुभारंभ किया जाएगा

परवल की नवीन प्रजातियों के विकसित होने के उपरांत झारखंड के कृषकों ने वैज्ञानिकों की सराहना और धन्यवाद किया है। किसानों का यह कहना है, कि वर्तमान में हमारे द्वारा उगाए गए परवल का स्वाद अन्य राज्य के लोग भी ले सकेंगे। इससे बिहार राज्य का नाम रौशन होगा और साथ में किसानों की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। ऐसा कहा जा रहा है, कि राज्य के 11 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के अनुरूप परवल की खेती का शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन इसकी देखरेख करेगा। विशेष बात यह है, कि परवल की इन प्रजातियों की खेती ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी की जा सकती है।

परवल की एक एकड़ में खेती करने पर कितना खर्चा आता है

इसी कड़ी में कृषि वैज्ञानिकों का कहना है, कि परवल की खेती से झारखंड के किसानों की आमदनी में काफी इजाफा होगा। क्योंकि, परवल एक ऐसी फसल है, जिसकी खेती चालू करने के उपरांत आप पांच वर्ष तक सब्जी तोड़कर प्राप्त सकते हैं। यदि किसान भाई एक एकड़ जमीन पर परवल का उत्पादन करते हैं, तो उनको लगभग 50 हजार रुपये तक का खर्चा करना पड़ेगा।

लेकिन, इससे किसान अच्छा-खासा फायदा भी अर्जित कर पाऐंगे।

परवल में विटामिन-ए, विटामिन बी और विटामिन-बी1 पाए जाते हैं

जानकारी के लिए बतादें, कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में परवल की सर्वाधिक खेती होती है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश परवल के मुख्य उत्पादक राज्य है। यहां के परवल की बिक्री संपूर्ण भारत में होती है। परवल में विटामिन-बी1, विटामिन बी2, विटामिन-ए एवं विटामिन-सी और कैल्शियम विघमान होता है। परवल की सब्जी बेहद ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। बहुत सारे लोग परवल का अचार बनाकर भी खाते हैं।

करौंदे की खेती से होगा बम्पर मुनाफा, जल्द ही मालामाल हो सकते हैं किसान

करौंदा एक ऐसी फसल है जो किसानों को अतिरिक्त सुरक्षा देने का काम करती है। यह एक बागवानी फसल है जिससे किसान भाई हर रोज कमाई कर सकते हैं। अगर किसान भाई अपने खेत में 100 करौंदा के पेड़ लगाते हैं तो वह 20 हजार रुपये की कमाई बेहद आसानी से कर सकते हैं। आइए हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि करौंदा की खेती कैसे करें, ताकि कम समय में ही आप जल्द से जल्द पैसे कमा सकें।

करौंदा एक झाड़ीदार कांटे वाला पेड़ होता है। इसलिए इसे देखभाल की कोई खास जरूरत नहीं होती है। काटों के कारण इसके पौधे के पास कोई जानवर भी नहीं आता। यह एक ऐसी फसल होती है जिसे लगाने के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत भी नहीं होती। इसे आप खेत के चारों ओर लगा सकते हैं। यह ऐसा पौधा होता है जो बिना पानी के भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इसमें सूखे को सहन करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इसलिए करौंदा बंजर और रेतीली भूमि में भी बेहद आसानी से उग जाता है। इसका पेड़ लगभग 6 से 7 फीट तक ऊंचा होता है। करौंदे की खेती ठंडी जलवायु में कर पाना संभव नहीं है।

करौंदा के लिए उपयुक्त मिट्टी का चुनाव

इसकी खेती के लिए बलुई और दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था हो। साथ ही मिट्टी का पीएच मान 6 से 8 के बीच होना चाहिए।

करौंदा की उन्नत किस्में

वैसे तो बाजार में करौंदा की बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं। लेकिन कैरिसा इब्लिसा, मनोहर, पंत स्वर्ण और सीआईएसएच करौंदा-2 जैसी किस्में किसानों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। इन किस्मों के पेड़ों के फल बड़े होते हैं और उत्पादन भी ज्यादा होता है।

करौंदा की पौध तैयारी एवं रोपाई

करौंदा की पौध की तैयारी बीजों के माध्यम से करते हैं। इसके लिए करौंदा के पके हुए फलों से बीज निकाल लेते हैं और पौधशाला में बुवाई कर देते है। 40 से 60 दिन पुराने पौधों को पन्नी में भरकर रोपाई के लिए तैयार कर लेते हैं।

करौंदा के पौधों की रोपाई जुलाई और अगस्त माह में की जाती है। अगर किसान के पास सिंचाई की उचित व्यवस्था है तो इसकी रोपाई फरवरी से मार्च माह के बीच भी की जा सकती है। करौंदा के पेड़ों की रोपाई गड्ढों में करें। इसके लिए खेत में 2 फ़ीट व्यास का गड्ढे बना लें, साथ ही रोपाई के 30 दिन पहले गड्ढों को गोबर की सड़ी हुई खाद से भर दें। रोपाई के समय एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच कम से कम एक मीटर का फासला जरूर रखें।

करौंदा के लिए खाद एवं उर्वरक की मात्रा

करौंदा की अच्छी ग्रोथ के लिए खाद एवं उर्वरक देना बेहद जरूरी है। जब करौंदा की पौध की रोपाई

करें तब प्रति पौधा के हिसाब से 5 किलो गोबर, 150 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरिया व 75 ग्राम पोटाश दें। खाद एवं उर्वरक की इतनी मात्रा पहले तीन सालों तक देनी है। जब पौधा बड़ा हो जाए तो 450 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 300 ग्राम यूरिया, 15-20 किलो गोबर की खाद व 225 ग्राम पोटाश प्रति वर्ष के हिसाब से दे सकते हैं।

करौंदा के पौधों की सिंचाई

करौंदा के पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। ये पौधे कम पानी में भी काम चला सकते हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में इन पौधों में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। बरसात के मौसम में पौधों के पास से उचित जल निकासी की व्यवस्था जरूर करें।

करौंदा के फलों की तुड़ाई एवं कमाई

करौंदा के पौधे लगाने के 4 से 5 साल बाद इनमें फल आने लगते हैं। पेड़ों पर फल आने के 2 से 3 माह बाद इनकी तुड़ाई की जा सकती है। करौंदा के फलों का उपयोग अचार, सब्जी व चटनी बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसके फलों से जेली भी बनाई जाती है। करौंदा का एक पेड़ 15 से 25 किलो के बीच फल दे सकता है। जिनके फलों की तुड़ाई करके 2 से 3 दिन के बीच विक्रय के लिए मंडी भेज दिया जाता है। अगर किसान एक एकड़ में करौंदा के पेड़ों को लगाएं तो आसानी से 1 लाख रुपये तक की कमाई कर सकते हैं।

किसान भाई इस विधि से करेले की खेती करने पर लाखों का मुनाफा उठा सकते हैं

करेला बागवानी के अंतर्गत आने वाली फसल है। विभिन्न राज्यों में करेले की खेती करने पर कृषकों को अनुदान भी दिया जाता है। करेले की विशेषता यह है, कि इसकी खेती चालू करने में खर्चा बहुत ही कम आता है। वहीं, मुनाफा काफी ज्यादा होता है।

पूरे भारत में करेला की खेती की जाती है। करेले के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन्स और पोषक तत्व विघमान रहते हैं। इसी वजह से चिकित्सक करेले के रस का सेवन करने की सलाह देते हैं। करेले को लोग भुजिया और सब्जी, भरता के तौर पर उपयोग करते हैं। चिकित्सकों की माने तो करेले का जूस पीने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। करेले में विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है, कि इसकी मांग सालों रहती है। ऐसी स्थिति में किसान भाई आधुनिक विधि से इसका उत्पादन कर मोटी आमदनी कर सकते हैं।

करेला बागवानी के अंतर्गत आने वाली एक फसल है

करेला एक प्रकार की बागवानी फसल है। विभिन्न राज्यों में करेले का उत्पादन करने पर किसानों को अनुदान भी प्रदान किया जाता है। करेले की एक ऐसी विशेषता है, कि इसकी खेती चालू करने में बहुत कम खर्चा आता है। जबकि लाभ काफी ज्यादा होता है। यदि किसान भाई करेले की खेती करने की योजना बना रहे हैं, तो बलुई दोमट मृदा में ही इसकी बुवाई करें। क्योंकि बलुई दोमट मृदा करेले की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। यदि आप चाहें तो नदी के किनारे भी करेले का उत्पादन कर सकते हैं। जलोढ़ मृदा में इसकी बेहतरीन पैदावार होती है।

करेले की खेती के लिए कितने डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है

करेले की फसल गर्म मौसम में तीव्रता के साथ विकास करती है। इसके लिए 20 डिग्री से 40 डिग्री तक का तापमान सबसे अच्छा माना गया है। अब ऐसी स्थिति में करेले की फसल को समुचित सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। हालाँकि, करेले की खेती वर्ष भर की जा सकती है।

परंतु, वर्ष में तीन बार इसकी बुवाई की जाती है। यदि किसान भाई जनवरी से मार्च माह के मध्य इसकी बुवाई करते हैं, तो अप्रैल से करेले का उत्पादन शुरू हो जाएगा। यदि किसान भाई बारिश के मौसम में इसकी बुवाई करना चाहते हैं, तो जून से जुलाई माह इसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन, पहाड़ी क्षेत्रों के किसान मार्च से जून माह के मध्य करेले की बुवाई कर सकते हैं।

बुवाई करने के 70 दिनों में फसल तोड़ने लायक तैयार हो जाती है

करेले की बुआई चालू करने से पूर्व खेत की बेहतर ढ़ंग से जुताई कर लें। उसके बाद खेत को एकसार कर लें। इसके बाद क्यारियां तैयार करके बीज की बुवाई करें। बीज सदैव 2 से 2 .5 सेमी गहराई में ही बोयें। विशेष बात यह है, कि बुवाई करने से पूर्व 24 घंटे तक बीज को पानी में भिगोकर रख दें। इससे बीज अतिशीघ्र अंकुरित होते हैं। जब करेले के पौधे बड़े हो जाएं, तब उसे लकड़ी अथवा बांस की मदद से उंचाई पर ले जाएं। इससे बेहतरीन उत्पादन हांसिल हो पाऐगा। इसी विधि को वर्टिकल फार्मिंग कहा जाता है। इस विधि से खेती करने पर बारिश होने की स्थिति में भी फसल की बर्बादी नहीं होती है। विशेष बात यह है, कि बुवाई करने के 70 दिनों के समयांतराल में फसल पककर तोड़ने हेतु तैयार हो जाती है।

कैसे करें कद्दू की फसल से कमाई; जाने फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी

कैसे करें कद्दू की फसल से कमाई; जाने फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी

कद्दू एक ऐसी फसल है जो बहुत ही कम समय में पक कर तैयार हो जाती हैं. साथ ही कद्दू में काफी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो इस सब्जी को स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक बना देता है. कद्दू की फसल की बात की जाए तो यह एक पौधों की श्रेणी में आता है और कद्दू के बीज को खाने में इस्तेमाल किया जाता है|

सब्जी बनाने के अलावा कद्दू का इस्तेमाल बहुत सी मिठाइयां बनाने में भी किया जाता है

कद्दू में प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और साथ ही इसमें जेल भी होता है जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है. डॉक्टर सर्दी जुखाम और वायरल जैसे संक्रमण के समय कद्दू खाने के लिए कहते हैं. इन सबके अलावा अगर किसान कद्दू की खेती करना चाहते हैं तो वह यह फसल उगा कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं. इस आर्टिकल के माध्यम से कद्दू की फसल के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है|

कद्दू की फसल उगाने के लिए कैसी मिट्टी सही रहती है?

किसी भी फसल की तरह कद्दू की खेती के लिए भी उपजाऊ भूमि होना अनिवार्य है और साथ ही भूमि ऐसी होनी चाहिए जिसमें जल निकासी का उचित प्रबंध हो। यह फसल गर्म और ठंड दोनों ही तरह की जलवायु में उगाई जा सकती है। कद्दू की फसल लगाते समय हम एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि इस फसल को बाकी फसलों के मुकाबले ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। फसल में सिंचाई के लिए पानी ज्यादा लगता है लेकिन एक और बात का ध्यान रखने की जरूरत है की फसल में किसी भी समय जलभराव नहीं होना चाहिए वरना यह फसल बर्बाद हो सकती है।

इकद्दू की अच्छी फसल के लिए जमीन का P.H. मान 5 से 7 के मध्य होना चाहिए|

कद्दू की खेती के लिए सही जलवायु और तापमान

शीतोषण और समशीतोष्ण जलवायु को कद्दू की फसल के लिए एकदम अनुकूल माना जाता है और यही कारण है कि हमारे देश में कद्दू की फसल बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं। गर्मी का मौसम कद्दू की फसल के लिए एकदम सही माना गया है क्योंकि सर्दियों में जब ज्यादा पाला पड़ता है तो कद्दू के फूल अच्छी तरह से बड़े नहीं हो पाते हैं और कई बार झड़कर गिरने लगते हैं। इसके अलावा हमें एक और बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि एक बार जब फसल पर फूल आ जाए तो उस समय बारिश का मौसम नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे फूलों के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इस फसल के बीजों के बनने के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना जरूरी है और वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि आप की फसल अच्छी तरह से उत्पादन करें तो तापमान 25 से 30 डिग्री के मध्य होना जरूरी है।

कद्दू की फसल की कुछ किस्म

कद्दू की फसल अच्छी हो और उसका उत्पादन सही रहे इसके लिए कद्दू की कई अलग-अलग किस्म तैयार की गई है और आप उत्पादन क्षमता के आधार पर उनका चुनाव कर सकते हैं।

पूसा विश्वास किस्म

भारत में उत्तर भारत के कई राज्यों में यह फसल उगाई जाती है और इसमें एक कद्दू का वजन लगभग 5 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इसमें निकलने वाले फल हरे रंग के होते हैं और साथ ही उन पर छोटे-छोटे सफेद धब्बे बने रहते हैं। एक बार उगाने के बाद यह फसल लगभग 120 दिन में पक कर तैयार हो जाती है और जमीन में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 40 क्विंटल कद्दू की पैदावार इस किस्म को लगाने के बाद मिल जाती है।

काशी उज्जवल किस्म

उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत में भी यह कैसे उगाई जाती है और इसमें एक कद्दू का वजन ही 10 से 15 किलो तक होता है। इसमें कद्दू के 1 पौधे पर चार से पांच फल आ जाते हैं और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 550 क्विंटल का उत्पादन इस किसी से हो जाता है। इस फसल को बनने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है जो तकरीबन 6 महीने तक हो सकता है।

डी.ए.जी.एच. 16 किस्म

यह किस्म एक बार उगाने के बाद लगभग 100 से 110 दिन के बीच में पैदावार देती है और इससे उगने वाले फल का रंग भी हरे और सफेद का मिश्रण होता है। इसमें कद्दू का वजन 12 किलोग्राम तक चला जाता है और एक पौधे पर चार से पांच फल आ जाते हैं। अगर पैदावार की बात की जाए तो जमीन में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यह किस्म 400 से 500 क्विंटल की पैदावार दे देती है।

काशी धवन किस्म

कद्दू की यह किस्म ज्यादातर पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में उगाई जाती है और इसे पककर तैयार होने में लगभग 3 महीने का समय लगता है। इसमें कद्दू के फल का वजन 12 किलोग्राम तक होता है और प्रति हेक्टेयर में आप लगभग 600 क्विंटल की पैदावार आसानी से कर सकते हैं।

पूसा हाईब्रिड 1

यह कद्दू की एक हाइब्रिड किस्म है और इसे ज्यादातर वसंत ऋतु के मौसम में उगाया जाता है। इसमें पौधे पर लगने वाले फल का वजन थोड़ा कम होता है, जो लगभग 5 किलोग्राम के आस पास होता है| और इसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग साढे 500 क्विंटल की पैदावार की जा सकती है।

कैसे करें कद्दू की फसल के लिए खेत को तैयार?

बाकी फसल की तरह ही कद्दू की फसल लगाने से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करने के बाद उसमें पुरानी गोबर की खाद डालकर खेत को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद एक बार और जुताई करते हुए जमीन को भी भुरभुरा कर लिया जाता। उसके बाद जमीन को समतल करते हुए कद्दू की फसल को क्यारियां बनाकर लगाया जा सकता है।

क्या है कद्दू के बीजों की रोपाई का सही समय और तरीका

कद्दू के बीज ज्यादातर किसान अपने हाथ से ही लगाते हैं और प्रति हेक्टेयर जमीन में 3 से 4 किलो बीज लग जाते हैं। | बीजो को खेत में लगाने से पहले उन्हें थीरम या बाविस्टीन की उचित मात्रा का घोल बना कर उपचारित कर लेना चाहिए | इसके बाद इन बीजो की खेत में तैयार की गई धोरेनुमा क्यारियों में रोपाई कर दे | जब आप क्यारियां बनाते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि क्यारियों के बीच में लगभग 4 से 5 मीटर की दूरी रखी जाए और बीजों के मध्य भी एक से डेढ़ फीट तक की दूरी बना कर रखना अनिवार्य है। ऐसा करने से पौधे अच्छी तरह से विकसित होते हैं और फसल भी अच्छी मिलती है।

अगर आप पर्वतीय इलाकों में है फसल उगाना चाहते हैं तो मार्च या अप्रैल के महीने में यह किया जा सकता है और जहां पर सिंचाई कम की जाती है वहां पर यह फसल बारिश के मौसम में जून के आसपास लगाई जाती हैं। इसके अलावा भारत में बहुत सी जगह है यह फसल अगस्त के महीने में भी उगाई जाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इसे अगस्त माह में उगाया जाता है |

कैसे करें कद्दू के फसल की सिंचाई

कद्दू की फसल में जब बीजों का अंकुरण हो रहा होता है तब उसे ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अगर आप अच्छी तरह से सिंचाई करेंगे तभी आपको अच्छा फल मिलने की संभावना है। जमीन में नमी बरकरार रहे इसीलिए कद्दू के खेत में तीन से चार दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना जरूरी है। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में भी एक हफ्ते के अंदर-अंदर इसमें पानी देना जरूरी है। साथ ही अगर आप बारिश के मौसम में है फसल उगा रहे हैं तो जरूरत पड़ने पर ही फसल की सिंचाई करें वरना फसल में पानी ठहर जाने की संभावना बनी रहती है जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो सकती हैं।

कद्दू की फसल के लिए कौन से उर्वरक हैं सही?

अगर आप चाहते हैं कि आप की फसल की पैदावार अच्छी हो और साथ ही आपको उन्नत किस्म का फल मिले तो आपको और ध्यान देने की जरूरत। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि जुताई के समय खेत में पुराने गोबर की खाद डाली जाती हैं। इसके अलावा जैविक खाद के रूप में कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप केमिकल खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 40KG नाइट्रोजन, 50KG पोटाश और 50KG फास्फोरस की मात्रा को खेत की आखरी जुताई के समय प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़क देना चाहिए|

कैसे करें कद्दू के खेत में खरपतवार पर नियंत्रण?

किसी भी फसल में खरपतवार का नियंत्रण करना बेहद जरूरी है लेकिन कद्दू के पौधों में आपको इसके बारे में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि यह फसल एक बेल के रूप में पूरे खेत में फैलती है और इसमें ज्यादा खरपतवार होने की संभावना बनी रहती हैं। समय-समय पर फसल में निराई और गुड़ाई करते रहना चाहिए। आप इसे हर 2 से 3 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार पौधे के बड़े हो जाने के बाद आप यह प्रक्रिया 10 दिन के अंतराल पर करना शुरू कर सकते हैं।

महोगनी की खेती कैसे होती है?

कद्दू की फसल में लगने वाले रोग और उनसे बचाव?

कद्दू की फसल में लगने वाले कुछ रोग इस प्रकार से हैं;

लालड़ी रोग

इस रोग को अंग्रेजी में पंपकिन विटल भी कहा जाता है और अगर एक बार पौधे में यह रोग लग जाता है तो पौधे का विकास होना बंद हो जाता है। यह रोग ज्यादातर पौधे की जड़ों और उसकी पत्तियों को प्रभावित करता है और एक बार यह रोग लग जाने के बाद बत्तियां मुरझाकर सूखने लगती हैं। इसकी रोकथाम ट्राइक्लोफेरान या डाईक्लोरोवास में से किसी एक दवा का उचित मात्रा में छिड़काव करते हुए किया जा सकता है।

फल मक्खी रोग

जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है यह रोग फसल के फलों को नुकसान पहुंचाता है। इसमें मक्खी फलों के अंदर छेद कर देते हैं और उसमें अंडे देना शुरु कर देते हैं। इसमें आपको फल के अंदर कीड़े नजर आते हैं जो पूरी तरह से फसल को और फलों को बर्बाद कर देते हैं| यह रोग लगने के बाद धीरे-धीरे फल खराब होकर गिरने लगते हैं। कार्बारिल या मैलाथियान का उचित मात्रा में छिड़काव कर इस कीट रोग की रोकथाम की जा सकती है|

सफ़ेद सुंडी रोग

यह रोग जमीन के अंदर से फसल को प्रभावित करता है। सबसे पहले यह रोग पौधे की जड़ों में फैलता है और धीरे-धीरे पौधे को सुखाकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अगर आप इस रोग की रोकथाम चाहते हैं तो जुताई के समय आप नीम का घोल बनाकर जमीन में डाल सकते हैं।

मोज़ैक रोग

यह एक विषाणु से होने वाला रोग है जिसकी वजह से पौधा पूरी तरह से विकसित होना बंद हो जाता है और अगर किसी तरह पौधे का विकास हो भी जाए तो उस पर आने वाला फल बहुत ही छोटे आकार का होता है। इस तरह के रोग से छुटकारा पाने के लिए मोनोक्रोटोफॉस या फास्फोमिडान का उचित मात्रा में छिड़काव किया जाना चाहिए|

एन्थ्रेक्नोज रोग

यह रोग कद्दू की फसल को बारिश के मौसम में ज्यादा प्रभावित करता है और इस रोग के होने से पौधे की पत्तियां काले और भूरे रंग के धब्बों से भर जाती है। धीरे-धीरे यह सारी फसल में फैल जाता है और पौधे का विकास होना बंद हो जाता है। इस तरह के रोग से बचाव के लिए पौधों पर हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल का उचित मात्रा में छिड़काव करे|

फल सड़न रोग

एक बार जब कद्दू की फसल पर फल आ जाते हैं तो कोशिश करें कि उन्हें समय-समय पर पलटते रहे वरना उनमें पल सड़न रोग लगने की संभावना हो जाती हैं। अगर आप इस रोग से बचाव चाहते हैं तो फसल में टेबुकोनाजोल या वैलिडामाईसीन का छिड़काव करना चाहिए|

कद्दू की फसल से मिलने वाला लाभ और पैदावार

सामान्यता कद्दू की फसल 100 से 110 दिन के बीच में बनकर तैयार हो जाती है| जब कद्दू हल्के पीले रंग के होने लगे और उसमें बीच-बीच में थोड़ी सफेदी आ जाए तो आप फल को तोड़ सकते हैं। एक हेक्टेयर जमीन पर सामान्यतया 400 क्विंटल तक फसल की पैदावार की जा सकती है और कद्दू मार्केट में 10 से ₹15 प्रति किलो के भाव से बिकता है। ऐसे में किसान एक बार फसल लगाकर लगभग 5 से ₹6 लाख तक की अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं।

फल

पीले तरबूज का स्वाद लोगों को लाल तरबूज से ज्यादा पसंद आ रहा है, मुनाफा भी मिल रहा है।

पीले तरबूज का स्वाद लोगों को लाल तरबूज से ज्यादा पसंद आ रहा है, मुनाफा भी मिल रहा है।

आजकल नई नई तकनीक और फसलों की विभिन्न नई किस्में विकसित हो रही हैं। पीला तरबूज इस भूमि पर सिर्फ आज से नहीं बल्कि 5 हजार वर्ष पूर्व से है। पहले यह केवल अफ्रीका के अंदर ही की जाती था। परंतु, अब इसको पूरे विश्व में उत्पादित किया जाता है।

गर्मियों का मौसम आते ही तरबूजों की मांग बाजार में काफी बढ़ जाती है। यदि आप भी तरबूजों को पसंद करते हैं, तो गर्मी में लाल-लाल तरबूज खाने से स्वयं को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हम आज लाल तरबूज के नहीं पीले तरबूज के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लाल तरबूज से कहीं अधिक अच्छा होता है पीला तरबूज। बाजार में भी फिलहाल लाल तरबूज की भांति पीले तरबूज की भी मांग बढ़ी है। अधिकांश लोग फिलहाल इस तरबूज को बेहद अच्छा मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर विघमान गुण इसे औषधीय रूप से लाल तरबूज से बेहतर बताते हैं। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बतादें पीले तरबूज का स्वाद भी लाल तरबूज से अच्छा होता है।

पीला तरबूज किस जगह से आया है?

पीला तरबूज इस धरती पर सिर्फ अभी से नहीं बल्कि 5 हजार वर्ष पहले से मौजूद है। पूर्व में यह केवल अफ्रीका में पैदा किया जाता था। अब इसको संपूर्ण विश्व में उत्पादित किया जाता है। अमेरिका, चीन और बाकी बहुत सारे देशों में इस तरबूज की मांग में वृद्धि हुई है। भारतीय बाजारों में भी गिने-चुने कुछ स्थानों पर यह मौजूद है। दरअसल, आजतक यह लोकल बाजारों में आवक नहीं हुई है। परंतु, धीरे-धीरे यह तीव्रता से लोकल बाजारों में भी पहुंच जाएगा।

किस वजह से तरबूज का रंग पीला होता है?

विज्ञान के मुताबिक, तरबूजों का रंग किस प्रकार का होगा यह निर्धारित करता है, लायकोपीन नाम का एक रसायन। जिस तरबूज में यह रसायन अधिक होता है, उस तरबूज का रंग उतना ही ज्यादा लाल होता है। पीले तरबूज में यह रसायन मौजूद नहीं होता है। यही वजह है, कि इस तरबूज का रंग पीला होता है।

हालांकि, पीला तरबूज लाल तरबूज की तुलना में अधिक मीठा होता है। इसे खाने वाले लोग कहते हैं, कि इसका स्वाद बिल्कुल शहद की भांति होता है। इस तरबूज में विटामिन ए की मात्रा प्रचूर मात्रा में पायी जाती है।

यह तरबूज मुख्यत कहा उगाया जा सकता है

यह तरबूज हर एक जगह पर उत्पादित नहीं किया जा सकता। इनको डेजर्ट किंग भी कहा जाता है, मतलब कि रेगिस्तान का राजा। यह केवल रेगिस्तानी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यदि आप पीले तरबूजों की खेती करना चाहते हैं, तो भारत में यह केवल गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ही संभव है।

अनार की खेती करके किसान हो सकते हैं मालामाल, कम लागत में होता है जबरदस्त मुनाफा

अनार एक बेहतरीन फल है। जो विटामिन्स और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, इसके सेवन से शरीर में कभी भी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। अनार में आयरन, पोटेशियम, जिंक, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी और ओमेगा-6 की प्रचुरता होती है। जो शरीर को स्वस्थ और तंदरुस्त रखने में सहायक होते हैं। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए बाजार में इन दिनों अनार की भारी मांग रहती है। ऐसे में अगर किसान भाई बाजार की मांग की पूर्ति के लिए अनार की खेती करें तो इससे वो कम समय में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।

यह एक ऐसी फसल है जो उच्च तापमान वाली जगहों पर उगाई जाती है। अनार के पेड़ तेज धूप और उच्च तापमान सहन करने की क्षमता भी रखते है। साथ ही इस फसल में पानी की जरूरत भी बेहद कम होती है। इस कारण से इस फसल की खेती गर्मियों में की जाती है। गर्मियों का मौसम इस फसल के लिए बेहद अनूकूल माना गया है। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, अनार की फसल उतनी तेजी के साथ ग्रोथ कर सकेगी। ज्यादा सिंचाई करने पर अनार के पेड़ अच्छी ग्रोथ नहीं करते हैं। यही कारण है कि इसकी खेती ज्यादा वर्षा वाले स्थानों पर नहीं की जाती है। भारत में अनार की खेती मुख्यतः राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में की जाती है।

कृषि वैज्ञानिक बताते है कि यह एक सब-ट्रॉपिकल क्लाइमेट पौधा है जो गर्म और उष्ण मौसम में तेजी से विकसित होता है। तेज गर्मी वाले मौसम में इसके फल तेजी से विकसित होते हैं। साथ ही अगर मौसम गर्म रहा तो इस फसल की कटाई भी समय पर की जाती है। अगर अनार के खेत में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है तो यह उसके लिए सबसे अच्छा माना गया है।

अनार की खेती के लिए रेतीली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इस मिट्टी में अनार का पौधा तेजी से ग्रोथ करता है। अनार के पौधों की रोपाई अगस्त से फरवरी माह के बीच की जाती है। इस दौरान किसान भाई नर्सरी से अनार का पौधा लाकर अपने खेत में लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके पौधे कलम विधि द्वारा भी तैयार किए जा सकते हैं। एक साल पुरानी शाखाओं से 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी कलमों को काटकर नर्सरी में बेहद आसानी से पौधा तैयार किया जा सकता है। जब कलम में जड़ें विकसित होने लगें तो पौधे को खेत में स्थानांतरित कर दें।

फिलहाल बाजार में अनार की कई किस्में उपलब्ध हैं। जिनके पौधे किसान भाई अपने खेत में लगा सकते हैं। ज्योति, मृदुला, कंधारी, अरक्ता और सुपर भगवा अनार की कुछ बेहतरीन किस्मों के नाम हैं। ज्योति किस्म के फल साइज़ में बड़े होते हैं और इनमें रस ज्यादा निकलता है।

साथ ही मृदुला किस्म के फल मीडियम साइज के होते हैं और इनके बीजों का रंग लाल होता है। अगर किसान भाई अनार के पेड़ लगाते हैं तो वह पेड़ आगामी 25 सालों तक फल देता रहेगा। जिससे किसान भाई को बिना किसी मेहनत के 25 सालों तक अनार की फसल प्राप्त होती रहेगी।

किसान शहतूत की खेती से कमा रहा लाखों, अन्य किसानों के लिए भी बना नजीर

आज हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे किसान की जिसने लीक से हटकर कुछ नया करने की सोची है। हम बात कर रहे हैं, एक शहतूत की खेती करने वाले किसान आयुष जाटव के बारे में। जो कि पहले पारंपरिक विधिवत तरीके से खेती किया करते थे। इसमें उनको अधिक मुनाफा नहीं हो पाता था। ऐसी स्थिति में आर्थिक हालत उनकी डगमगाती जा रही थी।

जैसा सा कि हम जानते हैं, बागवानी का नाम सुनते ही सर्वप्रथम आमजनता के दिमाग में सेब, केला, आम, नाशपाती और अमरुद का नाम सामने आता है। अधिकांश लोगों का मानना है, कि केला, नाशपाती आम, अमरूद और सेब ही ऐसी बागवानी फसल हैं, जिसकी खेती से बेहतरीन आमदनी की जा सकती है। परंतु, असलियत में ऐसी कोई बात नहीं है। इन समस्त फलों के अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे फल हैं, जिसकी खेती से किसानों को मोटी आमदनी हो सकती है। इन्हीं में से एक शहतूत का भी फल है।

चुनौतियों के बाद भी मिशाल पेश की

न्यूज 18 हिन्दी के अनुसार, आमतौर पर शहतूत की खेती किसान बेहद कम करते हैं। वहीं, बाजार के अंदर शहतूत बिकता भी काफी कम है। परंतु, इसकी कीमत काफी अधिक होती है। जानकारी के लिए बतादें कि शहतूत को एक औषधीय फल भी माना जाता है। अगर हम इसके स्वाद की बात करें तो यह खाने में खट्टा- मीठा लगता है। मार्च-अप्रैल के माह में शहतूत के पेड़ फलों से लद जाते हैं। अगर वक्त रहते इसको तोड़ा नहीं गया, तो पकने के उपरांत शहतूत अपने- आप जमीन पर टूटकर गिरने लगते हैं। विशेष बात यह है, कि शहतूत से औषधियां भी निर्मित की जाती हैं। इसके बावजूद भी किसान इसका उत्पादन करने से सकुचाते हैं। परंतु, अब राजस्थान के एक किसान ने शहतूत की सफलतापूर्वक खेती करके लोगों के समक्ष नजीर प्रस्तुत की है।

आयुष जाटव प्रति वर्ष कितनी आमदनी करते हैं

बतादें कि किसान आयुष जाटव भरतपुर जनपद के भुसावर के रहने वाले हैं। उन्होंने वहीं अपने बाग में शहतूत की खेती की है। इससे उनको अच्छा-खासा मुनाफा भी हुआ है। पहले वह पारंपरिक ढंग से शहतूत की खेती किया करते थे,जिससे उनको काफी ज्यादा घाटा हो रहा था। परंतु, एक मित्र द्वारा दी गई सलाहनुसार उन्होंने आधुनिक विधि से खेती करना शुरू कर दिया था। दरअसल, किसान आयुष ने 6 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल से शहतूत के 500 से ज्यादा पौधे मंगवाए व उनकी रोपाई भी कर दी। अभी 3 हेक्टेयर में आयुष ने शहतूत की खेती कर रखी है। इसकी खेती से वह प्रति वर्ष 20 लाख रुपये की आमदनी कर रहे हैं।

शहतूत का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक

आयुष जाटव ने बताया है, कि पहले वह पारंपरिक विधि से खेती किया करते थे। इसमें उनको कोई ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। अब ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित होती जा रही थी। एक दिन उनके एक मित्र ने उनको शहतूत की खेती करने का मशवरा दिया। इसके उपरांत उनहोंने पश्चिम बंगाल से पौधे मंगवाकर इसकी खेती चालू की थी। तीन वर्ष के उपरांत ही पेड़ पर फल आने चालू हो गए, जिससे उनको अच्छी आमंदनी होने लगी। फिलहाल, उनके घर की आर्थिक स्थिति खूब अच्छी हो गई है। आयुष जाटव का कहना है, कि शहतूत का सेवन करने से शरीर मजबूत होता है। शहतूत में बहुत सारे विटामिन्स और पोशक तत्व विघमान होते हैं। ऐसी स्थिति में इसके सेवन से त्वाचा पर चमक रहने के साथ शरीर निरोगी भी रहता है।

फूल

छत्तीसगढ़ में किसान कर रहे हैं सूरजमुखी की खेती, आय में होगी बढ़ोत्तरी

छत्तीसगढ़ देश का प्रमुख धान उत्पादक राज्य है। जहां धान की खेती सर्वाधिक होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहां के ज्यादातर किसान अपने खेतों में धान का उत्पादन करते हैं और उसी से उनकी आजीविका चलती है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया है कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के लिए कई जनहितकारी योजनाएं लेकर आ रही है। जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा लाई जा रही जनहितकारी योजनाओं के कारण अब किसान धान की खेती के अलावा अन्य खेती की तरफ भी रुख कर रहे हैं। जिससे किसानों को भविष्य में फायदा होने वाला है। क्योंकि अन्य फसलों के उत्पादन में धान की अपेक्षा किसानों को ज्यादा मुनाफ़ा मिल सकता है। छत्तीसगढ़ शासन ने घोषणा की है कि धान के अलावा अन्य फसलों को उगाने पर सरकार किसानों को सीधे सब्सिडी प्रदान करेगी।

सरकार के प्रोत्साहन से प्रभावित होकर प्रदेश के कई किसानों ने अपने यहां सूरजमुखी की खेती प्रारंभ कर दी है। रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखण्ड के ग्राम बोन्दा के किसान तेजराम गुप्ता ने बताया है कि उन्होंने अपने खेतों में अब धान की जगह पर सूरजमुखी की खेती करना प्रारंभ कर दी है। इसमें उन्हें ज्यादा लाभ हो रहा है। किसान तेजराम गुप्ता ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों ने उन्हें यह खेती करने के लिए प्रोसाहित किया है। अधिकारियों ने सूरजमुखी की खेती की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई है। साथ ही बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं कीटनाशक भी उपलब्ध करवाए हैं। इसके लिए किसी भी तरह के पैसे नहीं लिए गए हैं। यह सहायता पूरी तरह से मुफ़्त उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा उन्होंने 5 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट स्वयं से खरीदकर खेत में डाला है।

किसान तेजराम गुप्ता ने बताया है कि उन्होंने सूरजमुखी की खेती के लिए कड़ी मेहनत की है। इसके लिए खेत तैयार करने के लिए 3 बार गहरी जुताई की है और दो बार रोटवेटर से खेत तैयार किया है। इसके बाद वर्मी कम्पोस्ट को खेत में मिलाकर बुवाई की है। बुवाई के 20 दिन बाद निराई गुड़ाई का काम किया है और सिंचाई की है। कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर क्लोरोपाईरीफास एवं एजाडिरेक्टिन 1500 पी.पी.एम.का छिडक़ाव किया है। अब फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। फसल को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार सूरजमुखी की खेती से अच्छा खासा लाभ होने वाला है।

किसान तेजराम गुप्ता ने बताया है कि सूरजमुखी की फसल उगाने से उनकी आय में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके साथ ही फसल चक्र होने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हुई है। अब राज्य के अन्य किसान भी खेती में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करने लगे हैं जिससे उत्पादन में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है और लोगों की आय भी बढ़ी है। इन दिनों भारत में तिलहन की काफी कमी चल रही है, जिसके चलते तिलहन की जबरदस्त मांग बनी हुई है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सूरजमुखी विदेशों से आयात करता है ऐसे में भारत के किसान सूरजमुखी का उत्पादन करके घरेलू मांग की आपूर्ति आसानी से कर सकते हैं।

महिला किसान गेंदे की खेती से कर रही अच्छी-खासी आमदनी

आजकल बदलते दौर में किसान अपना रुख परंपरागत खेती से हटकर अधिक मुनाफा देने वाली फसलों की खेती करने लगे हैं। इसी कड़ी में झारखंड राज्य के पलामू जनपद की रहने वाली एक महिला किसान गेंदे के फूल की खेती से अमीर हो गई है। फिलहाल, आसपास की महिलाएं और पुरूष भी उससे गेंदे की खेती करने के गुर सीख रहे हैं।

गेंदे के फूल का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर किया जाता है

हालाँकि, भारत में सभी प्रकार के फूल उत्पादित किए जाते हैं। परंतु, गेंदा की खेती सर्वाधिक की जाती है। क्योंकि इसका इस्तेमाल भी सर्वाधिक होता है। बतादें कि इसका उपयोग मंच और घर को सजाने से लेकर पूजा- पाठ में सबसे ज्यादा किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं नेताओं के स्वागत में सबसे अधिक गेंदे की माला ही गले में ड़ाली जाती है।

साथ ही, मंदिर और घर के तोरण द्वार भी गेंदे से ही निर्मित किए जाते हैं। ऐसे में किसान गेंदे की खेती कर बेहतर आय कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही महिला किसान की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसकी किस्मत गेंदे के फूल की खेती से बिल्कुल बदल गई। न्यूज 18 हिन्दी की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड के पलामू जनपद की रहने वाली एक महिला गेंदे के फूल की खेती कर के मालामाल हो गई है।

आसपास की महिलाऐं और पुरुष मुन्नी से गेंदे की खेती सीखने आते हैं

अब समीपवर्ती महिलाएं और पुरूष भी उससे गेंदे की खेती करने का तौर तरीका सीखने आ रहे हैं। शेष बात यह है, कि उसने अपने मायके में गेंदे की खेती करने की तकनीक सीखी थी। शादी होने के बाद जब वह अपने ससुराल आई तो स्वयं ही उसने गेंदे के फूल की खेती करनी चालू कर दी। महिला का नाम मुन्नी देवी है। वह पांडू प्रखंड के तिसीबार गांव की रहने वाली है। हाल में वह लगभग 10 एकड़ की भूमि पर गेंदे की खेती कर रही है।

गेंदे के फूल की एक माला की कितनी कीमत है

मुन्नी देवी का कहना है, कि ससुराल आने के उपरांत उन्होंने वर्ष 2019 में गेंदे की खेती आरंभ की थी। प्रथम वर्ष ही उनको काफी अच्छा फायदा हुआ था। इसके उपरांत वह खेती के रकबे में इजाफा करती गईं, जिससे उनका मुनाफा भी बढ़ता गया। मुख्य बात यह है, कि मुन्नी देवी खेती करने के लिए प्रतिवर्ष कलकत्ता से गेंदे के पौधों को मंगवाती हैं। उसके बाद पौधों को लगाकर उनमें वक्त पर उर्वरक और सिंचाई करती हैं। तीन माह में पौधों में गेंदे के फूल आने शुरू हो जाते हैं। इसके उपरांत वह माला बनाकर बेच देती हैं। केवल एक माला 15 रुपये में बेची जाती है, जिसके अंतर्गत गेंदे के 40 फूल गुथे रहते हैं।

मुन्नी वर्षभर में लाखों रुपये की आमदनी कर रही है

सालाना आमदनी को लेकर मुन्नी देवी ने कहा है, कि वर्ष में वह दो बार गेंदे की खेती करती हैं। जनवरी के माह में लगाए गए पौधों में तीन माह के अंतर्गत फूल आ जाते हैं। क्योंकि, अप्रैल से लेकर जून तक शादियों का सीजन चलता है। ऐसे में गेंदे की बिक्री बड़ी ही सुगमता से हो जाती है। उसके बाद अगस्त और सितंबर माह में गेंदे के पौधों का रोपण किया जाता है। सर्दियों के मौसम में यह फूलों से लद जाते हैं। इसके चलते पौधों में बड़े-बड़े आकार के सुगंधित गेंदे के फूल आते हैं। फिलहाल,मुन्नी देवी गेंदे की खेती से वर्षभर में लाखों रुपये की आमदनी कर रही हैं।

मशीनरी

कम जोत वाले किसानों के लिए कम दाम और अधिक शक्ति में आने वाले ट्रैक्टर

एक समय था, जब किसान खेती करने के लिए बैल और हल का उपयोग किया करते थे। लेकिन, आज के समय के किसान ट्रैक्टर जैसे अत्याधुनिक कृषि यंत्रों से कृषि कार्य करते हैं। दरअसल, ट्रैक्टर की कीमत अधिक होने की वजह से छोटी जोत करने वाले कृषकों को ट्रैक्टर खरीदने से पहले कई बार विचार करना पड़ता है। ट्रैक्टर आज के समय में कृषि क्षेत्र का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। आधुनिकता और कृषि से जुड़े नवीन अविष्कारों के चलते किसान काफी अच्छा उत्पादन कम समय और श्रम खर्च किए बिना उठा रहे हैं। अगर हम बात करें कि छोटी जोत के किसानों को अधिक महंगा ट्रैक्टर खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे ट्रैक्टरों के विषय में बताएंगे जो काफी छोटे हैं और इनकी कीमत भी काफी कम है। छोटे किसान इनको बड़ी आसानी से खरीदकर अपना कृषि कार्य सुगमता से कर सकते हैं।

सोनालिका GT20 ट्रैक्टर

सोनालिका GT20 ट्रैक्टर भी तीन सिलेंडर के साथ आता है और इसमें 20 हॉर्स पॉवर की ताकत होती है। इस ट्रैक्टर में कुल 8 गियर होते हैं और यह खेती से जुड़े लगभग वो समस्त कार्य कर लेता है, जो कि एक बड़ा ट्रैक्टर कर सकता है।

इस ट्रैक्टर में सिंगल क्लिच के साथ ही मैकेनिकल ब्रेक भी दिए गए हैं। इसका वजन 650 किलोग्राम है और यह बाजार में 3 से 3.5 लाख रुपये के मध्य आपको सुगमता से प्राप्त हो जाएगा।

कैप्टन 283 4WD 8G ट्रैक्टर

बतादें कि इसको मिनी ट्रैक्टर कहा जाता है। यह विशेष रूप से छोटी जोत के किसानों के लिए ही निर्मित किया गया है। 3 सिलेंडर वाला यह ट्रैक्टर दिखने में बेसक छोटा है, परंतु शक्तिशाली है। इसमें 27 हॉर्स पॉवर की शक्ति उपस्थित है। यह मिनी ट्रैक्टर हर वह कार्य कर सकता है, जिस कार्य को एक बड़ा ट्रैक्टर कर सकता है। इसमें समकुल 12 गियर होते हैं, जिसमें से 9 आगे की तरफ लगते हैं और 3 पीछे की तरफ लगाए जाते हैं। 750 किलो के इस ट्रैक्टर का बाजार में भाव तकरीबन 4.25 से 4.50 लाख रुपये है। इसे आप कर्ज पर भी खरीद सकते हैं।

जॉन डियर 3028 EN ट्रैक्टर

जॉन डियर 3028 EN एक मिनी ट्रैक्टर है। लेकिन इसकी डिजाइन इतनी बेहतरीन ढंग से की गई है, कि बड़े-बड़े ट्रैक्टर भी इसके आगे फेल हो जाएं। इस ट्रैक्टर में तीन सिलेंडर होते हैं और इसमें 28 हॉर्स पॉवर की शक्ति उपस्थित होती है। सबसे विशेष बात यह है, कि इसमें सिंगल क्लिच के साथ डिस्क ब्रेक भी हैं। इतना ही नहीं इसमें कॉलर रिवर्स ट्रांसमिशन भी उपलब्ध है। इस ट्रैक्टर में 8 गियर आगे और 8 गियर पीछे के लिए होते हैं। बाजार में यह ट्रैक्टर आपको 5.65 से 6.11 लाख के मध्य आसानी से मिल जाऐंगे। यही वजह है, कि यदि आप छोटी जोत के किसान हैं, तो आपको इन ट्रैक्टरों में से किसी एक का चयन करना चाहिए।

असली हीरो की ताक़त है
आधुनिक तकनीक!

नया
3230 TX Super
45 HP
33.55 kW
4WD

NEW HOLLAND
AGRICULTURE
जान भी, शान भी!

श्रेणी में अधिकतम
उपयोगी पावर

Eptraa PTO
ऐप्ट्रा PTO और
स्वतंत्र PTO
क्लच लीवर

PLANETARY DRIVE
स्ट्रेट एक्सल
प्लेनेटरी ड्राइव

6 साल T-वारंटी
नियम व शर्तें लागू।
www.newholland.com/in
हमारी 6 साल की ट्रांसफेरेबल वारंटी भारत में बेचे जाने वाले सभी न्यू हॉलैंड ट्रैक्टरों पर लागू है। दिखाए गए उत्पादों के चित्र केवल दृष्टांत उद्देश्य के लिए हैं, इनसे उत्पाद का सटीक प्रतिनिधित्व/चुनाव नहीं हो सकता है। इनका रंग वास्तविक उत्पाद से अलग हो सकता है। *1 hp=0.7457 kW

जानें CHATGPT ने कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्त्व के बारे में क्या कहा है

आज हम आपको कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) के उपयोग के विषय में बताने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह मदद कर सकता है, इस सवाल पर CHATGPT का कहना है, कि AI कृषि के क्षेत्र में विभिन्न तरह से कार्य कर सकता है।

आज के दौर में निरंतर एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) का उपयोग बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक कार्य में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता लेने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सवाल यह है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेती में किस प्रकार से किसानों की सहायता कर सकता है। जब हमने CHATGPT जो खुद एक चैटबॉट है, उससे इस सवाल का जवाब मांगा तो उसने हमें विभिन्न रोचक बातें बताईं। जिनके बारे में जानना आपके लिए भी काफी आवश्यक है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृषि डेटा विश्लेषण कर किसानों की काफी सहायता करता है

एआई कृषि क्षेत्र से संबंधित डेटा को विश्लेषण करके फसलों की मौसम पैटर्न, मात्रा एवं विकास के संकेतों को समझ सकता है। इससे कृषकों को फसल प्रबंधन, प्रीक्टिव एनालिटिक्स, उपयुक्त खेती तकनीकों की अनुशंसा और कृषि निर्माण प्रबंधन की सलाह मिलती है।

एआई द्वारा अनुप्रयोग और संचालन विधि के विकास में मदद मिलती है

एआई खेती में किसानों को विभिन्न खेती अनुप्रयोगों और कृषि यंत्रों के लिए संचालन विधि विकसित करने में सहायता कर सकता है। यह दौर श्रम और संसाधनों की बचत करके फायदेमंद एवं स्वतंत्र खेती प्रथाओं का विकास करने में सहायता करता है।

ऑटोमेशन और रोबोटिक्स कृषि क्षेत्र में क्या सहयोग करता है

बतादें, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) खेती में ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के इस्तेमाल से किसानों की मेहनत के साथ-साथ समय की बर्बादी को रोकने में काफी मदद मिलती है। रोबोट के जरिए किसान के खेत में कई उपयोगी कार्यों को संभव किया जा सकता हैं। जैसे कि बीजारोपण, फसल के लिए पानी का वितरण, जैविक उर्वरक का छिड़काव और कीटनाशक छिड़काव।

एआई कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का निर्धारण करने में मदद करता है

एआई (AI) कृषि के अंदर उत्पादों की गुणवत्ता का निर्धारण करने में सहायता कर सकता है। इससे फसलों की गुणवत्ता एवं मात्रा को नियंत्रण में किया जा सकता है। बाजार में उनकी कीमतों को ज्यादा सुविधाजनक किया जा सकता है।

एआई कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का निर्धारण करने में मदद करता है

एआई (AI) कृषि के अंदर उत्पादों की गुणवत्ता का निर्धारण करने में सहायता कर सकता है। इससे फसलों की गुणवत्ता एवं मात्रा को नियंत्रण में किया जा सकता है। बाजार में उनकी कीमतों को ज्यादा सुविधाजनक किया जा सकता है।

एआई समस्या निवारण करने के लिए काफी मदद कर सकता है

एआई (AI) खेती में किसानों को उनकी परेशानियों का निराकरण करने के लिए सहायता कर सकता है। इससे उनको बीमारियों का प्रबंधन, जैविक उर्वरक और कीटनाशक आदि के विषय में कई सारे तरीकों की सलाह और उपाय मिलते हैं। आजकल बदलते समय के साथ-साथ आधुनिकता भी बढ़ती चली जा रही है। देश में लगभग समस्त कार्य क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होना शुरू हो गया है।

मौसमी व अन्य कृषि सुझाव

मिर्च की खेती करके किसान भाई जल्द ही कमा सकते हैं अच्छा खासा मुनाफा, इतना आएगा खर्च

भारत में मिर्च सब्जी और मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग हर घर में किया जाता है। यह स्वाद में बेहद तीखी होती है, जिसकी वजह से व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के लिए किचन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में लाल के साथ-साथ हरी मिर्च का भी बहुतायत में उत्पादन किया जाता है। भारत दुनिया में मिर्च का एक प्रमुख निर्यातक देश है। भारत के मिर्च की दुनिया भर के बाजारों में अच्छी खासी मांग रहती है।

मिर्च की खेती में इतना आता है खर्च

अगर किसान भाई एक हेक्टेयर खेत में मिर्च का उत्पादन करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए 10 किलोग्राम बीज की जरूरत होगी। देशी मिर्च के 10 किलोग्राम बीज की बाजार में कीमत 2500 रुपये प्रति किलो है। जबकि हाइब्रिड बीज की कीमत 3500 से 4000 रुपये प्रति किलो तक हो सकती है। इसके अलावा एक हेक्टेयर खेत में सिंचाई, खाद डालना, कीटनाशक डालना और कटाई में 3 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है।

इतना होगा फायदा

एक हेक्टेयर खेत में लगभग 300 क्विंटल मिर्च का उत्पादन हो सकता है। जबकि मिर्च की औसत कीमत 40 रुपये प्रति किलो होती है। इस हिसाब से एक हेक्टेयर खेत में 12 लाख रुपये की मिर्च का उत्पादन हो सकता है। अगर मिर्च की खेती में आने वाली लागत को अलग कर दें तब भी किसान भाइयों को एक हेक्टेयर खेत में मिर्च उत्पादन करने पर लगभग 9 लाख रुपये का मुनाफा हो सकता है। इस हिसाब से किसान भाई बेहद कम समय में मिर्च की खेती से ज्यादा से ज्यादा रुपये कमा सकते हैं।

ऐसी जमीन पर करें मिर्च की खेती

मिर्च की खेती हर तरह की जमीन में की जा सकती है। अच्छे उत्पादन के लिए हल्की उपजाऊ और पानी के अच्छे निकास वाली ज़मीन का चयन करना चाहिए। मिर्च की खेती के लिए जमीन का चुनाव करने के पहले मिट्टी का परीक्षण अवश्य करवाएं। इस खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए।

मिर्च की रोपाई हमेशा मिट्टी के बेड पर ही करना चाहिए। इससे पौधों के आस पास पानी जमा नहीं होता है और पौधे सड़ने से बच जाते हैं। मिर्च के पौधों को हमेशा नर्सरी में तैयार करना चाहिए। जिसके लिए उपचारित बीजों का इस्तेमाल करें। बीजों की बुवाई के 40 दिनों के बाद पौध तैयार हो जाती है। जिसे बाद में खेत में लगाया जा सकता है। पौध को खेत में लगाते समय ध्यान रखें कि पौधे स्वास्थ्य हों और उनकी ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

मिर्च की खेती में हानिकारक रोगों के साथ ही कीटों का आक्रमण होता रहता है। जिससे निपटने के लिए किसान भाई जैविक कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रोगों से निपटने के लिए मिथाइल डैमेटन, एसीफेट, प्रॉपीकोनाज़ोल या हैक्साकोनाज़ोल जैसी दवाइयों का भी उपयोग किया जा सकता है।

फसल आने पर मिर्च को हरे रूप में ही तोड़ लिया जाता है और बाजार में बेंच दिया जाता है। इसके अलावा जब मिर्च लाल हो जाती है तो उसे तोड़कर सुखा लिया जाता है और मिर्च के आकार के हिसाब से अलग कर लिया जाता है। इसके बाद सूखी मिर्च को पैक करके स्टोर कर लिया जाता है और बाजार में बेंचने के लिए भेज दिया जाता है।

मखाने की खेती करने पर यह राज्य दे रहा है फ्री में ₹72000,जल्द करें आवेदन

इन तकनीकों से उत्पादन कर किसान कमा रहे हैं मोटा मुनाफा

नमकीन हो या फिर व्रत का आहार या फिर आपको ड्राई फ्रूट से बने हुए कोई लड्डू बनाने हो, कोई भी देश मखाने के बिना अधूरी रह जाती हैं. आज हम इसी से जुड़ी हुई एक खुशखबरी आपके लिए लेकर आए हैं.

अगर आप बिहार के किसान हैं और मखाने की खेती करते हैं तो बिहार सरकार की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. बिहार सरकार ने मखाने की खेती करने वाले किसानों के लिए एक योजना बनाई है जिसका नाम मखाना विकास योजना रखा गया है. इस योजना के तहत मखाने की इकाई लगाने के लिए किसानों को लगभग 75% तक की सब्सिडी मुहैया करवाई जाएगी.

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि बिहार सरकार ने मखाना के बीच पर पर इकाई लागत लगभग 97,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तय की है और इस तय की गई राशि के ऊपर मखाना उगाने वाले किसानों को 75 फ़ीसदी सब्सिडी मिलेगी. सरल शब्दों में बात की जाए तो मखाना उगाने वाले किसानों को ₹72000 के लगभग पैसा अनुदान राशि में फ्री में दिया जाएगा. इसके अलावा किसान भाइयों के लिए एक और राय भी बिहार सरकार ने दी है कि यहां के किसान मखाना-1 एवं सवर्ण वैदेही प्रभेद का कमाल करते हुए अगर मखाने की खेती का उत्पादन करते हैं तो उनकी उत्पादकता में अच्छा-खासा इजाफा होने की संभावना है.

मखाने से बनने वाली खीर की जाती है बहुत ज्यादा पसंद

मखाने की फसल की ज्यादातर खेती भारत में बिहार राज्य में की जाती है. अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पूरे विश्व भर का लगभग 80% मखाना अकेले बिहार राज्य के किसानों द्वारा उत्पादित किया जाता है.

इसके अलावा मिथिलांचल में मखाने को जीआई टैग भी मिल चुका है जो इसकी कीमत को और बढ़ाता है. बिहार राज्य में अगर बात की जाए तो यहां के जले दरभंगा और मधुबनी में सबसे ज्यादा मखाने का उत्पादन किया जाता है. इसके अलावा अब बहुत से किसान चंपारण जिले में भी मखाने की खेती करना शुरू कर चुके हैं. बिहार सरकार की योजना है कि मखाने के उत्पादन को पूरे बिहार राज्य में हरेक हिस्से में फैलाया जा सके और किसानों को इसकी खेती करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए.

मखाने को मिल चुका है जी आई टैग

मखाना कितना ज्यादा पौष्टिक होता है इसके बारे में तो बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. यह फाइबर से भरपूर होता है और इसमें बहुत से औषधीय गुण भी पाए जाते हैं. बहुत से लोग इसे स्नेक्स की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही बहुत सी जगह पर इसकी खीर बनाई जाती है जो बहुत ही लजीज होती है.

इसके उत्पादन के आंकड़ों के बारे में आई हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार राज्य के मधुबनी और दरभंगा जिले में पूरे भारत का 70% मखाना प्रोडक्शन किया जाता है और इन दोनों ही जिलों में लगभग 120,00 टन मखाने का उत्पादन होता है. पूरे देश में लगभग 15 हजार हेक्टेयर में मखाने की फार्मिंग हो रही है. इसके अलावा पिछले साल ही मखाने को जीआई टैग दिया गया है जिसकी वजह से यह विश्व भर में प्रचलित हो गया है.

किसान परवल की खेती से कुछ महीनों में ही अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं

किसान परवल की खेती से कुछ महीनों में ही अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं

किसान भाई परवल की खेती से अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। यह दीर्घकाल तक किसानों को फायदा प्रदान कर सकती है। आलू-परवल की सब्जी अधिकांश लोगों को काफी पसंद होती है। इस वजह से हर प्रकार के कार्यक्रम में यह सब्जी आपको बड़ी आसानी से खाने के लिए मिल जाती है। हमारे भारत में इसकी कितनी लोकप्रियता है, इसके संबंध में शायद ही किसी को नहीं पता हो। यदि किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए खेत में किसी अन्य फसल को उगाने के विषय में सोच रहे हैं, तो परवल उनके लिए काफी अच्छा विकल्प हो सकता है। केवल एक एकड़ में परवल की खेती से अन्नदाता किसान वर्षभर में लाखों की आमदनी कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए अधिक लागात नहीं लगानी पड़ती है। अब हम एक एकड़ जमीन में परवल की खेती पर कितना खर्च होता है और कितना लाभ के बारे में।

खेत के एक एकड़ हिस्से में परवल के कितने पौधे लग सकते हैं

परवल की खेती भी बाकी अन्य फसलों की तरह से ही होती है। इसकी खेती के लिए सर्व प्रथम खेतों की जुताई कर ली जाती है। उसके बाद रोटावेटर से खेत को समतल रूप दिया जाता है। जिससे कि आगे चलकर सिंचाई में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। इसके उपरांत परवल के पौधे खेत में आठ फीट की दूरी पर रोप जाते हैं। इसी प्रकार एक एकड़ भूमि में तकरीबन 650 परवल के पौधे लगते हैं। साथ ही, रोपण के वक्त गोबर की खाद डालकर भूमि को अधिक उपजाऊ बनाया जाता है। जिससे कि उत्पादन अधिक हो सके। साथ ही, जून से अगस्त व अक्टूबर से नवंबर का माह इसकी रोपाई के लिए अनुकूल माना जाता है। परवल को तैयार होने में अन्य सब्जियों की भांति ही लगभग तीन महीने का वक्त लगता है। इसकी खासियत यह है, कि परवल तैयार होने के उपरांत करीब आठ-नौ माह तक पैदावार देते हैं।

परवल की खेती से किसान कितना लाभ उठा सकते हैं

पौधे, रोपाई और सिंचाई समेत सभी खर्चों का योग करें तो एक एकड़ में परवल की खेती पर तकरीबन 25 हजार रुपये की लागत आती है। साथ ही, उत्पादन तकरीबन 150-250 क्विंटल तक होता है। यदि बाजार में परवल की थोक कीमत की बात की जाए। तो यह कम से कम 3000 रुपये क्विंटल तक बिकता है। सीधी सी बात है, किसान इसको बेचकर के कुछ ही महीनों में लाखों की कमाई कर सकते हैं। बतादें, कि परवल के अंदर भी बहुत सारे गुण होते हैं। इसे खाने सेहत हमेशा अच्छी रहती है। इसमें विटामिन-बी 1, विटामिन-बी 2 और विटामिन-सी जैसे पोषक तत्व विघमान रहते हैं। जो कि बहुत सारी बीमारियों को शरीर से दूर रखने में अपनी अहम भूमिका निभाती है।

सरकारी नीतियां

सिंचाई समस्या पर राज्य सरकार का प्रहार, इस योजना के तहत 80% प्रतिशत अनुदान देगी सरकार

बिहार सरकार की तरफ से सामूहिक नलकूप योजना के अंतर्गत कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। इसका मतलब यह है, कि सामूहिक नलकूप स्थापित करने के लिए सरकार राज्य के किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है।

बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां पर कुछ जनपद बारिश की वजह से प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। इन जनपदों में ज्यादा बारिश होने से फसलें चौपट हो जाती हैं। साथ ही, कुछ जनपद ऐसे भी हैं, जहां पर जल की समस्या सदैव बनी रहती है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को सिंचाई करने के लिए ट्यबवेल की सहायता लेनी पड़ती है। परंतु, अब इन जनपदों में किसानों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार द्वारा सिंचाई की परेशानी को दूर करने के लिए सामूहिक नलकूप योजना जारी की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को अच्छा-खासा अनुदान प्रदान कर रही है।

बिहार के इन जिलों को वर्षा के समय बाढ़ का सामना करना पड़ता है

दरअसल, उत्तरी बिहार के विभिन्न जनपद प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इससे खेतों में खड़ी फसल बाढ़ के पानी के साथ बह जाती है, जिससे किसान भाइयों को करोड़ों रुपये की हानि होती है। साथ ही, दक्षिणी बिहार के गया, जहानाबाद, औरंगाबाद और नवादा समेत विभिन्न जनपदों में उत्तरी बिहार के तुलनात्मक कम बरसात होती है। इससे इन जनपदों में रबी के साथ- साथ खरीफ फसल के दौरान भी जल की समस्या बनी रहती है। ऐसी स्थिति में किसान फसलों की वक्त पर सिंचाई नहीं कर पाते हैं।

किसानों को बिहार सरकार दे रही अच्छा-खासा अनुदान

बिहार राज्य के अंदर सिंचाई के साधनों हेतु जूझ रहे कृषकों के लिए एक खुशखबरी है। बिहार सरकार की तरफ से सामूहिक नलकूप योजना के अंतर्गत किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान देने का ऐलान किया गया है। इसका अर्थ यह है, कि सामूहिक नलकूप की स्थापना करने पर किसान भाइयों को सरकार से 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में किसान भाई समूह बनाकर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।

पानी से जुड़ी समस्या पर सरकार का प्रहार

दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना को जारी किया है। सरकार का यह मानना है, कि इस विधि से सिंचाई करने पर जल की काफी बचत होगी और पौधों को भरपूर मात्रा में जल मिल सकेगा।

अब ऐसे में जो किसान भाई ड्रिप इरिगेशन एवं मिनी स्प्रिंकलर विधि द्वारा अपनी फसल की सिंचाई करना चाहते हैं, वह समूह बनाकर अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।

आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं

किसान भाई अनुदान से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह कृषि विभाग की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही, अनुदान का लाभ उठाने वाले समूह उद्यान निदेशालय की वेबसाइट HTTP://WWW.HORTICULTURE.GOV.IN पर जाकर आवेदन भी कर सकते हैं।

बिहार सरकार कोल्ड स्टोरेज खोलने पर 50% प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है

एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत राज्य में कोल्ड स्टोरेज यूनिट की स्थापना हेतु किसानों को अनुदान देने का निर्णय किया गया है। बिहार राज्य में पारंपरिक खेती समेत बागवानी फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। बिहार राज्य के किसान सेब, अंगूर, केला, अनार, आम और अमरूद की खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इससे कृषकों की आय में काफी बढ़ोत्तरी भी हुई है। परंतु, कोल्ड स्टोरेज के अभाव की वजह से किसान उतना ज्यादा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा इस परेशानी को दूर करने के लिए किसानों के फायदे हेतु बड़ा निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में बागवानी फसलों की खेती में अत्यधिक गति आएगी। साथ ही, कृषकों की आमदनी में भी इजाफा हो सकता है।

कोल्ड स्टोरेज से किसानों को काफी फायदा होगा

बिहार सरकार ऐसा मानती है, कि कोल्ड स्टोरेज होने से किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी। बाजार में कम भाव होने पर वह अपनी फसल को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही भाव में वृद्धि आएगी, वह इसको बाजार में बेच सकते हैं। इससे अच्छा भाव मिलने से किसानों की आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी। वैसे भी कोल्ड स्टोर के भीतर बहुत दिनों तक खाद्य पदार्थ बेकार नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में किसान भाई हरी सब्जियों एवं फल की तुड़ाई करने के उपरांत कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो फसलों का खराब होना भी कम हो पाएगा। साथ ही, काफी समय तक वह खराब नहीं होंगे।

बिहार सरकार किसानों को 4000 रुपये अनुदान स्वरूप प्रदान करेगी

बिहार सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी मिशन योजना के चलते कोल्ड स्टोरेज यूनिट (टाइप-1) की स्थापना करने के लिए 8000 रुपये की लागत धनराशि तय की गई है। बिहार सरकार की तरफ से इसके लिए किसान भाइयों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में कृषकों को 4000 रुपये मुफ्त में प्राप्त होंगे। जो किसान भाई इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो वह कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आम उत्पादन के मामले में बिहार कौन-से स्थान पर है

जानकारी के लिए बतादें, कि बिहार में बागवानी की खेती काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। आम के उत्पादन के मामले में बिहार पूरे भारत में चौथे स्थान पर आता है। तो उधर लीची की पैदावार के मामले में बिहार का प्रथम स्थान पर है। मुज्फ्फरपुर की शाही लीची पूरी दुनिया में मशहूर है। बतादें, कि इसके स्वाद की कोई टक्कर नहीं है। इसके उपयोग से जूस एवं महंगी- महंगी शराबें तैयार की जाती हैं।

यह राज्य सरकार किसानों से 2970 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हजारों टन ज्वार खरीदेगी

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने ज्वार की खरीद के लिए सरकारी एजेंसी मार्कफेड को आदेश भी दे दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश देने के बाद मार्कफेड ज्वार की खरीद की तैयारियों में जुट गई है।

तेलंगाना राज्य में ज्वार की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के ज्वार किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए इधर उधर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तेलंगाना सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है, कि सरकार प्रदेश के कृषकों से 2970 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ज्वार की खरीद करेगी। साथ ही, इस खबर से ज्वार की खेती करने वाले कृषकों के मध्य खुशी की लहर है। किसानों का कहना है, कि सरकार के इस फैसले से उन्हें बेहद लाभ होगा। फिलहाल, ज्वार की धनराशि से धान की खेती बेहतर ढ़ंग से कर सकेंगे। वह इन रुपयों से धान की खेती में समयानुसार खाद डाल सकेंगे।

तेलंगाना सरकार मोटे अनाज को प्रोत्साहन दे रही है

किसान तक के अनुसार, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार प्रदेश में मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहन देना चाहती है। यही कारण है, कि उसने इस प्रकार का फैसला लिया है, बिजिससे कि किसान धीरे- धीरे मोटे अनाज की खेती की तरफ बढ़ सकें। दरअसल, तेलंगाना सरकार मोटे अनाज के रकबे को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों को निःशुल्क बीज भी वितरित किए जा रहे हैं। वर्तमान में ज्वार की खरीद किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। राज्य में इस बार ज्वार की संपूर्ण उपज को सरकार द्वारा खरीदा जाएगा।

तेलंगाना सरकार राज्य के किसानों से कितने हजार टन ज्वार खरीदेगी

विशेष बात यह है, कि राज्य सरकार द्वारा ज्वार की खरीद चालू करने के लिए सरकारी एजेंसी (मार्कफेड) को आदेश भी दे दिया है। आदेश मिलते ही सरकारी एजेंसी ज्वार की खरीद की तैयारियों में जुट गई हैं। इस बार तेलंगाना सरकार की तरफ से कृषकों से 65500 टन ज्वार की खरीद करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा मार्कफेड को बैंक गारंटी दिया जाएगा। सरकार मार्कफेड को 220 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रदान करेगी। जिससे कि ज्वार की खरीद में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो सके।

किसानों ने काफी बड़े पैमाने पर ज्वार का उत्पादन किया है

तेलंगाना राज्य में किसान बड़े पैमाने पर मोटे अनाज की खेती किया करते है। इस बार राज्य में लगभग एक लाख किसानों द्वारा 51395 हेक्टेयर में ज्वार की खेती की गई है। विकराबाद, गडवल, असिफाबाद, निरमल, कामारेड्डी, अदिलाबाद और नारायणपेट जनपद में किसानों ने सबसे ज्यादा ज्वार की खेती की है। ऐसे में सरकार के इस फैसले से लगभग एक लाख किसानों को सीधा लाभ होगा। उनके खाते में 2970 रुपये प्रति क्विंटल की दर धनराशि पहुंचाई जाएगी।

सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन किस राज्य में होता है

जानकारी के लिए बतादें, कि विगत वर्ष तेलंगाना में रबी सीजन के दौरान 35,600 हेक्टेयर में ज्वार का उत्पादन किया था। परंतु, इस बार कृषकों ने मिलेट मिशन के अंतर्गत बड़े रकबे में ज्वार की बुवाई की है। रबी फसल सीजन 2021-22 में तेलंगाना के किसानों ने 48 लाख टन ज्वार की पैदावार की थी। ऐसी स्थिति में भारत में आंध्र प्रदेश के अंदर सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन किया जाता है।

इस राज्य सरकार ने किसानों का कृषि कर्ज माफ करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी

मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ कृषकों के कर्ज का ब्याज माफ करने का ऐलान किया है। फिलहाल, सरकार की तरफ से उनके कर्ज का ब्याज मुहैय्या की जाएगी। इसके लिए 2000 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसान भाइयों को बड़ी सहूलियत दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में एक प्रस्ताव को पास किया है, जिसके माध्यम से उन किसानों को लाभ प्राप्त होगा, जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ किसानों के लिए सरकार द्वारा 2,123 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसकी वजह से 11.9 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा। साथ ही, सरकार के स्तर से उनके कर्ज का ब्याज माफ कर दिया जाएगा। किसानों के कर्ज का ब्याज माफ करने का निर्णय कैबिनेट ने एक बैठक के चलते लिया है।

इतने लाख से नीचे के कर्ज वाले किसानों को मिलेगा फायदा

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस निर्णय पर एक अधिकारी ने कहा है, कि जिन किसानों का कर्ज और ब्याज जॉइंट रुप से दो लाख रुपये से नीचे है, उन्हें इस योजना में शम्मिलित किया जाएगा। बतादें, कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत वर्ष ऐलान किया था, कि राज्य सरकार उन किसानों के कृषि कर्ज पर जारी ब्याज बैंकों में जमा करेगी। जिन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार के वादे की वजह से अपना कर्जा नहीं चुकाया था।

2,123 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है

अधिकारी ने जानकारी दी, है कि कैबिनेट द्वारा सहकारी बैंकों और समितियों से लिए गए कर्ज पर किसानों के लिए ब्याज का भुगतान करने हेतु 2,123 करोड़ रुपये की धनराशि के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। सरकार के इस निर्णय के उपरांत से अब कृषकों को ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने पूर्व में आरोप लगाया था, कि विगत कांग्रेस सरकार की तरफ से कर्ज माफी के वादे की वजह से कई किसान कृषि कर्ज नहीं चुका पाए थे। उन्होंने कांग्रेस पर कर्ज माफ करने के वादे को पूर्ण नहीं करने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से किसानों ने कर्ज नहीं चुकाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है, कि उनकी सरकार के समय प्रदेश के करीब 24 लाख किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ प्राप्त हुआ था।

मधुमक्खी पालन के लिए दी जा रही है 75% तक सब्सिडी, जाने किसान कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ

आजकल देश भर में किसान खेती के साथ-साथ कोई ना कोई वैकल्पिक इनकम सोर्स भी रखते हैं ताकि उन्हें खेती के साथ-साथ कुछ अलग से मुनाफा भी होता रहे। ऐसा ही एक बिजनेस जिसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है वह है मधुमक्खी पालन। बहुत ही राज्य सरकारें किसानों को मधुमक्खी पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और इनमें ही एक और सरकार जो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन कदम उठा रही है वह है बिहार सरकार.

मधुमक्खी पालन के लिए बिहार सरकार दे रही है सब्सिडी

अगर सब्सिडी की बात की जाए तो बिहार सरकार मधुमक्खी पालन के लिए अच्छी खासी सब्सिडी किसानों को दे रही है. अगर किसी किसान का रुझान मधुमक्खी पालन की तरह है और वह इसे एक व्यवसाय के तौर पर लेना चाहता है तो बिहार सरकार की तरफ से उसे 75% तक सब्सिडी दी जाएगी. बिहार सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए एक परियोजना शुरू की है, जिसे 'बिहार मधुमक्खी विकास नीति' के नाम से जाना जाता है। इस नीति के अंतर्गत, सरकार किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए विभिन्न उपकरणों, जैसे कि मधुमक्खी बक्से, जहाज, रासायनिक उपकरण आदि की आपूर्ति करती है।उदाहरण के लिए अगर आपको यह व्यवसाय शुरू करने में ₹100000 का खर्चा पढ़ रहा था तो इसमें से ₹75000 आपको बिहार सरकार द्वारा दिए जाएंगे.

क्या है आवेदन करने का तरीका?

आप इस परियोजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. एक तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन दे सकते हैं जहां पर आवेदन कर्ता को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत है. अगर आप यह आवेदन ऑनलाइन नहीं देना चाहते हैं तो आप उद्यान विभाग में जाकर भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं. यहां पर भी आपको मांगे गए सभी दस्तावेज दिखाने की जरूरत है.

केंद्र सरकार कैसे कर रही है मदद?

राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे किसानों को काफी लाभ मिलने वाला है. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन द्वारा शहद की क्वालिटी को चेक करने के लिए प्रशिक्षण प्रयोगशाला और क्षेत्रीय प्रयोगशाला बनाने की परमिशन दी गई है. इस योजना के तहत 31 मिनी प्रशिक्षण प्रयोग चलाएं और चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को बनाने की परमिशन के लिए सरकार द्वारा दे दी गई है. इसके अलावा जो भी शहर पालन का व्यवसाय की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन कृषि उद्यमियों या सभी तरह की स्टार्टअप की भी सरकार के द्वारा मदद की जाएगी.

भारत में क्या है शहद प्रोडक्शन के आंकड़े

अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत देश को शहद के उत्पादन का एक हग माना गया है और यहां पर सालाना कई लाख टर्न शहद का प्रोडक्शन हो रहा है. वर्ष 2021-22 के आंकड़ों को ही देखें तो देश में इस समय 1,33,000 मीट्रिक टन (एमटी) शहद का उत्पादन हो रहा है. इसके अलावा भारत में उत्पादित किया हुआ शहद विश्व के कई देशों में भी निर्यात किया जाता है.

11.9 लाख किसानों का कर्ज माफ कर रही है शिवराज चौहान सरकार, बनाई गई है लिस्ट

इअगर आप मध्य प्रदेश के किसान है तो आपके लिए शिवराज चौहान सरकार एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. मध्यप्रदेश में शिवराज चौहान सरकार ने राज्य के कुल 11.9 लाख किसानों का कर्ज माफ करने की योजना तैयार की है.

किसानों को इस योजना के बारे में एक बात जानना जरूरी है कि इसके लिए एक लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में उन्हीं किसानों को रखा गया है जिनका मूल और ब्याज मिलाकर कुल बकाया रुपए केवल ₹200000 बचा है. अगर आप डिफाल्टर किसानों की लिस्ट में आते हैं तो इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा और उसके बाद जांच करने के बाद ही आप का कर्ज पूरी तरह से माफ किया जाएगा

2,123 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के लिए दी गई है मंजूर

मध्यप्रदेश राज्य में बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने कई साल पहले कर दिया था और किसी कारण वश में है यह कर्ज नहीं चुका पाए थे. सरकार ने पूरी तरह से जांच करते हुए ऐसे किसानों की एक लिस्ट तैयार की है और इसमें ऐसे किसानों को शामिल किया गया है जिन का बकाया राशि ₹200000 तक का है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इसके लिए लगभग 2123 करोड रुपए का प्रस्ताव मंजूर किया गया है जिससे लाखों किसान फायदा उठाने वाले हैं. मंत्रिमंडल बैठक में फैसला ले लिया है और बुधवार को ही है प्रस्ताव सामने रखा गया है.

किसानों को है इसके लिए आवेदन करने की जरूरत

अगर किसान इस लिस्ट में आना चाहते हैं तो कर्ज माफी के लिए उन्हें एक आवेदन देना होगा जिसकी सरकार के द्वारा जांच की जाएगी और उसके बाद यह निर्धारित किया जाएगा कि उनका कर्ज माफी किया जाएगा या नहीं.यह आवेदन ऑनलाइन किसानों से मांगे गए हैं. पहले कांग्रेस सरकार ने भी किसानों के लोन माफी की घोषणा की थी जिसके बाद बहुत से किसानों ने लोन की राशि जमा ही नहीं की थी लेकिन उसके बाद ही सरकार बदल गई और किसानों पर यह लोन माफी की योजना को रोक दिया गया और तब से किसान उस कर्ज के तले दबे हुए हैं.माना जा रहा है कि इस योजना से किसानों को लाभ मिलेगा.

इस राज्य के किसानों को मिलेगा सोलर पंप पर अब 75 प्रतिशत अनुदान

जैसा कि हम सब जानते हैं, कि पीएम कुसुम योजना केंद्र सरकार की बेहतरीन योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना है। फिलहाल, इसके अंतर्गत किसान भाइयों को 75 प्रतिशत अनुदान मुहैय्या कराया जा रहा है। इसकी मदद से किसान भाइयों को बेहद सस्ती दरों पर अपने खेतों में सोलर पंप लगवाने में सहायता मिलेगी।

खेती-किसानी के लिए जितना आवश्यक मृदा का उपयुक्त होना है। उतना ही बेहतर बीजों का होना भी रहता है। इनके न होने पर फसल पर काफी बुरा असर पड़ता है। साथ ही, जल रहित कृषि की कल्पना करना भी मुश्किल होता है। खरीफ सीजन की फसलें सामान्यतः जल के अभाव का सामना करती हैं। धान और गन्ना की फसलों को अधिकांश जल की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की सहायता के लिए खड़ी होती हैं। किसानों को सिंचाई के लिए विभिन्न संसाधन मुहैय्या कराए जाते हैं। किसानों का सिंचाई पर ज्यादा खर्चा ना हो पाए, इसके संबंध में एक राज्य सरकार बड़ी सहूलियत दे रही है।

हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को सिंचाई के लिए 75 % अनुदान

हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के हित में सिंचाई पर अनुदान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के स्तर से देश के तमाम राज्यों के कृषकों की सहायता कर रही है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं सुरक्षा उत्थान महाभियान के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार किसानों को 75 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है।

पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 60 प्रतिशत तक अनुदान

केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत कृषकों को 60 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत किसानों को अपने खेतों पर सोलर पंप लगवाने के खर्चे का 30 प्रतिशत तक कर्ज प्रदान करती है। कृषकों को सोलर प्लांट लगाने सिर्फ 10 प्रतिशत तक खर्चा करनी पड़ेगी।

75 प्रतिशत सब्सिडी किस पर मिलेगी

हरियाणा सरकार ने पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी सहूलियत प्रदान की है। एक से 10 हॉर्स पॉवर बिजली आधारित कृषि ट्यबवेल आवेदकों को 75 प्रतिशत तक अनुदानित दर पर सौर पंप उपलब्ध कराया जाएगा।

आवेदन की आखरी तिथि 15 मई तक है

पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया चालू हो गई है। 28 अप्रैल से पोर्टल पर आवेदन चालू कर दिया है। किसान भाई आवेदन की आखरी तिथि तक 15 मई तक ही कर सकते हैं। आवेदन में लगभग एक सप्ताह का वक्त रह गया है। पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदक आधिकारिक वेबसाइट PMKUSUM.HAREDA.GOV.IN पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इस राज्य में किसानों को निःशुल्क पौधे, 50 हजार रुपये की अनुदानित राशि भी प्रदान की जाएगी

बिहार सरकार बागवानी को प्रोत्साहन दे रही है। कृषकों को बागवानी क्षेत्र से जोड़ने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। उनको शर्तों के मुताबिक फ्री पौधे, आर्थिक तौर पर सहायता भी की जा रही है।

भारत के कृषक अधिकांश बागवानी पर आश्रित रहते हैं। बतादें कि देश के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार सहित समस्त राज्यों में बागवानी की जाती है। किसान लाखों रुपए की आमदनी कर लेते हैं। साथ ही, राज्य सरकारों के स्तर पर कृषकों को काफी सहायता दी जाती है। इसी कड़ी में बिहार सरकार की तरफ से एक अहम कवायद की गई है। राज्य सरकार से कृषकों को बागवानी हेतु नि:शुल्क पौधे मुहैय्या किए जाऐंगे। साथ ही, उनको मोटा अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार की इस योजना से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं।

इस प्रकार किसानों को निःशुल्क पौधे दिए जाऐंगे

बिहार सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, नालंदा जनपद में निजी जमीन पर 15 हेक्टेयर में आम का बगीचा लगाता है, तो उसको निःशुल्क पौधे दिए जाएंगे। सघन बागवानी मिशन के अंतर्गत 10 हेक्टेयर जमीन में आम का बगीचा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक किसान 8 कट्ठा साथ ही ज्यादा से ज्यादा एक हेक्टेयर में पौधे लगा सकते हैं। 5 हेक्टेयर में अमरूद और 5 हेक्टेयर में केला और बाग लगाने वाले किसानों को भी सब्सिड़ी प्रदान की जाएगी।

योजना का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगा

किसान भाई इसका फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इसमें पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर चुनाव होगा। मतलब योजना के अंतर्गत जो पहले आवेदन करेगा। उसे ही योजना का फायदा मिल सकेगा। द्यान विभाग के पोर्टल (HORTICULTURE.BIHAR.GOV.IN) पर ऑनलाइन आवेदन कर आप योजना का फायदा उठा सकते हैं।

धनराशि इस प्रकार से खर्च की जाएगी

बिहार सरकार के मुताबिक, 50 फीसद अनुदान के उपरांत प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये के प्रोजेक्ट पर तीन किस्तों में धनराशि व्यय की जानी है। प्रथम वर्ष में 60 प्रतिशत तक धनराशि प्रदान की जाएगी। जो कि 30,000 रुपये तक होगी। एक हेक्टेयर में लगाए जाने वाले 400 पौधों का मूल्य 29,000 रुपये होगा। शेष धनराशि कृषकों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। द्वितीय वर्ष में 10 हजार, तीसरे वर्ष में भी 10 हजार रुपये का ही अनुदान मिलेगा। हालांकि, इस दौरान पौधों का ठीक रहना काफी जरूरी है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंतर्गत 5 हेक्टेयर में आम का बाग लगाया जाना है। प्रति हेक्टेयर 100 पौधों पर 18 हजार रुपये खर्च किए जाऐंगे। आम की किस्मों में मल्लिका, बंबइया, मालदाह, गुलाब खास, आम्रपाली शम्मिलित हैं।

फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिल रहा 40% प्रतिशत अनुदान

फ्लोरीकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपने अपने स्तर से कवायद कर रही हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसा ही कदम उठाया गया है। राजस्थान में किसानों को खेती करने पर 40 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त होगा।

फूलों का इस्तेमाल कार्यालय, घर के साथ बाकी जगहों पर होने वाले कार्यक्रमों में किया जाता है। किसान इससे अच्छी आमदनी कर लेते हैं। एक-एक फूल बाजार में 10 रुपये तक बेचा जाता है। कभी-कभी तो इनकी कीमत 500 रुपये प्रति फूल अथवा ज्यादा भी हो जाती है। भारतीय किसान फल, सब्जी के अतिरिक्त फूलों की खेती से भी मोटी आमदनी कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार फूलों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार की तरफ से हाल ही में फ्लोरीकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। इसका प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक फायदा किसानों को मिल सकता है।

राजस्थान सरकार फूलों की खेती पर अनुदान प्रदान कर रही है

राजस्थान में फूलों की खेती को बढ़ावा देने की कवायद की जा रही है। राजस्थान में फूलों की खेती करने वाले कृषकों को अनुदान दिया जाएगा। 2 हेक्टेयर क्षेत्र में लूज फ्लावर मतलब गुलदाउदी, गैलार्डिया, देसी गुलाब, गेंदा की खेती करने के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को कुल लागत पर 40 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। जो कि अधिकतम 16 हजार रुपये तक होगी। साथ ही, प्रति हेक्टेयर 40 हजार रुपये तक की लागत आने का अंदाजा है। साथ ही, अन्य कृषकों को 25 प्रतिशत, अधिकतम 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

यह जरुरी दस्तावेज होने बेहद आवश्यक हैं

फूलों की बागवानी करने हेतु कृषकों के समीप कुछ आवश्यक दस्तावेज होने आवश्यक हैं। इसमें आधार कार्ड की प्रति, जमाबंदी की कॉपी, किसान का शपथपत्र, जन आधार अथवा भामाशाह कार्ड की कॉपी होनी चाहिए।

राजस्थान के किन जनपदों में यह योजना चल रही है

फूलों के बगीचों के लिए अनुदान योजना विभिन्न जनपदों में जारी की गई है। इनके अंतर्गत डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुंनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, बारां, करौली, अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बाडमेर, भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ शम्मिलित हैं।

किसान बगीचों पर बोर्ड जरूर लगाएं

अगर कोई कृषक संपर्क करता है, तो ऐसे किसान को गोबर से निर्मित खाद 1.00 रुपये प्रति किलोग्राम एवं वर्मीकंपोस्ट 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपलब्ध करवाया जाएगा। फूलों के बगीचे पर अपना विस्तृत विवरण भी भरना होगा। इसके लिए किसान को बगीचे पर एक बोर्ड लगवाना होगा। उस बोर्ड पर किसान का नाम, पता, फूलों की किस्म का नाम, किस वर्ष में बगीचा लगा, कुल क्षेत्रफल और अनुदान का विवरण भी स्पष्ट करना होगा।

खुशखबरी: इस राज्य में एक लाख तक के कृषि लोन पर किसी भी प्रकार की ब्याज नहीं देनी पड़ेगी

ओडिशा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब ओड़िशा के कृषकों को एक लाख रुपये तक के कृषि कर्ज पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। प्रदेश में 35 लाख किसान कृषि लोन का फायदा उठा रहे हैं। इनमें से लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या तकरीबन 30 लाख है।

ओडिशा के किसानों के लिए यह एक बड़ी राहत भरी खबर है। बतादें कि ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कृषि लोन पर 441.76 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान वितरित किया है। नतीजतन, राज्य के 35 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। विशेष बात यह है, कि साल 2022-23 के लिए कृषि ब्याज सबवेंशन के दूसरे फेज में यह अनुदान धनराशि वितरित की गई है। साथ ही, राज्य सरकार के इस फैसले से किसानों के बीच खुशी की लहर है।

ओड़िशा के 35 लाख किसान कृषि लोन का फायदा उठा सकेंगे

ओडिशा बाइट्स की खबरों के अनुसार, राज्य में किसानों को एक लाख रुपये तक के कृषि कर्ज पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना होगा। प्रदेश में 35 लाख किसान कृषि लोन का फायदा उठाएंगे। इनमें से लघु और सीमांत किसानों की संख्या 30 लाख है। राज्य की समस्त सहकारी बैंकों से किसान कृषि लोन प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को ब्याज पर काफी सहूलियत भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि किसान भाई चाहें, तो 2409 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से भी सस्ती ब्याज पर कृषि कर्ज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज तक सरकार द्वारा समकुल 856.99 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान के तौर पर खर्च किए हैं।

कालिया शिक्षा छात्रवृत्ति से गरीब परिवारों का उत्थान होगा

इस संदर्भ में किसान भाइयों का कहना है, कि ब्याज पर अनुदान प्रदान करना मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार का एक काफी सराहनीय कदम है। इससे किसान भाइयों को काफी लाभ हुआ है। साथ ही, सरकार की इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को काफी बल मिला है। विशेष कर महिलाओं को स्वावलंबी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अनुदान धनराशि वितरित करने के उपरांत कहा है, कि कृषकों को मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार ने अलग से बजट तैयार किया है। इसके अंतर्गत किसानों को एक लाख रुपये तक कृषि लोन लेने पर किसी भी प्रकार की कोई ब्याज नहीं देनी होगी। साथ ही, खेती करने वाले परिवारों के कल्याण के लिए कालिया शिक्षा छात्रवृत्ति जारी की जा रही है।

एकमात्र सहकारी क्षेत्रों की तरफ से 60 प्रतिशत कृषि लोन दिया जाएगा

मुख्यमंत्री की मानें तो कालिया शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से गरीब किसान परिवारों को बेहद लाभ मिला है। उनका कहना है, कि हमारी सरकार की तरफ से चलाई गई विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की वजह से प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को और भी ज्यादा शक्ति अर्जित हुई है। यही कारण है, कि आज 60% प्रतिशत कृषि लोन एकमात्र सहकारी क्षेत्रों के माध्यम से दिया जा रहा है। बतादें, कि ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य है। यहां धान की खेती के

साथ-साथ किसान बड़े पैमाने पर सब्जी और बागवानी की खेती भी किया करते हैं। ऐसे में ब्याज पर अनुदान मिलने से इन किसानों को बेहद फायदा होगा।

BRAJDHAM

FARMS & RESORT

Best place to Celebrate Your Day

www.brajdhamfarms.com

इस राज्य में किसानों को फसल मुआवजा देने 6 जनपदों के लिए 92 करोड़ आवंटित किए गए हैं

बिहार राज्य में मार्च माह के समय हुई बारिश से तकरीबन 54,000 हेक्टेयर में खड़ी फसलों को काफी हानि पहुंची है। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण सहित छह जनपदों में फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं।

बिहार के किसानों के लिए अच्छा समाचार है। पंजाब-हरियाणा की भांति उन्हें भी फसल नुकसान का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। बस इसके लिए उनको सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर क्लेम करना होगा। फसल सहायता योजना के अंतर्गत किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। साथ ही, इस खबर से किसानों के मध्य खुशी की लहर है। किसानों ने सरकार के इस कदम की खूब सराहना की है।

हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार, बिहार के सहकारिता विभाग ने बताया है, कि मार्च महीने में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी फसलों को सर्वाधिक हानि पहुंची है। इसके बदले में किसानों को मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। बस इसके लिए किसानों को क्लेम करना पड़ेगा। सहकारिता विभाग ने क्लेम करने के लिए वेबसाइट पर विंडो खोल दी है। किसानों को 2500 रुपये से लेकर 22500 रुपये तक प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता धनराशि मिल सकती है।

बिहार सरकार ने राज्य स्तर से फसल बीमा योजना का आरंभ किया है

दरअसल, बिहार सरकार की तरफ से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया गया। इस संदर्भ में नीतीश सरकार का कहना है, कि पीएम फसल बीमा योजना की कवरेज प्रीमियम काफी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में समस्त किसान इसका भुगतान करने में असमर्थ हैं।

यही वजह है, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने साल 2018 में अपनी फसल बीमा योजना जारी की थी। इस योजना की विशेषता यह है, कि इसके लिए किसान भाइयों को किसी तरह का प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। बस किसानों को पंजीकरण करवाना होता है।

किसानों को 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी

बतादें, कि मार्च माह में हुई बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि से रबी फसलों के सहित सब्जी या बागवानी फसलों को भी काफी मोटी हानि पहुंची थी। इससे किसान भाइयों को काफी आर्थिक हानि पहुँची है। यही वजह है, कि सरकार को फसल क्षति हेतु मुआवजे की घोषणा करनी पड़ी। सहकारिता विभाग के एक अधिकारी ने बताया है, कि इस बीमा नीति के अंतर्गत किसी भी कारण से फसल क्षतिग्रस्त होने पर किसानों को 20,000 रुपये तक की मौद्रिक मदद प्रदान की जाती है।

किसानों की बारिश से हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसल चौपट

अधिकारियों के अनुसार, इस बार मार्च माह के समय हुई बारिश से तकरीबन 54,000 हेक्टेयर में खड़ी फसलों को काफी हानि पहुंची है। इसमें सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जनपदों के अंतर्गत रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण समेत छह जनपदों में फसलों को काफी हानि पहुंची

है। यही वजह है, कि इन 6 जनपदों के किसानों को मुआवजा प्रदान करने के लिए 92 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन जनपदों से तकरीबन 1.15 लाख किसानों ने फसल मुआवजे के लिए क्लेम किया है, जिसका फिलहाल मूल्यांकन किया जा रहा है। साथ ही, समाचार सामने आया है, कि कृषि विभाग अगले माह तक किसानों के खाते में मुआवजे की धनराशि हस्तांतरित कर सकती है।

राज्य सरकार की तरफ से कृषकों को प्रति एकड़ 22,500 रुपये का मुआवजा मिलेगा

बिहार राज्य में प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल क्षतिग्रस्त होने पर कृषकों को प्रति एकड़ 22,500 रुपये मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही, सिंचित जमीन पर फसल की हानि के लिए 17,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार असिंचित जमीन के लिए यह आंकड़ा 8,500 रुपये प्रति एकड़ है। विशेष बात यह है, कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा 2 एकड़ भूमि के लिए मुआवजा मिलता है। वहीं, कृषि विभाग ने सिंचित, गैर-सिंचित एवं बहुफसली खेतों के लिए न्यूनतम मुआवजा धनराशि क्रमशः 1,000 रुपये, 2,000 रुपये व 2,500 रुपये तय की गई है।

इस राज्य में हिम ऊर्जा सोलर पॉवर यूनिट लगवाने पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा

हिमाचल प्रदेश में हिम ऊर्जा का 250 से 5 मेघावाट का भूमि पर पॉवर प्लांट स्थापित करने का प्रोजेक्ट चालू किया गया है, जिसके अंतर्गत 250 से 1 मेघावाट के प्रोजेक्ट के लिए कोई भी हिमाचली युवा इस प्रोजेक्ट को लगवा सकता है। साथ ही, सरकार को बिजली बेच कर बेहतरीन आमदनी कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश सोलर ऊर्जा के मामले में अग्रणी राज्यों में से एक है। साथ ही, सरकार की तरफ से इसके विकास और उन्नति हेतु बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। जिनके अंतर्गत हिम ऊर्जा के 250 मेगावाट से 5 मेघावाट के प्रोजेक्ट के जरिए जहां एक ओर बिजली की परेशानियां दूर की जा सकती हैं। दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं के लिए एक रोजगार का उत्तम विकल्प भी है। यहां हिम ऊर्जा के सोलर पॉवर प्रोजेक्ट की संपूर्ण जानकारी है।

हिम ऊर्जा के रूफ टॉप पावर प्लांट स्थापना हेतु मिलेगा 40% प्रतिशत अनुदान

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक विशेष योजना जारी की गई है। इस योजना का नाम "सौर उत्पादक एवं अधिगम परियोजना" है। इस योजना के अंतर्गत, निजी एवं सरकारी संस्थानों की छत पर सोलर प्लांट स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के चलते सरकारी संस्थानों को 70% प्रतिशत तो वहीं निजी संस्थानों को 30% फीसद अनुदान मुहैय्या किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत पर 1 से 3 किलोवाट का पॉवर प्लांट स्थापित कर सकता है। इसके लिए हिमाचल सरकार भी 40% प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान करती है। इसके साथ ही, योजना के तहत स्थापित सोलर प्लांट की ऊर्जा उत्पादन भी उस संस्था हेतु निःशुल्क होती है, जिसमें वह लगवाई गई है।

इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है, कि हिमाचल प्रदेश के संस्थानों के तरफ से उत्पन्न विघुत खर्च कम किया जा सके। वह स्वतंत्र ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ती की सकें। यह योजना हिमाचल प्रदेश के लिए एक काफी बड़ी पहल है, जो कि स्वतंत्रता से विघुत उत्पादन करने में सहायक भूमिका निभाएगा।

किसान भाई अपनी भूमि पर सोलर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर अच्छी आय कर सकते हैं

जानकारी के लिए बतादें, कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हिम ऊर्जा का 250 से 5 मेघावाट का भूमि पर पॉवर प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट चालू किया गया है। इसके अंतर्गत 250 से 1 मेघावाट के प्रोजेक्ट हेतु कोई भी हिमाचली युवा इस प्रोजेक्ट को स्थापित कर सकते हैं। साथ ही, सरकार भी बिजली बेचकर काफी बेहतरीन आमदनी कर सकती है। इसके अतिरिक्त गैर हिमाचली भी 1 से 5 मेघावाट तक का हिम ऊर्जा का प्रोजेक्ट स्थापित कर सकते हैं। लेकिन, ध्यान रहे कि हिमाचल प्रदेश में उसकी स्वयं की भूमि हो अथवा लीज पर ली गई हो। इस प्रोजेक्ट में 1 मेघावाट तक का पॉवर प्लांट स्थापित करवाने हेतु न्यूनतम 1 करोड़ रुपये के खर्चे की आवश्यकता होगी।

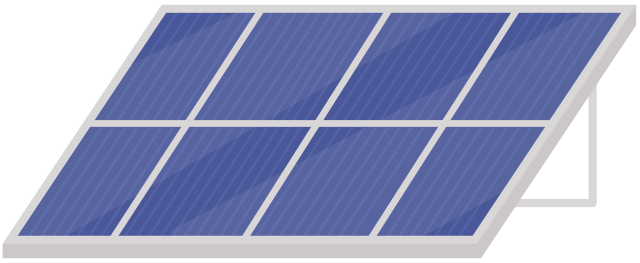

हिमाचल प्रदेश में समकुल कितने हिम ऊर्जा के प्रोजेक्ट हैं

हिमाचल प्रदेश में समकुल 330 MW का सोलर पॉवर प्रोजेक्ट चालू किया गया है। इनमें से 10 MW की लगवाने हेतु सोलन जनपद में, 100 MW का स्थापित करने ऊना जनपद में वहीं 210 MW की स्थापना कांगड़ा जनपद में की गई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने अनुमति पत्र वापस लेने के उपरांत कुछ प्रोजेक्ट हेतु अधिकृत ठहराया है। बाकी प्रोजेक्ट भी चालू होने वाले हैं।

हिमाचल प्रदेश में सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट से होंगे काफी फायदे

सोलर पॉवर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए काफी सहायक भूमिका निभा रहा है। इससे यहां की जनता के साथ सरकार को भी काफी फायदा पहुंच रहा है। जानकारी के लिए बतादें कि इससे रोजगार के विकल्प भी उत्पन्न हो रहे हैं। साथ ही, विघुत आपूर्ति में भी इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से राज्य में निवेश भी काफी बढ़ रहा है। सोलर ऊर्जा के माध्यम से सड़कों एवं गलियों में विघुत तारों के जाल से निजात मिलती है। साथ ही, सबसे प्रमुख और विशेष बात यह है, कि सोलर ऊर्जा के माध्यम से जल और जलवायु संरक्षण में सहायता मिलती है। साथ ही, लोगों की जीवन शैली में भी काफी हद तक सुधार होता है।

सोलर पॉवर प्रोजेक्ट पर लगभग कितना खर्च हो सकता है

बतादें, कि सोलर पॉवर प्रोजेक्ट हेतु समकुल निवेश की गणना करना काफी मुश्किल है। हालाँकि, जानकारी साझा करते हुए हिमाचल प्रदेश हिमऊर्जा के प्रोजेक्ट मैनेजर विनीत सूद ने कहा है, कि प्रोजक्ट पर आने वाला खर्चा उसके आकार पर निर्भर करता है। यानी कि प्रोजेक्ट का आकार जितना होगा और इसकी जितनी क्षमता होगी उतना ही लागत पर खर्चा आयेगा। उन्होंने कहा है, कि 1 MW सोलर पॉवर प्रोजेक्ट के लिए समकुल निवेश तकरीबन 1 करोड़ रुपये तक हो सकता है। इस आधार पर यदि MW के आकार में इजाफा होता है, तो लागत में भी इजाफा हो जाता है।

मोटे अनाज (मिलेट) की फसलों का महत्व, भविष्य और उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी

भारत के किसान भाइयों के लिए मिलेट की फसलें आने वाले समय में अच्छी उपज पाने हेतु अच्छा विकल्प साबित हो सकती हैं। आगे इस लेख में हम आपको मिलेट्स की फसलों के बारे में अच्छी तरह जानकारी देने वाले हैं।

मिलेट फसलें यानी कि बाजरा वर्गीय फसलें जिनको अधिकांश किसान मिलेट अनाज वाली फसलों के रूप में जानते हैं। मिलेट अनाज वाली फसलों का अर्थ है, कि इन फसलों को पैदा करने एवं उत्पादन लेने के लिए हम सब किसान भाइयों को काफी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। समस्त मिलेट फसलों का उत्पादन बड़ी ही आसानी से लिया जा सकता है। जैसे कि हम सब किसान जानते हैं, कि सभी मिलेट फसलों को उपजाऊ भूमि अथवा बंजर भूमि में भी पैदा कर आसान ढ़ंग से पैदावार ली जा सकती है। मिलेट फसलों की पैदावार के लिए पानी की जरुरत होती है। उर्वरक का इस्तेमाल मिलेट फसलों में ना के समान होता है, जिससे किसान भाइयों को ज्यादा खर्च से सहूलियत मिलती है।

जैसा कि हम सब जानते हैं, कि हरित क्रांति से पूर्व हमारे भारत में उत्पादित होने वाले खाद्यान्न में मिलेट फसलों की प्रमुख भूमिका थी। लेकिन, हरित क्रांति के पश्चात इनकी जगह धीरे-धीरे गेहूं और धान ने लेली और मिलेट फसलें जो कि हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसल हुआ करती थीं, वह हमारी भोजन की थाली से दूर हो चुकी हैं।

भारत मिलेट यानी मोटे अनाज की फसलों की पैदावार में विश्व में अव्वल स्थान पर है

हमारा भारत देश आज भी मिलेट फसलों की पैदावार के मामले में विश्व में सबसे आगे है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसान भाई बड़े पैमाने पर मोटे अनाज यानी मिलेट की खेती करते हैं। बतादें, कि असम और बिहार में सर्वाधिक मोटे अनाज की खपत है। दानों के आकार के मुताबिक, मिलेट फसलों को मुख्यतः दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। प्रथम वर्गीकरण में मुख्य मोटे अनाज जैसे बाजरा और ज्वार आते हैं। तो उधर दूसरे वर्गीकरण में छोटे दाने वाले मिलेट अनाज जैसे रागी, सावा, कोदो, चीना, कुटुकी और कुकुम शम्मिलित हैं। इन छोटे दाने वाले, मिलेट अनाजों को आमतौर पर कदन्न अनाज भी कहा जाता है।

वर्ष 2023 को "अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है

जैसा कि हम सब जानते है, कि वर्ष 2023 को "अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है। भारत की ही पहल के अनुरूप पर यूएनओ ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। भारत सरकार ने मिलेट फसलों की खासियत और महत्ता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018 को "राष्ट्रीय मिलेट वर्ष" के रूप में मनाया है। भारत सरकार ने 16 नवम्बर को "राष्ट्रीय बाजरा दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

मिलेट फसलों को केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर से बढ़ावा देने की कोशिशें कर रही हैं

भारत सरकार द्वारा मिलेट फसलों की महत्ता को केंद्र में रखते हुए किसान भाइयों को मिलेट की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मिलेट फसलों के समुचित भाव के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया जा रहा है। जिससे कि कृषकों को इसका अच्छा फायदा मिल सके। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के स्तर से मिलेट फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन में बढ़ोत्तरी हेतु विभिन्न सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिससे किसान भाई बड़ी आसानी से पैदावार का फायदा उठा सकें। सरकारों द्वारा मिलेट फसलों के पोषण और शरीरिक लाभों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण एवं शहरी लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। जलवायु परिवर्तन ने भी भारत में गेहूं और धान की पैदावार को बेहद दुष्प्रभावित किया है। इस वजह से सरकार द्वारा मोटे अनाज की ओर ध्यान केन्द्रित करवाने की कोशिशें की जा रही हैं।

मिलेट यानी मोटे अनाज की फसलों में पोषक तत्व प्रचूर मात्रा में विघमान रहते हैं

मिलेट फसलें पोषक तत्वों के लिहाज से पारंपरिक खाद्यान गेहूं और चावल से ज्यादा उन्नत हैं। मिलेट फसलों में पोषक तत्त्वों की भरपूर मात्रा होने की वजह इन्हें "पोषक अनाज" भी कहा जाता है। इनमें काफी बड़ी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन-E विघमान रहता है। कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन कैल्शियम, मैग्नीशियम भी समुचित मात्रा में पाया जाता है। मिलेट फसलों के बीज में फैटो नुत्रिएन्ट पाया जाता है। जिसमें फीटल अम्ल होता है, जो कोलेस्ट्राल को कम रखने में सहायक साबित होता है। इन अनाजों का निमयित इस्तेमाल करने वालों में अल्सर, कोलेस्ट्राल, कब्ज, हृदय रोग और कर्क रोग जैसी रोगिक समस्याओं को कम पाया गया है।

मिलेट यानी मोटे अनाज की कुछ अहम फसलें

ज्वार की फसल

ज्वार की खेती भारत में प्राचीन काल से की जाती रही है। भारत में ज्वार की खेती मोटे दाने वाली अनाज फसल और हरे चारे दोनों के तौर पर की जाती है। ज्वार की खेती सामान्य वर्षा वाले इलाकों में बिना सिंचाई के हो रही है। इसके लिए उपजाऊ जलोढ़ एवं चिकिनी मिट्टी काफी उपयुक्त रहती है। ज्वार की फसल भारत में अधिकांश खरीफ ऋतु में बोई जाती है। जिसकी प्रगति के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ठीक होता है। ज्वार की फसल विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। ज्वार की फसल बुआई के उपरांत 90 से 120 दिन के समयांतराल में पककर कटाई हेतु तैयार हो जाती है। ज्वार की फसल से 10 से 20 क्विंटल दाने एवं 100 से 150 क्विंटल हरा चारा प्रति एकड़ की उपज है। ज्वार में पोटैशियम, फास्पोरस, आयरन, जिंक और सोडियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ज्वार का इस्तेमाल विशेष रूप से उपमा, इडली, दलिया और डोसा आदि में किया जाता है।

बाजरा की फसल

बाजरा मोटे अनाज की प्रमुख एवं फायदेमंद फसल है। क्योंकि, यह विपरीत स्थितियों में एवं सीमित वर्षा वाले इलाकों में एवं बहुत कम उर्वरक की मात्रा के साथ बेहतरीन उत्पादन देती हैं जहां अन्य फसल नहीं रह सकती है। बाजरा मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। बाजरा के लिए 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल रहता है। बाजरे की खेती के लिए जल निकास की बेहतर सुविधा होने चाहिए। साथ ही, काली दोमट एवं लाल मिट्टी उपयुक्त हैं। बाजरे की फसल से 30 से 35 क्विंटल दाना एवं 100 क्विंटल सूखा चारा प्रति हेक्टेयर की पैदावार मिलती है। बाजरे की खेती मुख्य रूप से गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बाजरे में आमतौर पर जिंक, विटामिन-ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर तथा विटामिन-बी काम्प्लेक्स की भरपूर मात्रा उपलब्ध है। बाजरा का उपयोग मुख्य रूप से भारत के अंदर बाजरा बेसन लड्डू और बाजरा हलवा के तौर पर किया जाता है।

रागी (मंडुआ) की फसल

विशेष रूप से रागी का प्राथमिक विकास अफ्रीका के एकोपिया इलाके में हुआ है। भारत में रागी की खेती तकरीबन 3000 साल से होती आ रही है। रागी को भारत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न मौसम में उत्पादित किया जाता है। वर्षा आधारित फसल स्वरुप जून में इसकी बुआई की जाती है। यह सामान्यतः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडू और कर्नाटक आदि में उत्पादित होने वाली फसल है। रागी में विशेष रूप से प्रोटीन और कैल्शियम ज्यादा मात्रा में होता है। यह चावल एवं गेहूं से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम व लौह का अच्छा माध्यम है। इसलिए बच्चों के लिए यह प्रमुख खाद्य फसल हैं। रागी द्वारा मुख्य तौर पर रागी चीका, रागी चकली और रागी बालूसाही आदि पकवान निर्मित किए जाते हैं।

कोदों की फसल

भारत के अंदर कोदों तकरीबन 3000 साल पहले से मौजूद था। भारत में कोदों को बाकी अनाजों की भांति ही उत्पादित किया जाता है। कवक संक्रमण के चलते कोदों वर्षा के बाद जहरीला हो जाता है। स्वस्थ अनाज सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसकी खेती अधिकांश पर्यावरण के आश्रित जनजातीय इलाकों में सीमित है। इस अनाज के अंतर्गत वसा, प्रोटीन एवं सर्वाधिक रेसा की मात्रा पाई जाती है। यह ग्लूटन एलजरी वाले लोगो के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है। इसका विशेष इस्तेमाल भारत में कोदो पुलाव एवं कोदो अंडे जैसे पकवान तैयार करने हेतु किया जाता है।

सांवा की फसल

जानकारी के लिए बतादें, कि लगभग 4000 वर्ष पूर्व से इसकी खेती जापान में की जाती है। इसकी खेती आमतौर पर सम शीतोष्ण इलाकों में की जाती है। भारत में सावा दाना और चारा दोनों की पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडू में उत्पादित किया जाता है। सांवा मुख्य फैटी एसिड, प्रोटीन, एमिलेज की भरपूर उपलब्ध को दर्शाता है। सांवा रक्त सर्करा और लिपिक स्तर को कम करने के लिए काफी प्रभावी है। आजकल मधुमेह के बढ़ते हुए दौर में सांवा मिलेट एक आदर्श आहार बनकर उभर सकता है। सांवा का इस्तेमाल मुख्य तौर पर संवरबड़ी, सांवापुलाव व सांवाकलाकंद के तौर पर किया जाता है।

चीना की फसल

चीना मिलेट यानी मोटे अनाज की एक प्राचीन फसल है। यह संभवतः मध्य व पूर्वी एशिया में पाई जाती है, इसकी खेती यूरोप में नव पाषाण काल में की जाती थी। यह विशेषकर शीतोष्ण क्षेत्रों में उत्पादित की जाने वाली फसल है। भारत में यह दक्षिण में तमिलनाडु और उत्तर में हिमालय के चिटपुट इलाकों में उत्पादित की जाती है। यह अतिशीघ्र परिपक्व होकर करीब 60 से 65 दिनों में तैयार होने वाली फसल है। इसका उपभोग करने से इतनी ऊर्जा अर्जित होती है, कि व्यक्ति बिना थकावट महसूस किये सुबह से शाम तक कार्यरत रह सकते हैं। जो कि चावल और गेहूं से सुगम नहीं है। इसमें प्रोटीन, रेशा, खनिज जैसे कैल्शियम बेहद मात्रा में पाए जाते हैं। यह शारीरिक लाभ के गुणों से संपन्न है। इसका इस्तेमाल विशेष रूप से चीना खाजा, चीना रवा एडल, चीना खीर आदि में किया जाता है।

गेहूं के विपणन तथा भंडारण के कुछ उपाय

गेहूं की कटाई व गहाई पूरी हो गई है। अब कुछ लोग मंडियों में न्यूनतम मूल्य यानी एम.एस.पी. पर अपनी उपज बेच रहे हैं तो कुछ लोग अपने इस्तेमाल या अच्छे दाम की उम्मीद में अनाज का भंडारण कर रहे हैं। लेकिन, अगर भंडारण का तरीका सही नहीं हुआ तो अनाज खराब होने का खतरा पैदा होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक अनाज को भंडारण में रखने के लिए कई बाते ध्यान रखने योग्य हैं,
जैसे-

1. अनाज भंडारण मे रखने से पहले भंडारघर की सफाई करें,
2. अनाज को अच्छी तरह उसे सुखा लें,
3. दानों में नमी 12 प्रतिशत से ज्यादा नही होनी चाहिए,
4. छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हे भरकर बंद कर लें,
5. बोरियों को धूप में सुखाकर रखें,
6. बोरियों को 5 प्रतिशत नीम तेल के घोल से उपचारित करें,
7. अगर संभव हो तो, गेहूं को नमी-रोधी, खाद्य-श्रेणी की पैकेजिंग में संग्रहित करें, जैसे माइलर-प्रकार के बैग, पॉलीथीन बैग,
8. अनाज की बोरियों के सीधे जमीन पर ना रखे जमीन से 10-12 इंच ऊपर रखें,
9. चूहों के नियंत्रण के लिए मूषकनाशी दवा व, चूहे दानी का प्रयोग करें।
10. यदि लंबे समय तक भंडारण किया जाता है, तो कीटनाशकों के प्रयोग की आवश्यकता होगी,
11. गेहूँ को आक्सीजन के अभाव में तब तक भण्डारित करना आवश्यक नहीं है जब तक कीट उपस्थित न हों,
12. अगर खुले में भण्डारण कर रहे हैं, तो बोरियों के चट्टे को तिरपाल से ढक दें ।

गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण कैसे करें :
देश, विदेश में गेहूं की मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार गेहूं को समर्थन मूल्य में खरीदना शुरू कर दिया है, जिसका पैसा सीधे बैंक खाता में मिलता है। लेकिन अधिकांश किसानों को गेहूं का पंजीकरण कैसे करते है पता नहीं होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वेबसाइट, HTTPS://FCS.UP.GOV.IN शुरू की है, ताकि राज्य के सभी किसान गेहूं को समर्थन मूल्य में बेचने के लिए घर बैठे मोबाइल से पंजीकरण कर सके। गेहूं की बढ़ती लागत को देखते हुएसरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य को 110 रूपए बढ़ा दिया है इस वर्ष, 2023 में गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रूपए है। गेहूं के साथ ही साथ सभी प्रकार के रबी फसल के समर्थन मूल्य में वृद्धि किया है, लेकिन बहुत से किसानों को इसकी जानकारी नहीं होते है, जिसके कारण गेहूं को बाजार में बेच देते है। गेहूं को समर्थन मूल्य में बेचने के लिए पंजीकरण करना बहुत ही आसान है।

गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण कैसे करें ?

- सबसे पहले गेहूं का पंजीकर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट HTTPS://FCS.UP.GOV.IN/ को खोलना
- इसके बाद यूपी सरकार खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट खुल जायेगा जिसमे **गेहूं क्रय प्रबंधन प्रणाली** के ऑप्शन का चयन करें,
- गेहूं क्रय प्रबंधन प्रणाली के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद नया पेज खुलेगा जिसमे आपको गेहूँ 2023-24 के ऑप्शन को चुनना है|

- इसके बाद शाखा का नाम, यूजर टाइप, ईमेल आईडी, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड भरकर SUBMIT बटन का चयन कर देना है।
- इसके बाद गेहूं का पंजीयन करने का फॉर्म खुल जायेगा जिसमे पूछे गए सभी जानकारी को भरकर SUBMIT कर देना है।
- इस प्रकार आप गेहूं को समर्थन मूल्य में बेचने के लिए घर बैठे मोबाइल से पंजीकरण कर सकते है और 2125 रूपए में गेहूं को बेच सकते है।

गेहूं का पंजीयन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोट साइज फोटो
- जमीन का पर्ची

लेखक
डॉ. अंजू कापड़ी एवं डॉ.हरी शंकर गौड़
कृषि महाविद्यालय, गलगोटियास विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा

जानें दुनियाभर में मशहूर पुंगनूर गाय की पहचान और विशेषताओं के बारे में

जानें दुनियाभर में मशहूर पुंगनूर गाय की पहचान और विशेषताओं के बारे में

भारत में गाय का पालन प्राचीन काल से लगातार चलता आ रहा है। किसान कई सदियों से कृषि के साथ गावों में गाय पालन भी करते आ रहे हैं। भारत में गाय की विभिन्न सारी देसी नस्लें हैं, इन सबकी अपनी-अपनी विशेषताएं होती हैं। इनमें से आपने भी बहुत सारी प्रजातियों की गायों को देखा होगा। साथ ही, कुछ गायों के विषय में सुना भी होगा। पुंगनूर गाय भी इन्हीं में शामिल है, जो अपने कद-काठी के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। पुंगनूर गाय विश्व की सबसे छोटी गाय है, जो कि फिलहाल विलुप्ती की कगार पर है।

पुंगनूर गाय की मुख्य विशेषताएँ

1. शरीर का रंग : पुंगनूर मवेशी भिन्न-भिन्न रंगों में पाए जाते हैं। इनके शरीर में सफेद रंग सहित लाल, भूरे अथवा काले रंग के धब्बे भी दिखाई पड़ जाते हैं।

2. शरीर : पुंगनूर गाय विश्व में बहुत कम मिलने वाले पशुओं की प्रजाति में से एक है। इसका शरीर पीछे की तरफ से झुका हुआ और आगे से पीछे की तरफ पूंछ जमीन को छूती हुई होती हैं।

3. सींग: पुंगनूर किस्म का माथा चौड़ा और सींग छोटे होते हैं। सींग वर्धमान के आकार के होते हैं और अक्सर पुरुषों में आगे और पीछे की ओर और मादाओं में पार्श्व और आगे की तरफ झुके हुए होते हैं।

पुंगनूर गाय की यह पहचान होती है
1. पुंगनूर मवेशी की पूंछ जमीन को छूने लायक लंबी होती है।

2. पुंगनूर गाय के सींग थोड़े टेड़े-मेड़े होते हैं और पीठ बिल्कुल सपाट होती है।

3. पुंगनूर गाय का पीछे का भाग नीचे की तरफ झुका हुआ होता है।

पुंगनूर गाय में क्या-क्या खासियत मौजूद होती हैं

1. पुंगनूर गाय की प्रजाति अधिकांश सूखा प्रतिरोधी है। यह सूखे चारे पर भी जिंदा रह सकती है। पुंगनूर गाय औसतन प्रतिदिन तकरीबन 3-5 किलोग्राम दूध का उत्पादन कर सकती है।
2. गाय की यह पुंगनूर प्रजाति प्रति दिन औसतन 3-5 लीटर दूध उत्पादन करती है। इसके लिए इस गाय को रोजाना 5 किग्रा आहार की जरूरत होती है।
3. पुंगनूर मवेशी विशेष तौर से दूध उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनके दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती है और यह औषधीय गुणों से भरे होते हैं।
4. पुंगनूर मवेशी काफी कठोर जानवर हैं। वह अपने गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादन के लिए मशहूर हैं। बाकी मवेशियों की प्रजातियों के दूध की अपेक्षा में उनके दूध में वसा की अधिक मात्रा होती है। सामान्य तौर पर गाय के दूध में 3 से 5 प्रतिशत वसा की मात्रा विघमान होती है। बतादें, कि पुंगनूर गाय के दूध में करीब 8 प्रतिशत वसा की मात्रा मौजूद होती है।

इस राज्य में किसान कीटनाशक और उर्वरक की जगह देशी दारू का छिड़काव कर रहे हैं

किसान पंकज का कहना है, कि एक एकड़ भूमि में 500 एमएल देसी शराब का छिड़काव किया जाता है। इससे फसलीय उत्पादन में वृद्धि होने की बात कही जा रही है।

ऐसे तो किसान बेहतरीन उत्पादन के लिए खेतों में उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। परंतु, मध्य प्रदेश के कुछ किसान पैदावार बढ़ाने के लिए अजीबोगरीब तरीका अपना रहे हैं। जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां के किसान दलहन के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के लिए फसलों को देसी शराब पिला रहे हैं। हालांकि, इससे फसलों को कोई हानि नहीं पहुंचने का दावा किया जा रहा है। किसानों का यह मानना है, कि ऐसा करने से दलहन की पैदावार बढ़ जाती है।

इस जनपद के किसान फसल को पिला रहे देशी दारू

मीडिया के अनुसार, नर्मदापुरम जनपद में किसानों ने ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती की है। यहां पर किसान मूंग की दोगुनी पैदावार लेने के लिए फसल पर देसी दारू का छिड़काव कर रहे हैं। किसानों का यह भी कहना है, कि इंसान की भांति पौधे भी दारू पीते हैं। इससे फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। कहा जा रहा है, कि नर्मदापुरम के अतिरिक्त अन्य दूसरे जनपदों में भी किसान खेती की इस विधि को अपना रहे हैं। किसानों का कहना है, कि आगामी दिनों में पूरे राज्य में मूंग की फसल को देसी दारू पिलाने का चलन चालू हो जाएगा। इससे राज्य में मूंग का उत्पादन बढ़ जाएगा।

किसानों ने देसी दारू के छिड़काव को लेकर क्या कहा है

दरअसल, जनपद के किसान देसी दारू को कीटनाशक के तौर पर फसलों के ऊपर छिड़काव करते हैं। किसानों ने कहा है, कि देसी दारू को पानी में मिलाकर स्प्रे मशीन के जरिए से फसल पर छिड़काव किया जाता है। इससे कीट- पतंग भी मर जाते हैं। किसानों के मुताबिक, रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करने से हम लोगों की सेहत पर भी प्रभाव पड़ता था। कीटनाशक का छिड़काव करने वाले इंसान की आंखों में तेज जलन होने लगती है। इतना ही नहीं सिर में भी काफी दर्द होता है। बहुत बार तो यह भी देखा गया है, कि किसान बीमार भी पड़ जाते हैं। परंतु, देसी दारू के साथ इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।

वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक केके मिश्रा का शराब छिड़काव पर क्या कहना है

जानकारी के लिए बतादें, कि कुछ स्थानीय किसानों का ऐसा मानना है, कि देसी दारू एक प्रकार से जैविक दवा है। यह रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में काफी सस्ती भी होती है। ऐसे में किसानों की खेती पर होने वाली लागत कम हो जाती है। स्थानीय किसान पंकज ने कहा है, कि एक एकड़ जमीन पर 500 एमएल देसी शराब का छिड़काव किया जाता है। 20 लीटर जल में 100 एमएल देसी शराब का मिश्रण करके पौधों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। साथ ही, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक केके मिश्रा ने कहा है, कि ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में शराब का छिड़काव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे फसल को किसी तरह का कोई लाभ भी नहीं होने वाला है, बल्कि साइड इफेक्ट ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में फसलों की पैदावार में इजाफा होने की जगह गिरावट हो सकती है।

इस राज्य सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए जारी किए 450 करोड़

गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए यह धनराशि सहकारी चीनी मिलों पर कर्ज के तौर पर पहले से लंबित थी। इसलिए गन्ना उत्पादक किसान लंबे समय से बकाया धनराशि का भुगतान किए जाने की लगातार मांग कर रहे थे।

उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसानों लिए एक अच्छा समाचार है। शीघ्र ही राज्य के हजारों गन्ना उत्पादक कृषकों के खाते में बकाया राशि पहुंचने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा गन्ना बकाया का भुगतान करने का आदेश दे दिया है। विशेष बात यह है, कि इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 450 करोड़ रुपये की राशि जारी भी कर दी गई है। साथ ही, इस खबर से किसानों के मध्य प्रशन्नता की लहर है। किसानों का यह कहना है, कि फिलहाल वह बकाया धनराशि के पैसे से वक्त पर खरीफ फसलों की खेती बेहतर ढ़ंग से कर पाऐंगे।

किसानों ने ली चैन की साँस

मीडिया खबरों के अनुसार, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान हेतु यह राशि सहकारी चीनी मिलों पर कर्ज के तौर पर पहले से लंबित थी। ऐसी स्थिति में गन्ना उत्पादक किसान लंबे वक्त से बकाया धनराशि का भुगतान किए जाने की मांग कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में धान की बुवाई आरंभ होने से पूर्व सरकार के इस निर्णय से किसान भाइयों ने राहत भरी सांस ली है।

गन्ने की खेती काफी बड़े पैमाने पर की जाती है

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि संपूर्ण भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। फसल सीजन 2022-23 में 28.53 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई। साथ ही, यूपी के उपरांत गन्ना उत्पादन के संबंध में महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है। यहां पर गन्ने का क्षेत्रफल 14.9 लाख हेक्टेयर हैं। ऐसी स्थिति में हम कहा जा सकता है, कि उत्तर प्रदेश अकेले 46 प्रतिशत क्षेत्रफल में गन्ने की खेती करता है। उधर महाराष्ट्र की देश के कुल गन्ने के क्षेत्रफल में 24 फीसद भागीदारी है। हालांकि, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और हरियाणा में भी किसान बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती करते हैं।

गन्ना उत्पादक किसानों को कितने करोड़ का भुगतान किया जा चुका है

उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है, कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद से अभी तक वह गन्ना उत्पादक किसानों को 2 लाख 11 हजार 350 करोड़ का भुगतान कर चुकी है। इससे 46 लाख गन्ना किसानों के खाते में भुगतान राशि भेजी जा चुकी है। सरकार का यह भी दावा है, कि वह देश में गन्ना किसानों का भुगतान करने में सबसे अग्रणीय है। बतादें, कि यूपी में पेराई सत्र 2022-23 के समय कृषकों से 350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना खरीदा गया है। उधर सामान्य किस्म के गन्ने का भाव 340 रुपये और क्वालिटी प्रभावित गन्ने का भाव 335 रुपये प्रति क्विंटल रहा है।

हर तरह की मिट्टी में उत्पादित होने वाले सफेद चंदन की खेती से बनें अमीर

सफेद चंदन की खेती किसी भी तरह की मृदा में की जा सकती है। सफेद चंदन बंजर, धूस, पथरीली और ऊसर मृदा में भी तीव्रता के साथ उन्नति करता है। समय के चलते पढ़े-लिखे लोगों की रुचि भी खेती के प्रति बढ़ती जा रही है। वर्तमान में अच्छे- खासे वेतन वाली नौकरी को छोड़कर इंजीनियर और एमबीए पास युवक कृषि के अंदर अपने हाथ आजमा रहे हैं। विशेष बात यह है, कि इस प्रकार के प्रोफेशनल युवा वैज्ञानिक ढ़ंग से कृषि कर रहे हैं, जिससे उनको ज्यादा मुनाफा हो रहा है।

कोई उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रदेशों में सेब की खेती कर रहा है, तो कोई अखरोट और आंवले की बागवानी कर रहा है। परंतु, इन युवाओं को यह पता होना जरूरी है, कि सफेद चंदन की खेती में इन फसलों की तुलना में अधिक मुनाफा होता है। यदि युवा सफेद चंदन की पैदावार करते हैं, तो लाखों नहीं करोड़ों में मुनाफा कमाऐंगे।

सफेद चंदन की खेती इन राज्यों में की जा सकती है

मीडिया एजेंसियों के अनुसार, सफेद चंदन का उत्पादन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी किया जा सकता है। बहुत सारे किसानों ने तो इन राज्यों में सफेद चंदन की खेती चालू भी कर दी है। सफेद चंदन की लकड़ी काफी ज्यादा महँगी होती है। बाजार में इसकी कीमत 8 से 10 हजार रुपये प्रतिकिलो है। विदेशों में एक किलो सफेद चंदन का भाव 25 हजार रुपये है। मतलब कि चंदन के एक पेड़ से लाखों रुपये की आमदनी की जा सकती है। एक एकड़ में सफेद चंदन की खेती चालू करने पर एक लाख रुपये का खर्चा आता है। परंतु, 14 से 15 वर्ष के उपरांत इससे आप करोड़ों रुपये की आमदनी कर सकते हैं।

सफेद चंदन से निर्मित किए जाने वाले उत्पाद

सफेद चंदन औषधीय गुणों से संपन्न होता है। इसका इस्तेमाल खिलौने, परफ्यूम, हवन सामग्री, अगरबती, कंठी माला और साबुन बनाने में किया जाता है। चंदन से निर्मित किए गए साबुन और परफ्यूम काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं। यदि किसान भाई सफेद चंदन की खेती करते हैं। तब उनकी कुछ वर्षों के बाद जिंदगी ही बदल जाएगी।

सफेद चंदन की खेती के लिए हर प्रकार की मृदा उपयुक्त है

सफेद चंदन की खेती हर तरह की मृदा में की जा सकती है। यह पथरीली, बंजर, धूस और ऊसर मृदा में भी तेजी के साथ विकास करता है। हालाँकि, इस सब के बावजूद भी दोमट मृदा सफेद चंदन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसका उत्पादन शुरू करने से पूर्व भूमि को सही ढंग से तैयार कर लें। दो पौधों के मध्य कम से कम 10 फीट की दूरी अवश्य रखें। एक एकड़ में चंदन के 400 से ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। साथ ही, समय- समय पर इसकी सिंचाई भी करते रहें। मुख्य बात यह है, कि जिस खेत में आपने सफेद चंदन के पौधे लगाए हैं, उसके अंदर जल निकासी की भी बेहतरीन सुविधा होनी चाहिए। खेत में जलभराव होने की स्थिति में पौधों को काफी हानि भी हो सकती है।

गाजर का जडोंदा रोग एवं उनके उपाय

गाजर का जडोंदा रोग एवं उनके उपाय

गाजर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विटामिन ए, खनिज और आहार फाइबर का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। गाजर की मूसला जड़ का सेवन करने से खून की कमी और आंखों की रोशनी से संबंधित बीमारियों से बचा जा सकता है। गाजर को सलाद के रूप में कच्चा खाया जाता है या सब्ज़ी, करी बनाने के लिए पकाया जाता है। गाजर का हलवा या खीर लोकप्रिय स्वास्थ्यवर्धक मिठाई हैं । ताजा गाजर का रस अत्याधिक पौष्टिक और ताजगी-भरा पेय है। लाल या बैंगनी गाजर को किण्वन करके तैयार की गई कांजी एक पौष्टिक, स्वादिष्ट खट्टा पेय है, जो गर्मियों में बहुत तरोताजा कर देती है।

गाजर को विभिन्न रूपों में अचार या सूखे टुकड़े, फ्लेक्स या पाउडर के रूप में संरक्षित किया जा सकता है। इनकी बाजार में बहुत मांग है। जाहिर है, लाल, पीली या बैंगनी गाजर का उत्पादन किसानों के लिए फायदे की खेती है। व्यापारियों और उद्योगों को भी लाभदायक व्यवसाय के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले गाजर की आवश्यकता होती है। स्वस्थ गाजर 2-6 सेंटीमीटर की औसत मोटाई के साथ 10-30 सेंटीमीटर लंबी टेपरिंग मूसला जड़ें होती हैं। वे अच्छी पानी की उपलब्धता और जल निकासी वाली हल्की रेतीली, बलुई मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती हैं। अधिकतर किसान गाजर को एक ही खेत में बार-बार, या अन्य सब्जियों के साथ मिश्रित फसलों में उगाते हैं। अक्सर वे पाते हैं कि कुछ गाजर विकृत हैं और दो या दो से अधिक शाखाओं में विभाजित हैं जो सीधी या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। अक्सर वे कई बारीक जड़ों से ढके होते हैं। ऐसी गाजर बाजार में स्वीकार नहीं की जाती है। इस प्रकार, किसानों को उनके श्रम, समय और निवेश की भारी हानि होती है। उनको बहुत आर्थिक घाटा हो जाता है।

गाजर जडोंदा रोग का प्रमुख कारण जड़-गाँठ सूत्रकृमि / नेमाटोड द्वारा संक्रमण है। ये अधिकांश सब्जियों की फसलों के गंभीर कीट हैं। ये बहुत छोटे, पतले कृमि होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये बड़ी संख्या में मिट्टी में पाए जाते हैं। पौधों की नई जड़ों में प्रवेश करते हैं और जड़ के ऊतकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे पास के जड़ के ऊतकों की सूजन (जड़-गाँठ) का कारण बनते हैं। इससे जड़ द्वारा मिट्टी से लिए गए पोषक तत्व और जल पौधे के ऊपरी भागों तक नहीं पहुँच पाते हैं। इससे पौधों की वृद्धि और उपज में कमी आती है। छोटे और पीले रंग के पौधे खेतों में कुछ स्थानों पर देखे जाते हैं जहां इन पादप परजीवी सूत्रकृमियों का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। एक चम्मच मिट्टी में सैकड़ों सूत्रकृमि हो सकते हैं ।

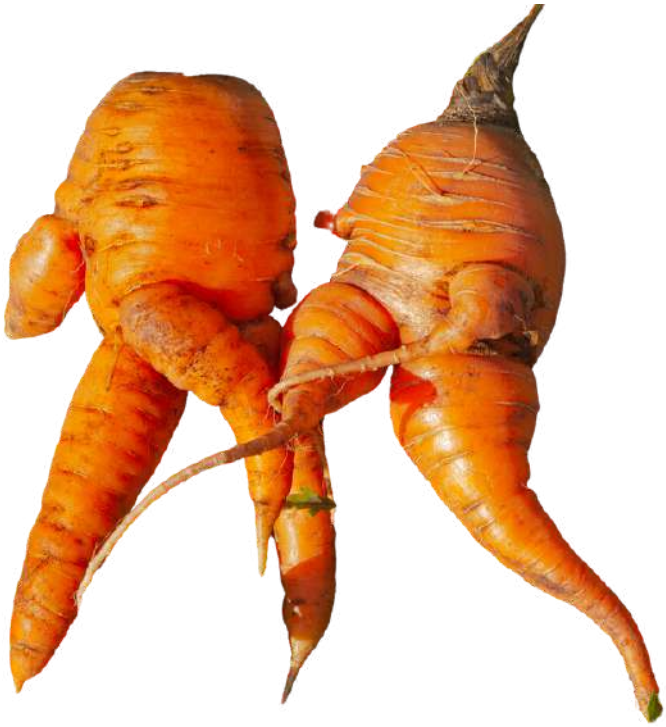

सूत्रकृमियो द्वारा क्षतिग्रस्त जड़ों पर कवक और बैक्टीरिया भी हमला करते हैं और जटिल रोग बनाते हैं। इन सूत्रकृमियो की एक बहुत विस्तृत मेजबान श्रृंखला है और 3000 से अधिक विभिन्न प्रकार के पौधों को संक्रमित करते हैं। टमाटर, बैंगन, भिंडी, चौलाई, आलू, चुकंदर, मिर्च, गाजर, खीरे, लौकी, तोरी, करेला, टिंडा, कद्दू, स्क्वैश, शरबत, तरबूज, कस्तूरी-खरबूज आदि सभी फसलें सूत्रकृमियो से संक्रमित होते हैं। इन सूत्रकृमियों का जनसंख्या घनत्व वर्षों में मिट्टी में बढ़ता रहता है। जब किसानों द्वारा एक या एक से अधिक मौसमों में या गाजर के साथ एक ही खेत में ऐसी फसलें उगाई जाती हैं, तो ये सूत्रकृमि गाजर की युवा बढ़ते नल-जड़ में प्रवेश कर जाते हैं और उस बिंदु पर इसकी वृद्धि को रोक देते हैं। इसकी वजह से पौधे टैप-रूट की एक और शाखा पैदा करता है।

नई नल-जड़ भी संक्रामक सूत्रकृमि से संक्रमित हो सकती है, और वह जड़ भी शाखित हो जाती है। जब एक ही पौधे की मूसला जड़ की कई शाखाएँ बढ़ रही होती हैं, तो वे छोटी और कभी-कभी मुड़ी हुई रहती हैं । इस प्रकार, ये गाजर लगातार पोषक तत्वों और पानी का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन सामान्य गाजर को अच्छी दिखने वाली सीधी सुडोल गाजर नहीं बनाते हैं।

सूत्रकृमि के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के उपाय पादप परजीवी सूत्रकृमि अपने जीवन चक्र के एक या अधिक चरण मिट्टी में व्यतीत करते हैं। एक बार जब वे पौधे की जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, तो उपचार करने का कोई तरीका उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए, खेत में फसल बोने से पहले सूत्रकृमि की संख्या को कम करने के लिए कई तरीकों को अपनाने की आवश्यकता होती है। जड़-गांठ सूत्रकृमि द्वारा गाजर की जड़ों के संक्रमण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं:

1. ऐसे खेत में गाजर कभी न उगाएं जिसमें पिछले मौसम में उगाई गई सब्जियों की फसल में छोटी या बड़ी सूजन या जड़-गांठ हो । कटाई के समय फसलों की बारीक जड़ों को धीरे से निकालें, धीरे से पानी से धो लें और जड़-गांठ सूत्रकृमि देखने के लिए आवर्धक लेंस से जड़ का निरीक्षण करें।
2. फसल चक्र अपनाएं। गाजर को उन खेतों में उगाया जा सकता है जिनमें पिछली फसल गेहूँ, जौ, जई, सरसों, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल आदि थी।
3. मिट्टी को गर्म और सुखाने के लिए खेत की गहरी गर्मियों की जुताई करें। सूत्रकृमि गर्म और सूखी मिट्टी को सहन नहीं कर पाते हैं. इसलिए ऊपरी मिट्टी की परत में इनकी संख्या घट जाती है ।
4. ट्राइकोडर्मा विरिडे, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस जैसे जैव-एजेंटों से समृद्ध गोबर खाद का प्रयोग करें।
5. यदि संभव हो तो फसल चक्र अपनाएं जिसमें खेत को दो भागों में बांटा जाता है। गेहूँ/जौ/जई/ज्वार/बाजरा/मक्का/सरसों/तिल को एक वर्ष में एक भाग में तथा दूसरे भाग में सब्ज़ियों को वैकल्पिक वर्षों में उगाया जा सकता है।

किसान भाई उपरोक्त तरीकों से रोग की पहचान कर उसका उपचार करें तथा स्वस्थ गाजर का उच्च उत्पादन लेकर अधिक लाभ पाएं। आपके क्षेत्र के पास कृषि महाविद्यालयों में परामर्श के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध हो सकते हैं। मिट्टी में सूत्रकृमियों की उपस्थिती तथा जनसंख्या घनत्व की जांच भी यहां की प्रयोगशाला में करवा सकते हैं। गलगोटिया विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा के कृषि महाविद्यालय में ऐसे विशेषज्ञ हैं जो बिना किसी शुल्क के फसलों के रोगों की पहचान कर सकते हैं और उनके इलाज के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। किसान भाई, बहिन इसका लाभ उठा सकते हैं।

गाजर का जडोंदा रोग

डॉ. हरि शंकर गौड़ एवं डॉ. उजमा मंजूर
कृषि महाविद्यालय, गलगोटियास विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश

अमरूद की इन बेहतरीन किस्मों से किसान प्रतिवर्ष लाखों की आय कर सकते हैं

आपकी जानकारी के लिए बतादें कि अमरूद एक ऐसी फसल है, जिसका उत्पादन किसी भी प्रकार की जलवायु में किया जा सकता है। यह 5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक के तापमान को सहन करने में सक्षम है।

अमरूद का सेवन करना सभी लोगों को काफी पसंद है। यह एक ऊर्जावान फल है। यह मिनरल्स और विटामिन से भरपूर है। सर्दी के मौसम में लोग इसका सेवन बड़े ही चाव से करते हैं। इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर भी विघमान रहता है। अमरूद का सेवन करने से कब्ज की बीमारी बिल्कुल सही हो जाती है। अच्छे एवं ताजे अमरूद का भाव सदैव 60 से 80 रुपये प्रतिकिलो होता है। अब ऐसी स्थिति में यदि किसान भाई अमरूद का उत्पादन करते हैं, तो उनकी आमदनी में काफी इजाफा हो सकता है।

अमरुद की कुछ बेहतरीन किस्में

अमरूद की फसल एक बागवानी फसलों के अंतर्गत आती है। अमरुद की खेती हर एक तरह की मृदा में की जा सकती है। एक हेक्टेयर में अमरूद की खेती करने पर किसान वर्ष भर में 24 लाख रुपये की आमदनी कर सकते हैं। इसमें 14 से 15 लाख रुपये का मुनाफा होगा। विशेष बात यह है, कि अमरूद की खेती की शुरूआत करने से पूर्व किसानों को इसकी बेहतरीन प्रजातियों के विषय में जानना होगा। यदि किसान भाई, बाग में अच्छी किस्म के पौधे नहीं रोपेंगे, तो निश्चित रूप से पैदावार प्रभावित होने की संभावना रहती है। हिसार सुर्खा, सफेद जैम,अर्का अमुलिया और वीएनआर बिही अमरूद की अच्छी किस्में हैं।

इसके अतिरिक्त चित्तीदार, इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ-49 भी अमरूद की शानदार किस्में हैं।

अमरुद के पौधे हमेशा एक पंक्ति में 8 फीट की दूरी पर ही लगाएं

अमरूद बागवानी के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी फसल है, जिसकी खेती हर तरह की जलवायु में की जा सकती है। यह 5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक तापमान को सह सकता है। इस वजह से किसान पूरे भारत में इसका उत्पादन कर सकते हैं। एक बार खेती आरंभ करने पर किसान कई वर्षों तक मुनाफा कमा सकेंगे। अमरूद के पौधों को सदैव एक पंक्ति में 8 फीट की दूरी पर ही लगाएं। इससे पौधों को भरपूर मात्रा में धूप, हवा और पानी मिलते हैं, जिससे फसल का काफी अच्छा विकास होता है। दो पंक्तियों के मध्य 10 से 12 फीट की दूरी भी होनी चाहिए। ऐसे में आपको पौधे के ऊपर कीटनाशकों का छिड़काव करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही, फल की तुड़ाई करना भी काफी सुगम हो जाएगा।

एक हेक्टेयर भूमि में 1200 अमरूद के प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं

किसान भाई एक हेक्टेयर में 1200 अमरूद के प्लांट स्थापित कर सकता है। 2 साल के उपरांत अमरूद के बाग में फल आने चालू हो जाएंगे। इस दौरान रोपाई से लेकर पौधों के रख-रखाव पर लगभग 10 लाख की लागत आएगी। साथ ही, 2 साल के उपरांत एक सीजन में एक पेड़ से आप लगभग 20 किलो तक अमरूद तोड़ सकते हैं। इस प्रकार आप 1200 अमरूद के पौधों से एक सीजन में 24000 किलो अमरूद अर्जित कर सकते हैं।

किसान इस तरह अमरूद की खेती से 24 लाख तक की आमदनी कर सकते हैं

बाजार में अमरूद 60 से 80 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से बिकता है। अगर आप 50 रुपये किलो के हिसाब से भी अमरूद बेचते हैं, तो 24000 किलो अमरूद का भाव लगभग 12 लाख रुपए हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि अमरूद का पेड़ वर्ष में दो बार फल प्रदान करता है। इस प्रकार आप अरूद की खेती से 24 लाख तक की आमदनी कर सकते हैं।

भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, कॉफी की खेती कैसे की जाती है

भारत के अंदर अधिकांश लोग चाय या कॉफी के शौकीन होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बतादें कि देश के कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में एक बड़े पैमाने पर कॉफी का उत्पादन किया जाता है। दरअसल, देश का कर्नाटक राज्य सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है।

भारत के अंदर अगर लोग चाय के बाद किसी पेय पदार्थ का सेवन करना पसंद करते हैं, उसका नाम कॉफी है। कॉफी को लेकर युवाओं के मध्य अच्छी-खासी रूचि देखने को मिल रही है। इसको स्वास्थ के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। परंतु, क्या आप यह जानते हैं, कि कॉफी की खेती किस प्रकार से की जाती है। अब हम आपको इस लेख में कॉफी की खेती के बारे में जानकारी देने वाले हैं।

भारत के किन राज्यों में कॉफी का अधिकांश उत्पादन किया जाता है

भारत के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती विशेष रूप से की जाती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कॉफी का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। कॉफी के पौधों का मात्र एक बार रोपण करने के उपरांत वर्षों तक इससे उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इसकी खेती के लिए सर्वप्रथम खेत की मृदा को ढीला करने के लिए जुताई करनी पड़ती है। उस स्तर के इलाके के उपरांत पुनः कुछ दिनों के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। खेत को एकसार करने के उपरांत चार या पांच मीटर की पंक्ति एवं चार मीटर की पंक्ति की दूरी वाले गड्ढे तैयार करें। प्रत्येक पंक्ति में पौधरोपण किया जाए। जब गड्ढा तैयार हो जाए तब पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद और रासायनिक खाद मृदा में मिला दें। उसके बाद गड्ढे में डाल दें। इन समस्त गड्ढों को भरने के उपरांत सही ढ़ंग से सिंचाई कर दें। गड्ढे में मृदा सही तरह से जम जाए इसके लिए पुनः गड्ढे को ढक दें। पौधे लगाने से एक माह पूर्व गड्ढा तैयार कर लें।

कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त तापमान क्या होता है

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, कॉफी का उत्पादन करने के लिए करीब 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश पर्याप्त होती है। यह सर्दियों में खेती के लिए अनुकूल नहीं होती है। क्योंकि, ऐसे मौसम में इसके पौधों का बढ़ना रुक जाता है। इसके पौधों की उन्नति और बढ़ोत्तरी के लिए 18 से 20 डिग्री का तापमान उपयुक्त माना जाता है। परंतु, यह गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री और सर्दियों में कम से कम 15 डिग्री तक सहन कर सकता है।

भारत की सबसे पुरानी कॉफी कौन-सी है

भारत में कॉफी की विभिन्न किस्मों का उत्पादन किया जाता है। वह विभिन्न प्रकार की मृदा में पैदा की जाती हैं। इसी कड़ी में हम भारत की केंट कॉफी पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि यह भारत की सबसे पुरानी कॉफी मानी जाती है। केरल राज्य के अंतर्गत इसकी सबसे ज्यादा पैदावार होती है। अरेबिका कॉफी को भारत में उत्पादित उच्चतम गुणवत्ता वाली कॉफी कहा जाता है। यह कॉफी समुद्र तल से 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उत्पादित की जाती है। विशेष तौर से दक्षिणी भारत में पैदा होती है। इसके अतिरिक्त भारत में बाकी अन्य किस्मों की भी कॉफी उत्पादित की जाती है।

चीड़ की पत्तियों से बनाई जाएगी कंप्रेस्ड गैस क्या है, जाने क्या है राज्य सरकार की योजना

चीड़ की पत्तियों से बनाई जाएगी कंप्रेस्ड गैस क्या है, जाने क्या है राज्य सरकार की योजना

हम सभी जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में चीड़ के पेड़ काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमालय के आस पास पाए जाने वाले चिल्के इन पेड़ों की पत्तियां नॉनबायोडिग्रेडेबल होती है. इसके अलावा यह पत्तियां अपनी प्रकृति में बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है जो बहुत बार जंगल में आग का कारण भी बन जाती है और पूरे के पूरे जंगल नष्ट कर देती हैं.

सरकार ने इस समस्या का हल निकालने के साथ-साथ चीड़ के पेड़ से किसानों को कुछ लाभ करवाने के बारे में भी योजना बनाई है. पहाड़ी इलाकों में उगने वाले इस पेड़ की पत्तियों से सरकार कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के बारे में सोच रही है.

पहाड़ों में रहने वाले ग्रामीण लोगों की स्थिति में होगा सुधार

गर्मियों के मौसम में चीड़ की पत्तियां गर्मी के कारण आग पकड़ लेती है जो जंगल की आग का कारण बनती है. अब राज्य सरकार द्वारा इन पत्तियों से कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार करने के बारे में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं. यहां की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इसके लिए सबसे पहले चीड़ की पत्तियों को सीबीजी के उत्पादन के टेस्ट के लिए एचडी ग्रीन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर बेंगलुरु में भेजा जाएगा और उसके बाद इस पर आगे का निर्णय लिया जाएगा. अगर यह योजना सफल हो जाती है तो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आसपास के ग्रामीण लोगों के लिए यह बहुत बड़ा आर्थिक सुधार का कदम साबित होने वाला है.

हिमाचल में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में आती हैं जंगल में आग लगने की खबर

अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हिमाचल में लगभग सालाना 1200 से 2500 खबरें जंगल में आग लगने की सामने आ ही जाती हैं. इसे पेड़ों को तो नुकसान होता ही है साथ ही आसपास रहने वाले इलाके के लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इन्हीं घटनाओं को देखते हुए सरकार ने चीड़ की पत्तियों से कंप्लेंट बायोगैस बनाने का फैसला लिया है.

ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है समझौता

राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता करने के लिए अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया है.माना जा रहा है कि इसके लिए जल्द ही पायलट परियोजना की शुरुआत कर दी जाएगी.

ऊर्जा संकट की परेशानी दूर होने की है संभावना

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मानें तो उनके अनुसार वनों से निकलने वाले अपशिष्ट का अगर सही तरह से प्रयोग किया जाए तो यह राज्य में ऊर्जा संकट की परेशानी को दूर कर सकता है. इससे ना सिर्फ जंगल में आग लगने के मामले कम होंगे बल्कि आसपास के क्षेत्र में लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और साथ ही ऊर्जा संकट की परेशानी में भी अच्छा-खासा इजाफा होने की संभावना है.

किसान इन तीन पत्तों के कारोबार से अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं

किसान इन तीन पत्तों के कारोबार से अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं

वर्तमान की नई पीढ़ी को शायद साखू के पत्तों के विषय में जानकारी भी नहीं होगी। एक दौर था जब वैवाहिक कार्यक्रमों में इसके पत्ते का उपयोग प्लेट के तौर पर किया जाता था।

भारत में विभिन्न तरह की खेती की जाती है। भिन्न-भिन्न सीजन और रीजन के अनुरूप यहां किसान अपनी फसल का चयन करते हैं। बहुत सारे लोग पारंपरिक खेती से इतर फूलों का उत्पादन करते हैं, तो कुछ किसान सब्जियों का उत्पादन करते हैं। साथ ही, कुछ लोग फलदार पेड़ लगाकर उससे आमदनी अर्जित करते हैं। हाल ही में जड़ी बूटियों की खेती से भी बेहतरीन मुनाफा अर्जित किया जा रहा है। परंतु, हम आज जिस खेती के विषय में चर्चा कर रहे हैं, वो पत्ते हैं। जी हां, पत्ते, जिन्हें अक्सर किसी काम का नहीं समझा जाता। परंतु, यह तीन पत्ते आपके भाग्य को चमका सकते हैं। पूरे साल इनकी इतनी मांग रहती है, कि यदि आपने इनकी खेती कर ली तो मालामाल हो जाएंगे।

पान के पत्तों से अच्छी आमदनी होगी

बनारस के पान के संबंध में तो आपने अवश्य सुना ही होगा। परंतु, यह बनारस का पान पनवाड़ी के पास किसी खेत से ही आता है। बतादें, कि पान की मांग अब उत्तर भारत से निकल कर संपूर्ण विश्व में हो रही है। इसके औषधीय लाभों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। गुटका खाने वाले लोग भी अब इसके स्थान पर पान को विकल्प बना रहे हैं। भारत सहित दुनियाभर में पान विभिन्न तरह के निर्मित किए जाते हैं, उसी प्रकार से पान के पत्ते के भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। यदि आप भी पान से धन अर्जित करना चाहते हैं, तो आज ही इसकी खेती का प्रशिक्षण लीजिए और इन्हें अपने खेतों में उत्पादित करना आरंभ कर दीजिए।

साखू के पत्तों से कमाऐं

आजकल की नई पीढ़ी को साखू के पत्तों के विषय में शायद ही पता होगा। एक वक्त था जब वैवाहिक कार्यक्रम में इसके पत्ते का उपयोग प्लेट के तौर पर किया जाता था। उत्तर भारत एवं पहाड़ी क्षेत्रों में यह बेहद लोकप्रिय है। जब से लोगों के अंदर जागरुकता और समझदारी आई है। डिस्पोजल को छोड़ कर पुनः नेचर की ओर लौट रहे हैं। इस वजह से साखू के पत्तों की मांग विगत कुछ वर्षों में बढ़ी है। सबसे खास बात यह है, कि एक ओर जहां आप साखू के पत्तों से आमदनी करते हैं। साथ ही, दूसरी ओर आप इसकी लकड़ी को बेचकर भी लाखों रुपये की आमदनी की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि साखू की लकड़ी की मांग भारत सहित विदेशों में भी सदैव बनी रहती है।

केले के पत्ते से कमाऐं

केले के पत्तों का उपयोग खाना खाने के लिए किया जाता है। दक्षिण भारत में इसकी मांग बेहद अधिक होती है। परंतु, फिलहाल भारत के अन्य इलाकों में भी केले के पत्तों की मांग में इजाफा हुआ है। दरअसल, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भारत के प्रत्येक इलाके में तीव्रता से खोले जा रहे हैं। अधिकांश साउथ इंडियन रेस्टोरेंट फिलहाल अपने ग्राहकों को ऑथेंटिक भोजन खिलाना चाहते हैं। इसके लिए वह उस भोजन को परोसने के लिए केले के पत्ते का उपयोग कर रहे हैं।

यही वजह है, कि दक्षिण भारत के साथ-साथ उत्तर भारत और देश के बाकी इलाकों में भी केले के पत्तों की मांग बढ़ी है। केले की खेती में सर्वोत्तम बात यह है, कि अब इसका हर हिस्सा बिक जाता है। केला, केले का पत्ता यही नहीं वर्तमान में कुछ लोग इसके तने तक भी खरीद रहे हैं। दरअसल, केले के तने से एक फाइबर उत्पन्न हुई है, जो काफी ज्यादा मजबूत होता है। यही कारण है, कि कुछ लोग केले के तने को भी खरीद रहे हैं।

खुशखबरी : इस राज्य में बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के खाते में पहुंचेंगे 60 हजार रुपए

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से देश के विभिन्न स्थानों पर किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार राहत पैकेज का लाभ केवल 13 प्रभावित जनपदों के किसानों को ही मिलेगा। इन जनपदों के अंतर्गत साबरकांठा, सूरत, कच्छ, अमरेली, जामनगर, भावनगर, अहमदाबाद, जूनागढ़, राजकोट, बनासकांठा, अरवल्ली, तापी और पाटन का नाम शम्मिलित हैं।

गुजरात राज्य के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। गुजरात की बीजेपी सरकार द्वारा किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। गुजरात सरकार का कहना है, कि मार्च और अप्रैल माह के चलते बेमौसम बारिश से राज्य में फसलों की काफी ज्यादा हानि हुई है। इससे किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ी है। हालाँकि, अब किसानों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आजकल राज्य के किसानों को फसलीय क्षति से राहत दिलाने के बदले में मुआवजा धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से रोड मैप तैयार कर लिया है।

इस बार दिए जाने वाली मुआवजे की धनराशि सबसे ज्यादा होगी

द इकोनॉमिक टाइम्स की खबरों के अनुसार, बीते दिनों बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इसके उपरांत मंत्रिमंडल ने राहत पैकेज की घोषणा की है। फिलहाल, शीघ्र ही किसानों के खाते में मुआवजा की धनराशि पहुंच जाएगी। इसके लिए किसानों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही, गुजरात सरकार ने यह दावा किया है, कि इस बार दी जाने वाली राहत धनराशि अब तक की सर्वोच्च सहायता राशि होगी।

इन जनपदों के किसानों को मिलेगी मुआवजे की सहायक धनराशि

गुजरात सरकार द्वारा कुछ जनपदों की सूचि पेश की गई है। जिनको फसलीय क्षति होने की वजह से मुआवजा देने की कवायद की जा रही है। सरकार के अनुसार, राहत पैकेज का लाभ केवल 13 प्रभावित जनपद के किसानों को ही होगा। इन जनपदों में पाटन, साबरकांठा, सूरत, कच्छ, अमरेली, जामनगर, भावनगर, अहमदाबाद, जूनागढ़, राजकोट, बनासकांठा, अरवल्ली और तापी का नाम शम्मिलित है। विशेष बात यह है, कि इन जनपदों में फसल क्षति का आकलन करने के लिए गिरदावरी का कार्य कर लिया गया है।

मुआवजे के अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी

ऐसे किसानों की फसल 33 फीसद या उससे ज्यादा खराब हुई है, उनको राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी उन किसानों को वित्तीय मदद भी प्रदान की जाएगी। विशेष बात यह है, कि सरसों, गेहूं, पपीता, केला और चना जैसी फसलों के लिए किसानों को एसडीआरएफ 13,500 रुपये की सहायता धनराशि प्रदान करेगा। साथ ही, प्रदेश सरकार भी 9,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से किसानों को अलग से सहायता प्रदान करेगी।

सरकार किसानों को कितने रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देगी

जानकारी के लिए बतादें, कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेक्टेयर जमीन के लिए ही किसानों को मुआवजा धनराशि प्रदान की जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ है, कि जिन किसानों की 10 हेक्टेयर में लगी फसल को हानि पहुंची है। उनको भी दो हेक्टयेर के लिए ही मुआवजा धनराशि प्रदान की जाएगी। साथ ही, अमरुद, नींबू और आम की खेती करने वाले कृषकों को 30600 रुपये प्रति हेक्टेयर के अनुरूप मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से केले की फसल बर्बाद, किसान मुआवजे की गुहार कर रहे हैं

अचानक आई बेमौसम, बारिश की वजह से किसानों की फसलों को काफी हानि पहुंची है। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसान आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

बेमौसम, बारिश से किसानों को होने वाली हानि रुकने का नाम नहीं ले रही है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं और सरसों की फसलों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया है। साथ ही, गेहूं, सरसों के अतिरिक्त बाकी फसलें भी प्रभावित हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में लीची, टमाटर और आम सहित विभिन्न फसलों को क्षति पहुँचने की खबरें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश से भी एक ऐसी ही फसल क्षति होने की बात सामने आ रही हैं। किसान सहायता की आशा भरी निगाहों से सरकार की तरफ देख रहे हैं।

मध्य प्रदेश में केला, प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ है

मीडिया की खबरों के मुताबिक, मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से कृषकों को ज्यादा हानि हुई है। ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी की वजह हल्दी, केला और प्याज की फसलें गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। किसानों की हुई फसल क्षति को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से सर्वे कराने की मांग की है।

केले की फसल क्षति के लिए मुआवजे की गुहार कर रहे किसान

स्थानीय किसान राज्य सरकार से केले की फसलों को हुई क्षति की मांग कर रहे हैं। स्थानीय किसानों ने बताया है, कि विगत 3 सालों से केले की फसल का बीमा तक भी नहीं हो सका है। जो कि अतिशीघ्र होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसानों को हुए फसल हानि को ढाई लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। इससे किसानों को अच्छी-खासी राहत मिल सकेगी।

राज्य सरकार ने सर्वे कराने के निर्देश जारी किए

राज्य सरकार के स्तर से किसानों की समस्याओं को देखते हुए सर्वेक्षण करावाना चालू कर दिया है। कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग की एक ज्वाइंट टीम हुए फसलीय क्षति का आंकलन करने में लगी हुई है। टीमों के स्तर से सर्वे का काम तेज कर दिया गया है। वहीं, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बड़ी संख्या में किसान केले की खेती करते हैं। ऐसे में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से इन्ही किसानों को भारी क्षति हुई है। वहीं, बड़ी तादात में किसान ऐसे भी हैं, जोकि यह आरोप लगा रहे हैं, कि उनकी फसलों को काफी ज्यादा क्षति पहुँची है। लेकिन, सर्वे वाली टीम फसलीय क्षति का आंकलन काफी कम दिखा रही है।

इस राज्य सरकार ने किया ऐलान, बेमौसम बारिश की मार से बचेंगे किसान

सरकार की तरफ से गीले चावल को इकठ्ठा करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, एक भी दाना भी खराब किए बिना शीघ्र अतिशीघ्र धान का संग्रह पूर्ण कर लेंगे। निरंतर बेमौसम बारिश के चलते किसानों को भारी हानि हो रही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें किसानों को राहत पहुँचाने की घोषणा कर रही हैं। इसी कड़ी में तेलंगाना का भी नाम भी शामिल हो गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का कहना है, कि किसानों को इस बात की फिकर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फसल बर्बाद होने पर उनकी क्षति का क्या होगा?

मुख्यमंत्री का कहना है, कि इस बारे में सरकार द्वारा पहले ही तैयारी कर ली है। किसानों को जितना धन सामान्य धान के लिए प्रदान किया जाता है। समान धन उस धान के लिए भी दिया जाएगा, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुई है।

मुख्यमंत्री ने कृषि से संबंधित समीक्षा बैठक की है

साथ ही, इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री द्वारा कृषि विभाग को इस बात का भी अध्ययन करने के लिए बोला गया है, कि ऐसी कौन-सी नीति बनाई जाए, जिससे बेमौसम बारिश के मध्य यासंगी धान की कटाई मार्च से पूर्व ही की जा सके। साथ ही, केसीआर का किसानों को मशवरा है, कि बेमौसम बारिश के चलते तीन-चार दिन कटाई ना की जाए। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि मुख्यमंत्री ने कृषि से जुड़ी समीक्षा बैठक भी की थी।

अनाज की बर्बादी नहीं होने देंगे

राज्य सरकार की ओर से ओलावृष्टि से बर्बाद होने वाली फसल के मुआवजे के रुप में किसानों को 10 हजार प्रति एकड़ प्रदान किया जा रहा है। इस बार सरकार की ओर से गीले चावल को एकत्रित करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, एक दाना भी खराब किए बिना शीघ्र अतिशीघ्र धान का संग्रह पूर्ण कर लिया जाएगा। नागरिक आपूर्ति विभाग के कमिश्नर अनिल कुमार ने सीएम केसीआर को जानकारी दी कि बेमौसम वर्षा के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परंतु, अनाज एकत्रित होना शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग और किसानों को बदलते मौसम से सबक लेने को कहा है। साथ ही, जागरुकता फैलाने की भी बात कही है। उन्होंने किसानों को चावल की जल्दी रोपाई करने को कहा, जिससे धान की कटाई मार्च के माह तक संपन्न हो पाए।

सीएम ने अधिकारियों को किसानों के लिए समयानुसार अलर्ट जारी करने को कहा है

मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को और वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करने को कहा है। साथ ही, किसानों में जागरुकता फैलाने के लिए भी बोला है। प्राकृतिक आपदा को लेकर पूर्णतय सतर्क रहने एवं किसानों को समयानुसार जानकारी देने के साथ उनमें जागरुकता उत्पन्न करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है, कि अधिकारी वक्त-वक्त पर किसानों के लिए अलर्ट जारी करते रहें। मुख्यमंत्री का कहना है, कि कृषि विभाग को लोअर लेवल से हाई लेवल तक के अधिकारियों व कर्मचारियों समेत और ज्यादा गतिशील रूप से कार्य करने के साथ-साथ राज्य सरकार की कृषि नीतियों एवं उद्देश्यों को बेहतरीन ढ़ंग से समझने की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए सरकार
गन्ना भुगतान के बाद अब गन्ने की पैदावार में इजाफा करने में जुटी

यह राज्य सरकार बकाये गन्ना भुगतान के निराकरण के बाद अब गन्ने की पैदावार में इजाफा करने की कोशिश में जुटी

गन्ना की फसल एक सालाना फसल है। इसके तैयार होने में कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली वर्षा के अनुरूप 3 से 7 बार जल की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश के लगभग 46 लाख गन्ना कृषकों का फायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने प्रथम कार्यकाल से ही सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। योगी जी के दूसरे कार्यकाल में भी यह सिलसिला उसी ढ़ंग से चल रहा है। केवल आवश्यकता के मुताबिक प्राथमिकताएं परिवर्तित की जा रही हैं। बकाए, मिलों के संचलन की व्यवस्था को बेहतर करने के पश्चात सरकार का ध्यान फिलहाल गन्ने की खेती को और अधिक फायदेमंद बनाने पर है। अब इस बात को साकार तभी किया जा सकता है। जब पैदावार में वृद्धि के साथ-साथ लागत में कमी आएगी। इसके लिए खेती में निवेश की सामर्थ के साथ बेहतरीन संसाधनों की उपलब्धता है।

फसल की तैयारी में कितने जल की आवश्यकता होती है

जैसा कि हम जानते हैं, कि गन्ना एक वर्षभर की फसल है। एक अनुमान के अनुसार, गन्ने की फसल को 1500 से 2500 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है। बतादें, कि प्रति किलोग्राम गन्ना की उपज में 1500 से 3000 हजार लीटर जल की आवश्यकता होती है। इतना तो तब है, जब कृषक अपने खेत की परंपरागत ढ़ंग से पोखर, नलकूप, पंपिगसेट और तालाब से सिंचाई करते हैं। इस प्रकार सिंचाई करने से आधा से ज्यादा जल की बर्बादी हो जाती है। अगर खेत पूर्णतय समतल नहीं है, तो कहीं कम और कहीं ज्यादा जल लगने से फसल में नुकसान हो जाता है।

ड्रिप इरीगेशन बच पाएगी 50 प्रतिशत जल खपत

ड्रिप इरीगेशन (टपक प्रणाली) से कम समय में हम फसल को आवश्यकतानुसार पानी देकर पानी की बर्बादी सहित सिंचाई का खर्चा भी बढ़ा सकते हैं। यही कारण है, कि सरकार का ड्रिप स्प्रिंकलर तरीके से सिंचाई पर काफी ध्यान केंद्रित है। इसके लिए योगी सरकार लघु सीमांत कृषकों को निर्धारित रकबे के लिए 90 प्रतिशत और अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत तक अनुदान देती है।

ड्रिप सिंचाई हेतु योगी सरकार अनुदान मुहैय्या करा रही है

इसी कड़ी में गन्ना विभाग की तरफ से भी एक कवायद की गई है। वह ड्रिप इरीगेशन से बेहतरीन उत्पादन पाने के लिए कृषकों को 20 प्रतिशत ब्याज मुक्त लोन प्रदान करेगी। बतादें, कि इसकी अदायगी गन्ना मूल्य भुगतान से हो सकेगी। यह लोन किसानों को चीनी मिलें और गन्ना विकास विभाग उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इससे राज्य के 90 प्रतिशत से ज्यादा गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। यह किसानों का वही वर्ग है, जो चाहते हुए भी संसाधनों के अभाव के चलते खेती में यंत्रीकरण का अपेक्षित फायदा प्राप्त नहीं कर पाता है। दरअसल, ज्यादा श्रम एवं संसाधन लगाने के बावजूद भी उसको कम फायदा उठा पाते हैं।

टपक सिंचाई से कम लागत में अधिक उपज के साथ होंगे विभिन्न फायदे

ड्रिप इरिगेशन एक फायदेमंद तकनीक है। जल की अत्यधिक खपत के अतिरिक्त प्रत्यक्ष तौर पर पौधों की जड़ों में घुलनशील उर्वरक भी दे सकते हैं। इस प्रकार से खाद के पोषक तत्वों की प्रचूर मात्रा में आपूर्ति के चलते गन्ने की पैदावार में भी वृद्धि होगी। दरअसल, इसके माध्यम से सिंचाई करने में जल की खपत कम, श्रम की बचत साथ ही न्यूनतम खाद के इस्तेमाल से पैदावार भी अच्छी होती है। परिणामस्वरूप, कम लागत और अधिक पैदावार की वजह से कृषकों की आमदनी में वृद्धि होगी। यूपी सरकार की यह प्राथमिकता भी है। इसी कड़ी में यूपी शुगर मिल्स असोसिएशन एवं विश्व बैंक के संसाधन समूह के मध्य एक मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना विकास कोष की स्थापना की है

इसी प्रकार खेत की तैयारी से लेकर रोपाई एवं उससे आगे गन्ना उत्पादकों हेतु संसाधन बाधक बनें। इस बात को लेकर सरकार द्वारा गन्ना विकास कोष स्थापित करने का भी फैसला लिया गया है। इसमें भी नाबार्ड की भाँति 10.70. इस पर 3.70 प्रतिशत की छूट भी होगी। यह कर्जा उन लघु सीमांत किसानों को मिल पाएगा जो गन्ना समितियों में पंजीकृत होंगे।

6 वर्ष में कितने गन्ना उत्पादकों का भुगतान किया गया है

योगी जी ने जब मार्च 2017 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। उस वक्त गन्ने का बकाया, संचलन में चीनी मिलों का मनमानी आचरण गन्ना कृषकों की प्रमुख परेशानी थी। क्योंकि, इसकी खेती से लाखों की संख्या में किसान परिवार जुड़े हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जनपदों की मुख्य फसल ही गन्ना है। दरअसल, गन्ना मूल्य के बकाए पर ही कुछ लोगों की राजनीति चलती थी। क्योंकि, यह किसानों का एक प्रमुख मुद्दा है। मिलों की मनमानी से किसानों को इस हद तक परेशानी थी, कि किसान अपने खेत में ही गन्ना को आग लगा देते थे।

एक मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रथम कार्यकाल में गन्ना किसानों के भुगतान पर ध्यान केंद्रित किया था। नतीजतन, गन्ना उत्पादकों को रिकॉर्ड भुगतान हुआ। मुख्यमंत्री जी के प्रथम कार्यकाल समापन के बाद अब दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने पर जारी किए गए आकड़ों के अनुसार, गन्ना किसानों को दो लाख दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सरकार की तरफ से मिलर्स को साफ निर्देशित किया गया है, कि जब तक किसानों के खेत में गन्ना मौजूद है, तब तक मिलें बंद नहीं की जाऐंगी। इसके अतिरिक्त भुगतान की समयावधि भी निर्धारित की गई है। ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से इसको पारदर्शी भी बनाया गया है।

इस राज्य सरकार ने सर्वाधिक फसल क्षति मुआवजा देने का दावा करते हुए, किसानों के खाते में 159 करोड़ भेजे

विगत मार्च माह में हुई बेमौसम बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि से किसानों की फसल प्रचंड रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही, इस हानि के लिए प्रदेश सरकार भी किसानों की हर संभव सहायता कर रही है। फिलहाल, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के खाते में 159 करोड़ हस्तांतरित किए गए हैं।

विगत खरीफ सीजन किसानों के लिए अनुकूल नहीं रहा था, क्योंकि बाढ़, बारिश एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों को जमकर दुखी किया था। इस रबी के सीजन में किसानों को उपयुक्त पैदावार होने की संभावना थी। बतादें, कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान सहित बहुत सारे राज्यों में किसानों की फसल बिल्कुल चौपट हो गई थी। साथ ही, राज्य सरकारों के स्तर से भी किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही, में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है।

शिवराज सरकार ने 159 करोड़ की धनराशि आवंटित की है

मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि के चलते बड़ी मात्रा में फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके अंतर्गत राज्य में प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों के स्तर से फसलीय क्षति का आंकलन किया जा रहा था। वर्तमान में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से दुष्प्रभावित हुई रबी फसलों का मुआवजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदान किया है। मुख्यमंत्री की तरफ से 36 जिलों के 1 लाख 48 हजार किसानों के खातों में 159 करोड़ 52 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की है।

प्रदेश में किसानों को सर्वाधिक मुआवजा दिया जाता है : शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना है, कि प्रदेश सरकार किसान भाइयों को असहाय स्थिति में अकेला नहीं छोड़ेगी और ना ही उनको किसी तरह की हानि होने देगी। मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है। भारत में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां के किसान भाईयों की फसलीय हानि होने की स्थिति में सर्वाधिक मुआवजा प्रदान किया जाता है। इस बार भी किसानों को धनराशि जारी करने में किसी भी प्रकार का कोई विलंभ नहीं किया जाएगा।

किसानों के परिश्रम से ही हर घर तक अनाज पहुँचता है

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है, कि दिन रात परिश्रम कर किसान अपनी फसल जोतते हैं। किसान भाई ना तो आंधी, बारिश देखते हैं और ना ही ताप, धूप को देखते हैं। देश के प्रत्येक घर तक अनाज किसानों के अथक परिश्रम की बदौलत ही पहुँच पाता है। जब किसान भाई अपने परिश्रम से पीछे नहीं हट रहा है, तो राज्य सरकार भी उनकी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगी। भविष्य में भी फसल क्षति का आंकलन शीघ्र अतिशीघ्र सम्पन्न कराकर कृषकों को मुआवजा प्रदान किया जाता रहेगा।

अब नहीं होगी किसानों को उर्वरकों की कमी, फसलों के लिए प्रयाप्त मात्रा में मिलेगा यूरिया और डी ए पी

इस राज्य में उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में हुआ भंडारण, किसानों को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं

उत्तर प्रदेश में विगत साल 2022 में उर्वरक की खपत में काफी देखने को मिली थी। साथ ही, इस साल प्रदेश सरकार पहले ही बड़ा कदम उठा रही है। उर्वरकों का अभी से भंडारण करना शुरू कर दिया है।

रबी सीजन की फसलें काटकर किसान बेचने के लिए मंडी पहुँचाने लगे हैं। गेहूं से भारत के विभिन्न राज्यों में मंडियां भरी पड़ी हैं। किसानों ने रबी सीजन की फसलें काट ली हैं। उन्होंने नए सीजन की फसलों की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है। जिस तरह अच्छी फसल पाने के लिए अच्छे बीज का होना जरूरी है। इस प्रकार उर्वरक भी खेत के लिए समान उपयोगी है। रबी सीजन में उत्तर प्रदेश में उर्वरक संकट गहरा गया था। पूर्वांचल में किसानों को डीएपी, यूरिया प्राप्त करने के लिए इधर उधर चक्कर काटना पड़ता था। परंतु, इस वर्ष किसानों के समक्ष यह संकट नहीं उत्पन्न होने वाला है। इस बार प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण तैयारी कर ली गई है।

साल 2022 में धान, यूरिया की कितनी खपत हुई

किसी भी फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में उर्वरक की खपत काफी ज्यादा हुई थी। प्रदेश के किसानों ने निजी खेत में 37 लाख मीट्रिक टन यूरिया एवं 8.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी लगाया। ज्यादा डीएपी और यूरिया का उपयोग होने के कारण प्रदेश में इसकी कमी हो गई थी। परंतु, वर्तमान में प्रदेश सरकार अभी से इसका भंडारण करने में लग गई है।

यूरिया और डीएपी का कितना भंडारण हुआ है

मीडिया खबरों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 13.24 लाख मीट्रिक टन यूरिया के साथ 3.28 लाख मीट्रिक टन डीएपी का भंडारण कर लिया गया है। प्रदेश सरकार के अधिकारियों के बताने के मुताबिक, साल 2022 में किसानों ने यूरिया एवं डीएपी की खपत खूब हुई थी। परंतु, इस बार संपूर्ण हालत को देखते हुए पूर्व से ही बंदोवस्त कर लिया है।

डीएपी, यूरिया की खेत में कितनी आवश्यकता है

एक रिपोर्ट के मुताबिक, खेतों में डीएपी का इस्तेमाल करने के लिए मानक तय हैं। बतादें कि धान में प्रति एकड़ 110 किलोग्राम यूरिया की खपत हो जाती है। डीएपी की 52 किलोग्राम तक खपत हो जाती है। इसके साथ-साथ 40 किलोग्राम पोटाश का भी इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल, उर्वरकों के उपयोग की मात्रा तक भी तय है। किसान के द्वारा निर्धारित मात्रा में उर्वरकों के इस्तेमाल से अच्छी पैदावार भी अर्जित की जा सकती है।

जानें लाल केले की विशेषताओं और फायदों के बारे में

आज के दौर में किसान फसलों और फलों की आधुनिक एवं नवीन प्रजातियों के बीज बोकर अच्छा खासा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। हालाँकि, कुछ किसान आज भी परंपरागत फसलों का उत्पादन करके अपना जीवनयापन कर रहे हैं। इसी कड़ी में लाल केला भी बाजार में आ चुका है। बतादें, कि लाल केला पीले केले की तुलना में अधिक उत्पादन देता है। इसके एक गुच्छे में करीब 100 केले मौजूद होते हैं। वर्तमान में बाजार के अंदर इस केले का भाव 200 रुपये दर्जन से अधिक होता है।

लाल केले में औषधीय गुण विघमान होते हैं

केला हमारे स्वास्थ के लिए फायदेमंद रहता है। इसका मीठा स्वाद लोगों को काफी भाता है। इसमें बीज नहीं पाए जाने इस वजह से इसका सेवन भी काफी आसान होता है। यह इतना मुलायम होता है, कि बूढ़े, जवान यहां तक कि बच्चे भी इसको बड़े चाव से खा लेते हैं। इसमें विघमान विटामिन सी, विटामिन बी-6, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और विटामिन ए की प्रचूर मात्रा इसको लोगों के मध्य काफी ज्यादा लोकप्रिय बनाती है। दरअसल, आजतक आपने केवल पीला केला ही देखा अथवा खाया होगा। परंतु, हम आपको जिस केला के संबंध में बताने जा रहे हैं, वह लाल केला है। यह दिखने में जितना सुंदर है, स्वाद में भी उतना ही ज्यादा शानदार भी है। इतना ही नहीं इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है, कि इसमें पीले केले से ज्यादा औषधीय गुण विघमान होते हैं।

लाल केला सबसे पहले कहाँ उत्पादित किया गया था

जानकारी के लिए बतादें, कि विशेष रूप से लाल केले की खेती ऑस्ट्रेलिया में पहले की जाती थी। परंतु, बदलते समय के साथ-साथ यह मेक्सिको, अमेरिका और वेस्टइंडीज तक पहुंच गया है। हालांकि, अब भारत में भी किसान इसकी खेती करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में लाल रंग के केले की बड़े पैमाने पर खेती हो रही है। किसान इसकी खेती कर के मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इस केले की मांग इसके रंग के कारण और इसके साथ ही इसमें मौजूद बीटा- कैरोटीन के चलते भी इसकी बाजार में काफी मांग है।

पीले केले के तुलनात्मक लाल केला अधिक पैदावार देता है

लाल केला पीले केले की तुलना में ज्यादा पैदा होता है। लाल केले के एक गुच्छे में करीब 100 केले होते हैं। वर्तमान में बाजार के अंदर इस केले का भाव 200 रुपये दर्जन से अधिक होता है। इसका उत्पादन शुष्क जलवायु में किया जाता है। इस केले का तना काफी ज्यादा लंबा होता है। उत्तर प्रदेश में इसकी खेती मिर्जापुर में की जा रही है। वर्ष 2021 में मिर्जापुर उद्यान विभाग ने लाल केले के 5 हजार पौधे मंगाए थे, इसके उपरांत किसानों के मध्य इन पौधों को वितरित किया गया है।

असली हीरो की ताक़त है आधुनिक तकनीक!

नया 3230 TX Super

45 HP 4WD

33.55 kW

NEW HOLLAND AGRICULTURE

जान भी, शान भी!

श्रेणी में अधिकतम उपयोगी पावर

ऐप्ट्रा PTO और स्वतंत्र PTO क्लच लीवर

स्ट्रेट एक्सल प्लेनेटरी ड्राइव

6 साल T-वारंटी

नियम व शर्तें लागू।

हमारी 6 साल की ट्रांस्फेरेबल वारंटी भारत में बेचे जाने वाले सभी न्यू हॉलैंड ट्रैक्टरों पर लागू है। दिखाए गए उत्पादों के चित्र केवल दृष्टांत उद्देश्य के लिए हैं, इनसे उत्पाद का सटीक प्रतिनिधित्व/चुनाव नहीं हो सकता है। इनका रंग वास्तविक उत्पाद से अलग हो सकता है। *1 hp=0.7457 kW

www.newholland.com/in

गोमूत्र की गंध और स्वाद आपकी पसंद का होगा, क्योंकि अब मनचाहे फ्लेवर में गोमूत्र उपलब्ध

यह फ्लेवर्ड गोमूत्र वर्तमान में 6 प्रकार के भिन्न भिन्न स्वाद में मौजूद है। इन फ्लेवर्स में स्ट्रॉबेरी, पान, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल और मिक्स फ्लेवर है। इसके एक लीटर की कीमत 200 रुपये के लगभग है।

गोमूत्र विगत कुछ सालों से ज्यादा चर्चा में है। दरअसल, इसका उपयोग औषधीय के तौर पर आयुर्वेद में सदियों से किया जाता रहा है। आयुर्वेद की द्रष्टि से देखें तो बहुत सारी गंभीर बीमारियों में भी इसके सेवन से फायदा होता है। भारत सहित संपूर्ण विश्व में ऐसे लाखों लोग हैं, जो इसका उपभोग करते हैं। परंतु, कुछ लोग इसके स्वाद और इसकी बदबू के कारण चाह कर भी इसका सेवन नहीं कर पाते हैं।

गोमूत्र ऑरेंज, आम और पाइनएप्पल फ्लेवर्स में उपलब्ध है

फिलहाल, ऐसे ही लोगों की सुविधा के लिए वैज्ञानिकों द्वारा फ्लेवर्ड गोमूत्र तैयार किया गया है। इसका अर्थ यह है, कि फिलहाल गोमूत्र आपको अलग-अलग प्रकार के स्वाद में मिल पाऐगा। यदि आपको आम पसंद है तो गोमूत्र आम फ्लेवर में मिल जाएगा। यदि आपको संतरा पसंद है तो गोमूत्र ऑरेंज फ्लेवर में मिल पाऐगा। वहीं, यदि आप पाइनएप्पल के शौकीन हैं, तो आपको गोमूत्र इस स्वाद में भी मिल जाएगा। मतलब कि फिलहाल आप खट्टा, मीठा व नमकीन जैसा स्वाद और सुगंध में चाहेंगे गोमूत्र आपको उसी तरह का मिल जाएगा।

फ्लेवर्ड गोमूत्र को किसने तैयार किया है

गोमूत्र के विभिन्न फ्लेवर्स की यह बड़ी खोज आईआईटी मुंबई से पीएचडी कर चुके डॉक्टर राकेश चंद्र अग्रवाल ने की है। उन्होंने इस फ्लेवर्ड गोमूत्र को नाम संजीवनी रस रखा है। इस खोज के उपरांत गोमूत्र विभिन्न फ्लेवर्स में पूरे भारत में उपलब्ध है। भिन्न-भिन्न प्रयोग शालाओं में इसको तैयार करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। डॉ. राकेश इसको लेकर दीर्घ काल से शोध कर रहे थे और अंततः उन्हें सफलता मिल ही गई। डॉ. राकेश का कहना है, कि गोमूत्र में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के गंभीर रोगों से ग्रसित होने से बचाते हैं। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया है, कि फिलहाल वह फ्लेवर्ड गोमूत्र तैयार कर इसको घर-घर तक उपलब्ध करा देंगे।

फ्लेवर्ड गोमूत्र का नाम संजीवनी रस रखा है

मीडिया की खबरों के अनुसार, आपको बतादें कि यह फ्लेवर्ड गोमूत्र वर्तमान में 6 प्रकार के अलग-अलग स्वाद में मौजूद है। इन फ्लेवर्स में पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, पान, मैंगो, ऑरेंज और मिक्स फ्लेवर है। इसको तैयार करने के लिए फूड ग्रेड कलर एवं एसेंस का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में यह कोटा की 6 गोशालाओं में बनाया जा रहा है। लेकिन, आहिस्ते आहिस्ते इसको बड़े पैमाने पर तैयार करने की भी योजना है। यदि आप भी इस प्रकार का फ्लेवर्ड गोमूत्र चाहते हैं, तो आपको एक लीटर के लिए न्यूनतम 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

गाय पालन को प्रोत्साहन देने के लिए यह राज्य सरकार अच्छी-खासी धनराशि प्रदान कर रही है।

गाय पालन को प्रोत्साहन देने के लिए यह राज्य सरकार अच्छी-खासी धनराशि प्रदान कर रही है।

पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों की तरफ से अहम कवायद की गई है। यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 900 रुपये पाना चाहते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के तहत खुद को रजिस्टर कराना होगा।

भारत में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। हिंदू धर्म का अनुपालन करने वाले लोग सामान्यतौर पर प्रत्येक जीव से प्यार करते हैं। परंतु, गाय को लेकर उनको विशेष लगाव होता है। हिंदू धर्म में गाय को काफी ज्यादा पवित्र जीव घोषित किया गया है और इसे मां का दर्जा प्रदान किया गया है। यही कारण है, कि गाय के दूध के साथ-साथ उसके गोबर और मूत्र का भी उपयोग सनातन धर्म के धार्मिक कार्यों में होता है। परंतु, फिलहाल, धीरे-धीरे गाय को पालने वाली परंपरा और संस्कृति समाप्त होती जा रही है। इसी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

गाय पालन हेतु किसे धनराशि प्रदान की जाएगी

मध्य प्रदेश सरकार ने यह ऐलान किया है, कि वह प्रति माह उन लोगों को 900 रुपये प्रदान किए जाऐंगे। जो गाय का पालन और जैविक खेती करेंगे। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 22000 किसानों को पहली किश्त जारी भी कर दी है। साथ ही, सरकार द्वारा राज्य में पशु चिकित्सा एंबुलेंस सर्विस का भी शुभारंभ किया है।

योजना का लाभ लेने के लिए क्या करें

यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 900 रुपये पाना चाहते हैं। तो आपको मध्य प्रदेश की सरकारी वेबसाइट पर जाकर इस योजना के चलते स्वयं को पंजीकृत कराना होगा। इसके साथ ही गाय का गोबर भी खरीदने की योजना तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है, कि वह संपूर्ण राज्य में विभिन्न गोबर प्लांट लगा कर गाय के गोबर से सीएनजी तैयार करेंगे।

पशु एंबुलेंस बुलाने के लिए इस नंबर को डायल करें

यदि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और अपने पशु के रोगग्रस्त होने पर एंबुलेंस मंगाना चाहते हैं। तब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1962 नंबर डायल कर देना है। यह नंबर पूर्णतयः टोल फ्री है। इस नंबर को डायल करने पर आपके फोन से एक भी रुपया भी नहीं कटेगा। ऐसा करते ही कुछ ही समय में आपके घर के बाहर पशु एंबुलेंस उपस्थित हो जाएगी।

बढ़ते तापमान और गर्मी से पशुओं को बचाने की काफी आवश्यकता है

जैसा हम जानते हैं, गर्मी के दिन आने शुरू हो चुके हैं। दिनों दिन तापमान में इजाफा होने से पशुओं में संक्रमण फैलने का खतरा अधिक हो जाता है। लंगड़ी रोग पशुओं को सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। इस वजह से उसे रोग प्रतिरोधक टीके वक्त पर लगवाते रहें।

तापमान में इजाफा होने से केवल जनता ही नहीं पशुओं की भी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ऐसी हालत में ज्यादा गर्मी पड़ने पर पशु दूध देना भी कम कर देते हैं। विशेष बात यह है, कि इंसान की भांति दुधारू मवेशियों को गर्म हवाऐं भी लगने का भय रहता है। विभिन्न मामलों में यह देखा गया है कि लू की चपेट में आने से पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। इस वजह से अप्रैल माह में विशेष कर किसान भाई अपने पशुओं को लू और गर्मी से बचाएं। क्योंकि, इस माह में मौसम में तीव्रता से परिवर्तन होता है। इससे जानवरों की सेहत पर प्रभाव पड़ने का संकट मंड़रा जाता है।

पशुपालक बढ़ती गर्मी और तापमान से अपने पशुओं को बचाऐं

बिहार राज्य के पशु और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा पशुपालकों के लिए से विशेष सावधानियां बरतने की अपील की है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से किसानों को कहा है कि अप्रैल माह में गर्मी काफी हद तक बढ़ जाती है। इससे पशुओं को लू लगने का खतरा अधिक हो जाता है। साथ ही, गर्मी की वजह से दूध की पैदावार काफी कम हो जाती है। मवेशियों के शरीर में जल और नमक की मात्रा कम हो जाती है। साथ ही, गाय- भैंस को भूख भी काफी कम लगने लगती है।

अगर आपकी गाय-भैंस में इस प्रकार के लक्षण नजर आ रहे हैं, तब आप समझलें कि वह लू और गर्मी की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में मवेशियों को अतिशीघ्र पशु चिकित्सकों से दिखाना चाहिए।

पशुओं को हरा चारा अधिक मात्रा में खिलाऐं

यदि आप अपने पशुओं को लू और गर्मी के प्रभाव से बचाना चाहते हैं, तो उन्हें असहनीय धूप होने से पूर्व ही छाया में बांध दें। साथ ही, किसानों को समयानुसार ताजा पानी पिलाया जाए, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो पाए। साथ ही, मवेशियों को खाने के लिए हरा चारा अधिक दें। यदि हो सके तो किसान भाई अपने पशुओं को एजोला घास चारे के तौर पर प्रदान करें। इससे उसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेड, विटामिन एवं खनिज प्रचूर मात्रा प्राप्त हो सकेंगे।

गर्मी बढ़ने पर पशुओं में फॉस्फोरस की काफी कमी आ जाती है

साथ ही, गर्मी व तापमान बढ़ने से मवेशियों में संक्रमण फैलने का खतरा काफी बढ़ जाता है। लंगड़ी रोग पशुओं को सबसे ज्यादा परेशान करता है। इस वजह से उसे रोगरोधी टीके वक्त पर लगवाते रहें। साथ ही, गर्मी बढ़ने पर मवेशियों में फॉस्फोरस की कमी आ जाती है। इससे मवेशी स्वयं का पेशाब पीना चालू कर देते हैं। साथ ही, मिट्टी भी चाटने लग जाते हैं। इससे उन्हें बीमार पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। इस वजह से पशुओं को चारे में नमक मिलकार खिलाएं। इससे उनके शरीर में फॉस्फोरस की कमी नहीं आएगी। साथ ही, पशुओं को दिन में न्यूनतम चार बार पानी पिलाएं और हवादार स्थान पर रखें। इससे वह काफी सेहतमंद रहेंगे।

पशुपालन में इन 5 घास का इस्तेमाल करके जल्द ही हो सकते हैं मालामाल

भारत दुनिया का सबसे बाद दुग्ध उत्पादक देश है। दुनिया में उत्पादित होने वाले कुल दूध का 24 फीसदी उत्पादन अकेले भारत में होता है। इस बीच भारत की बड़ी जनसंख्या की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार लगातार पशुपालन को प्रोत्साहित कर रही है। ताकि देश में पशुओं से प्राप्त उत्पादों की पूर्ति की जा सके। इसके लिए सरकार समय-समय पर कई योजनाएं लॉन्च करती रहती है। जिससे किसानों को फायदा होता है और देश में पशुपालन में बढ़ोत्तरी होती है। लेकिन इन सब के बीच किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या पशु चारे को लेकर है, जिसके बिना पशुपालन संभव नहीं है। भारत में ऐसे कई पशुपालक या किसान हैं जो अपने पशुओं को उच्च गुणवत्ता वाला पशु चारा उपलब्ध नहीं करवा पाते जिसके कारण कई बार दुग्ध उत्पादन में कमी आती है और किसानों को इस व्यवसाय से अपेक्षाकृत कमाई नहीं हो पाती। इसलिए आज हम ऐसे हरे चारे की किस्मों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी मदद से दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी, साथ ही पशुओं को अतिरिक्त पोषण मिलेगा जिससे पशु स्वस्थ्य रहेंगे और उन्हें किसी प्रकार का रोग नहीं होगा।

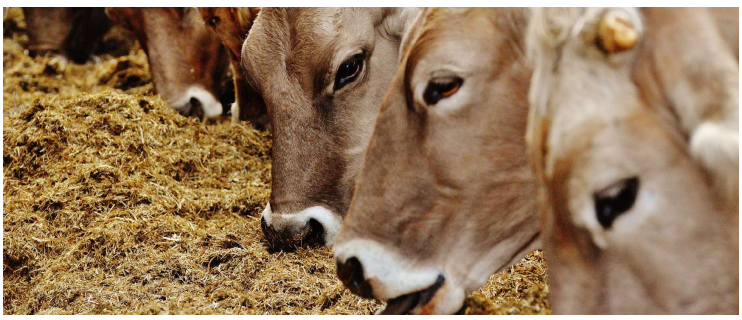

नेपियर घास :

यह घास गन्ने की तरह दिखती है, जिसे हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। यह बेहद कम समय में उग जाती है, साथ ही यह पशुओं में दूध की क्षमता बढ़ाती है, जिससे इसे बेहतरीन पशु आहार कहा जाता है। नेपियर घास मात्र 2 माह में तैयार हो जाती है। इसको खाने के बाद पशु चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं। नेपियर घास हर तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है। इस घास की खेती में ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। इस घास को एक बार लगाने के बाद किसान अगले 4 से 5 साल तक हरा चारा ले सकते हैं, इस हिसाब से इस घास की खेती में ज्यादा लागत भी नहीं आती है। जिन भी किसानों के पास 4 से 5 पशु हैं वो आधा बीघा खेत में नेपियर घास को लगा सकते हैं। इसे खेतों की मेड़ पर भी लगाया जा सकता है। इस घास में प्रोटीन 8-10 फ़ीसदी, रेशा 30 फ़ीसदी और कैल्सियम 0.5 फ़ीसदी होता है। अगर इस घास को दलहनी चारे के साथ मिलाकर पशुओं को खिलाया जाए तो यह ज्यादा लाभकारी साबित होती है।

बरसीम घास :

बरसीम घास खाने से पशुओं का पाचन सबसे अच्छा रहता है, इसलिए किसान भाइयों को पशुओं के खाने में इसे जरूर मिलाना चाहिए। यह घास कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है,इसलिए इसके सेवन से पशुओं के दूध देने की क्षमता में

बढ़ोत्तरी होती है। सबसे पहले इसकी खेती प्राचीन मिस्त्र में की जाती थी। भारत में इसका उत्पादन उन्नीसवीं शताब्दी में आरम्भ हुआ है। वर्तमान में अमेरिका और यूरोप में पशु चारे के रूप में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। भारत में यह घास मुख्यतः नवम्बर से मई तक उगाई जाती है। यह एक दलहनी फसल है, इसलिए इसकी खेती से मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। बरसीम में प्रोटीन, रेशा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम तथा पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं।

जिरका घास :

यह एक ऐसी घास है जिसको उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इसलिए इसकी खेती मुख्यतः राजस्थान, गुजरात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में की जाती है। इस घास को पशुओं को खिलाने से उनका हाजमा सही रहता है, जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। इसकी बुवाई अक्टूबर से नवंबर माह के बीच की जाती है। जो भी किसान अपने पशुओं में दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने पशुओं को जिरका घास जरूर खिलाएं।

पैरा घास :

पैरा घास की खेती दलदली और अधिक नमी वाली जमीनों पर की जाती है। अगर खेतों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा होता है तो यह घास तेजी के साथ बढ़ती है। बुवाई के 70 से 80 दिनों के बाद इस घास की पहली कटाई कर सकते हैं। इसके बाद 35 से 40 दिनों बाद इसकी कटाई की जा सकती है। इस घास में 6 से 7 प्रतिशत प्रोटीन होता है। इसके अलावा घास में 0.76 फीसदी कैल्शियम, 0.49 फीसदी फास्फोरस और 33.3 फीसदी रेशा होता है। यह घास करीब 5 मीटर ऊंचाई तक बढ़ सकती है। आमतौर पर पैरा घास की बुवाई मई से लेकर अगस्त के बीच की जाती है। इस घास के खेती नदी और तालाब के किनारे ऐसी जगह पर भी की जा सकती है जहां जुताई बुवाई संभव नहीं होती। पैरा घास की पहली कटाई बुवाई से 70 से 75 दिन बाद की जा सकती है। इसके बाद हर 35 दिन बाद इसकी कटाई की जा सकती है।

गिनी घास :

गिनी घास की खेती छायादार जगहों में की जाती है। भारत में मुख्य तौर पर इसकी खेती फलों के बागों में की जाती है। इस घास की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है। इसकी बुवाई जून और जुलाई माह में की जाती है। बुवाई के समय इस घास की जड़ों की रोपाई की जाती है। इस इस की पहली कटाई बुवाई के 4 माह बाद की जाती है। इसके बाद हर 40 दिन में इस घास की कटाई की जा सकती है। गिनी घास पोषक तत्वों से भरपूर होती है, इसलिए इस घास को पशुओं को खिलाकर अच्छा खासा दुग्ध उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

फसलों पर कीटनाशकों का प्रयोग करते समय बरतें सावधानी, हो सकता है भारी नुकसान

फसलों पर कीटों का हमला होना आम बात है। इसलिए लोग पिछली कई शताब्दियों से कीटों से छुटकारा पाने के लिए फसलों पर कीटनाशकों का प्रयोग करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि किसानों ने रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा दिया है। साथ ही जैविक कीटनाशकों का प्रयोग तेजी से कम हुआ है। बाजार में उपलब्ध सभी कीटनाशकों को प्रमाणिकताओं के आधार पर बाजार में बेंचा जा है, इसके बावजूद रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से फसलों को नुकसान होता है और किसान इससे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं।

इन दिनों बाजार में विभिन्न तरह के कीटनाशक उपलब्ध हैं। लेकिन इनको खरीदने के पहले किसान को पूरी जानकारी होना आवश्यक कि वो किस कीटनाशक को खरीद रहे हैं और वह रोग को खत्म करने में सहायक होगा या नहीं। वैसे आजकल बाजार में ऐसे कीटनाशी भी आ रहे हैं जिनका प्रयोग अलग-अलग फसल के लिए भी कर सकते हैं। इससे फसल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। सरकार ने कुछ कीटनाशकों को कुछ फसलों के लिए निर्धारित किया है। इन चुनी गई फसलों में विशेष कीटनाशक ही डाले जा सकते हैं।

कई बार देखा गया कि कीटनाशकों के कारण फसलें नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। इसलिए सरकार ने कुछ कीटनाशकों को बाजार में बेंचने से प्रतिबंधित कर दिया है। इनमें मालाथयॉन कीटनाशक प्रमुख है। इसका उपयोग ज्वार, मटर, सोयाबीन, अरंडी, सूरजमुखी, भिंडी, बैगन, फूलगोभी, मूली की खेती में किया जाता था। इसके अलावा क्युनलफोस और मैनकोजेब को प्रबंधित किया जा चुका है। इन दोनों कीटनाशकों का उपयोग जूट, इलायची, ज्वार, अमरुद और ज्वार की फसल में किया जाता था।

सरकार ने फसलों के ऊपर खतरे को देखते हुए अक्सिफलोरफेन और क्लोरप्यरिफोस को भी प्रतिबंधित कर दिया है। इनका प्रयोग आलू, मूंगफली, बेर, साइट्रस और तंबाकू की फसलों में किया जाता था। कई बार ये कीटनाशक फसलों के साथ-साथ आम लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीटनाशक खाद्य चीजों के साथ आपकी खाने की थाली में पहुंच जाते हैं और आपके भोजन का हिस्सा बन जाते हैं। जो मानव शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह होते हैं।

ESCORTS

THE POWERTRAC
EURO 55 NEXT

#TechnologyDesignedToDeliver

55 HP ENGINE | 2-WHEEL DRIVE | 15-SPEED GEARBOX | INDEPENDENT PTO | 2,000KG SENSI 1 LIFT

EQUIPPED WITH ADVANCED TECHNOLOGY FOR HIGH-END APPLICATION

POWERTRAC

देश का # 1 किफ़ायती ट्रैक्टर

इन सब्जियों की खेती से किसान कम खर्चा व कम समय में अधिक आमदनी कर सकते हैं

आज के समय में किसान भाई बागवानी की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। बतादें, कि पालक, राजमा, करेला और भिंडी की खेती करके कम वक्त में अधिक आमदनी अर्जित कर सकते हैं। ये सब्जियां लगभग 50 से 100 दिन की समयावधि में ही उत्पादित हो जाती हैं।
यदि आप भी खेती किसानी किया करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। आज हम आपको इस लेख में बताएंगे ऐसी 5 सब्जियों की खेती के विषय में जिनका उत्पादन कर आप पूरे माह में हजारों-लाखों रुपये की आमदनी कर सकते हैं। अब जानते हैं उन सब्जियों के बारे में जो किसानों को अच्छी-खासी आमदनी करा सकती हैं।

भिंडी की सब्जी

किसान भाई यदि प्रत्येक सब्जी में भिंड़ी का ही उत्पादन करता है तो वह निश्चित रूप से अच्छी-खासी आमदनी कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि भिंडी की फसल की बुवाई के मात्र 50 दिन के बाद तैयार हो जाती हैं। भिंडी की बुवाई करने में करीब 20 से 25 हजार रुपए लग जाते जाते हैं। इससे किसान करीब 80 क्विंटल तक की पैदावार हांसिल कर सकते हैं। वर्तमान में बाजार के अंदर भिंडी का भाव तीन हजार रूपए प्रति क्विंटल चल रहा है। यदि किसान 80 क्विंटल भिंडी का उत्पादन करता है। तब वह उससे लगभग 2 लाख रुपए तक का मुनाफा उठा सकते हैं।

पालक की सब्जी

बतादें, कि पालक की बुवाई किसान भाई तीन सीजन में कर सकते हैं। पालक की खेती के लिए किसी विशेष मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। 17 हजार रुपये में लगभग 1 एकड़ भूमि में खेती हो सकती है। इससे लगभग 100 क्विंटल तक पैदावार मिलती है। बाजार में किसानों को इसके लिए औसतन 5 रुपये प्रति किलो का भाव प्राप्त होता है। पालक की खेती करने से किसान भाई काफी कम समय में करीब 50 हजार रुपये की आय कर सकते हैं।

राजमा की सब्जी

राजमा की फसल करीब 100 से भी कम दिन में पककर तैयार हो जाती है। 10 से 12 क्विंटल राजमा की पैदावार के लिए किसान भाइयों को लगभग 1 एकड़ में उत्पादन करना होता है। राजमा की फसल की कीमत बाजार में बेहद अच्छी है। किसानों को 1 क्विंटल राजमा की कीमत लगभग 11-12 हजार मिलती है। अब ऐसी स्थिति में वह लगभग 35 हजार रुपये लगाकर 1 लाख रुपये से ज्यादा उठा सकते हैं।

करेला की सब्जी

किसान भाई करेला की खेती करके अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं। दरअसल, करेला की फसल 50 से 55 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। एक एकड़ खेती में लगभग 55 हजार रुपये का खर्चा होता है। इसमें लगभग 100 क्विंटल करेला की पैदावार हो जाती है। बाजार में भी इसकी अच्छी-खासी कीमत होती है। किसान कुछ ही दिनों के अंदर एक- से डेढ़ लाख रुपये तक की आमदनी कर सकते हैं।

कीटनाशक कितना खतरनाक है, इसका पता हम रंग से भी लगा सकते हैं

जैसा कि हम सब जानते हैं, कि कीटों का खत्मा करने के लिए किसान खेतों में कीटनाशक का इस्तेमाल किया करते है। साथ ही, इसकी पैकेट पर प्रदर्शित रंगों से इसकी तीव्रता का पता चल जाता है। इनमें लाल रंग सर्वाधिक तीव्रता वाला होता है।

खेती से उत्तम उत्पादन पाने के लिए जितनी आवश्यक मृदा है, उतनी ही आवश्यक जलवायु भी होती है। बीज का उत्तम होना भी काफी महत्वपूर्ण होता है। साथ ही, फसल का कीटों से संरक्षण करने के लिए उत्तम कीटनाशक का चुनाव अत्यंत आवश्यक होता है। बाजार में सैंकड़ों की तादात में कीटनाशक विघमान होते हैं। इनका समुचित चयन काफी जरूरी होता है। परंतु, कौन सा कीटनाशक बेहतरीन ढंग से कार्य करता है। इसका चयन किस प्रकार से किया जाए। कहा जाता है, कि कीटनाशकों के ज्यादा खतरनाक होने की जानकारी रंगों के जरिए से भी की जा सकती है। यह रंग कीटनाशकों के पैकेट पर भी लगा हुआ होता है।

लाल रंग निशान वाले कीटनाशक सबसे खतरनाक होते हैं

लाल रंग खतरे का निशान माना जाता है। रंगों के संबंध में भी कुछ ऐसा ही है। लाल रंग जहर की तीव्रता को नापने वाले पैमाने पर सबसे ज्यादा होता है। अब अगर किसी कीटनाशक के पैकेट के पीछे लाल रंग का लोगो है, तो यह सबसे तीव्र कीटनाशक रसायन के रूप में माना जाता है।

पीला रंग दूसरे स्तर पर खतरनाक कीटनाशक माना जाता है

लाल रंग के उपरांत पीले रंग को खतरनाक स्तर के मामले में दूसरे स्तर का कीटनाशक माना जाता है। खेत में इसका कितना इस्तेमाल किए जाना चाहिए। इसके पैकेट पर लिखा हुआ होता है। हालांकि, कृषि विशेषज्ञों से इसकी सलाह भी ली जा सकती है।

नीला रंग वाले मध्यम स्तर की तीव्रता रखते हैं

कीटनाशक के पैकेट का रंग यदि नीला होता है। उसकी तीव्रता मध्यम स्तर पर होती है। मतलब साफ है, कि यह लाल एवं पीले रंग से कुछ कम खतरनाक होता है। कृषि वैज्ञानिक डॉ. विवेक राज का कहना है, कि हर फसल में भिन्न-भिन्न प्रकार के कीट लगते हैं। उनकी तीव्रता भी ज्यादा और कम हो सकती है। इसी तीव्रता के आधार पर किसानों को कीटनाशक इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा है, कि कोई भी किसान खेत में कीटनाशक इस्तेमाल करने से पूर्व कृषि एक्सपर्ट से सलाह जरूर प्राप्त करे।

हरा रंग वाले कीटनाशकों में न्यूनतम स्तर की तीव्रता होती है

जिस पैकेट का रंग हरा होता है, उसकी तीव्रता न्यूनतम होती है। ऐसे में खेती में कम कीटनाशक होने अथवा फिर कीटनाशक के खतरे को देखते हुए इस प्रकार के कीटनाशकों के उपयोग की सलाह प्रदान की जाती है। अधिकांश किसानों को कीटनाशकों के खतरनाक होने के स्तर की जानकारी नहीं होती है। इसके चलते उनके साथ दुर्घटना होने की संभावना भी होती है।

मिट्टी की सेहत - खाद

वैज्ञानिकों ने तैयार की अरहर की नई किस्म, कम जल खपत में देगी अधिक उपज

राजस्थान राज्य में स्थित कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने अरहर की नई किस्म तैयार करली है। इस किस्म में कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही आमदनी में भी इजाफा देखने को मिलेगा।

देश के किसान दलहन, तिलहन एवं अन्य बागवानी फसलों का उत्पादन करके मोटी आय कर लेते हैं। आए दिन प्रदूषण में होने वाली वृद्धि के साथ-साथ खराब होती जलवायु का प्रभाव फसलों की पैदावार पर भी देखने को मिला है। अच्छी खेती के लिए अच्छा बीज होना भी अत्यंत आवश्यक है। बीज उत्पादकता बढ़ाने, कम जल खपत और बाकी गुणवत्ताओं से युक्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर कृषि वैज्ञानिक निरंतर उन्नत किस्म के बीज विकसित करने के लिए शोध में लगे रहते हैं। हाल ही, में ऐसा ही शोध वैज्ञानिकों की तरफ से किया गया है। बतादें, कि अरहर के उन्नत बीज से देश के किसान अंधाधुंध कमाई कर सकेंगे। नवीन प्रजाति के आने से किसान काफी प्रशन्न हैं।

वैज्ञानिकों ने अरहर की नई प्रजाति एएल-882 तैयार की है

भारत के अंदर बड़ी तादात में किसान दलहन फसलों की बुवाई करते हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक, कोटा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक अरहद की नवीन किस्म को तैयार करने के लिए विगत 2 वर्षों से नई प्रजाति विकसित करने में जुटे हुए थे। अब जाकर वैज्ञानिकों के हाथ सफलता लग पाई है। वैज्ञानिकों ने अरहर की नई किस्म एएल-882 तैयार की है। इस प्रजाति के दानों का वजन सिर्फ 8 से 9 ग्राम के आसपास ही है।

इस किस्म से 16 से 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक

मुख्य बात यह है, कि अरहर के बीजों का वजन भी कुछ ज्यादा नहीं होता है। इनका वजन मात्र 8 से 9 ग्राम तक ही होता है। अरहर की इस किस्म की खासियत यह है, कि इसका उत्पादन 16 से 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकता है। ज्यादा उत्पादन होने की वजह से किसानों को बेहतरीन आमदनी भी हो सकेगी। साथ ही, यह नई किस्म रोग प्रतिरोधक किस्म है। वहीं, अरहर की इस किस्म में होने वाला उखटा रोग भी नहीं हो पाएगा।

आईसीएआर ने भी स्वीकृति प्रदान की है

अरहर की इस किस्म को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) की तरफ से स्वीकृति भी दे दी गई है। किसान खेतों में इस किस्म के बीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके पौधों की ऊंचाई लगभग 200 से 210 सेमी होती है। दानों का रंग भूरा रहता है, अधिक पैदावार पाने के लिए फूल निकलने पर ही एनपीके घुलनशील उर्वरक का नियमित मात्रा के अनुरूप छिड़काव किया जा सकता है।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने नौकरी छोड़कर केसर का उत्पादन शुरू किया, वेतन से कई गुना ज्यादा कमा रहा मुनाफा

भारत में केसर की खेती कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक स्तर पर होती है। बाजार में इसकी कीमत काफी ज्यादा है। अब तक एक किलो केसर की मूल्य 3 लाख रुपये है।

केसर का नाम कान में पड़ते ही दिमाग में सर्व प्रथम कश्मीर का नाम आता है। लोगों का यह मानना है, कि भारत के अंदर केवल कश्मीर जैसे सर्द मौसम वाले क्षेत्रों में ही केसर का उत्पादन किया जाता है। परंतु, यह बातें अब काफी पुरानी हो चुकी हैं। फिलहाल, आधुनिक तकनीक के माध्यम से लोग गर्म राज्यों में भी केसर का उत्पादन कर रहे हैं। इससे किसान भाइयों की अच्छी-खासी आमदनी भी हो रही है। आज हम एक ऐसे ही किसान के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ कर केसर की खेती चालू की है। किसान ने इसमें काफी सफलता भी अर्जित की है।

शैलेश मोदक कहाँ के रहने वाले हैं

द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी की खबरों के अनुसार, पुणे जनपद निवासी शैलेश मोदक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने 13 वर्ष तक विभिन्न कंपनियों में अच्छे-खासे वेतन पर नौकरी की है। अचानक से उनके मन में केसर की खेती करने का विचार आया। विचार आने के बाद शैलेश मोदक ने नौकरी छोड़कर कंटेनर के अंदर केसर की उत्पादन आरंभ कर दिया। इससे उनको लाखों रुपये की आमदनी भी हो रही है। शैलेश ने कहा है, कि आहिस्ते-आहिस्ते वह कंटेनरों की संख्या में बढ़ोत्तरी करेंगे।

शैलेश मोदक किस तरह से केसर की खेती करते हैं

शैलेश मोदक शिपिंग कंटेनर के भीतर केसर का उत्पादन करने के लिए तापमान को नियंत्रण में रखते हैं। शैलेश मोदक का कहना है, कि वह कंटेनर के अंदर हाइड्रोपोनिक तकनीक से बाकी फसलों का भी उत्पादन कर रहे हैं। विशेष कर वह हाइड्रोपोनिक तकनीक से महंगी सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, जिसकी विदेशों में काफी ज्यादा मांग है। वर्तमान में शैलेश मोदक अन्य किसानों को भी केसर का उत्पादन करने के लिए बारीकियों को सीखा रहे हैं।

भारत में केसर की अधिक मांग को देखते हुए शैलेश केसर की खेती का रकबा बढ़ाएंगे

बतादें, कि भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। बाजार में इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। अभी एक किलो केसर का मूल्य 3 लाख रुपये है। शैलेश अभी कंटेनर के भीतर 160 स्क्वायर फीट में केसर का उत्पादन कर रहे हैं।

इससे वह करीब 5 से 6 किलो तक केसर की पैदावार अर्जित कर रहे हैं। शैलेश मोदक का कहना है, कि वह 6 साल से केसर की खेती करते आ रहे हैं। इससे पूर्व वह मधुमक्खी पालन किया करते थे। भारत में 4 टन ही केसर की पैदावार होती है, जबकि मांग लगभग 100 टन की है। ऐसे में मांग की आपूर्ति करने के लिए विदेशों से केसर का आयात किया जाता है। विशेष कर ईरान, अफगानिस्तान और नीदरलैंड से सर्वाधिक केसर का आयात किया जाता है। शैलेश मोदक की योजना है, कि आगामी वर्षों में वह 320 वर्ग फीट में केसर का उत्पादन किया करेंगे।

युवा किसान ने मिसाल पेश की सिर्फ 2 महीने में ही इस फसल से कमाए लाखों

सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने नौकरी छोड़कर केसर का उत्पादन शुरू किया, वेतन से कई गुना ज्यादा कमा रहा मुनाफा

आजकल किसान आधुनिकता और मशीनीकरण की तरफ अग्रसर होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है 27 वर्षीय युवा किसान जिसका नाम शिव शर्मा है। जानकारी के लिए बतादें गुर कि वह अशोकनगर जनपद में मौजूद गांव मढ़खेड़ा का मूल निवासी है। उसने तीन वर्ष पूर्व एक किसान से बीज खरीदकर खरबूजे की खेती करना शुरू किया था।

मध्य प्रदेश के एक युवा किसान ने अन्य किसानों के समक्ष एक मिसाल पेश की है। इसने खरबूजे की खेती से केवल 2 माह के अंदर ही लाखों रुपये की आमदनी कर ली है। इसके इस हुनर एवं काबिलियत से आसपास के किसान भाई बेहद प्रभावित हुए हैं। ऐसी स्थिति में बाकी युवक भी इस किसान से खरबूजे की खेती करने का तरीका और गुर सीख रहे हैं। विशेष बात यह है, कि इस किसान ने 45 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रखा है। दरअसल, जब इस युवा किसान ने खरबूजे की खेती चालू की थी, तब लोग काफी मजाक उड़ाया करते थे। परंतु, फिलहाल आमदनी होनी शुरू हुई तो सभी लोग चुप हो चुके हैं।

दैनिक भास्कर की खबरों के अनुसार, 27 वर्षीय इस युवा किसान का नाम शिव शर्मा है। वह अशोकनगर जनपद के अंतर्गत गांव मढ़खेड़ा का मूल निवासी है। उसने तीन वर्ष पूर्व एक किसान से बीज लेकर खरबूजे की खेती चालू की थी। देखते ही देखते वह खरबूजे की खेती में निपुड़ और सशक्त खिलाड़ी बन गया है। उसने प्रारंभ में 35 बीघे में खरबूज की खेती की थी। इससे उसको लाखों रुपये की आमदनी हुई थी। इससे शिव शर्मा का और ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ा। अगले वर्ष शिव शर्मा ने 50 बीघे भूमि में खरबूज की खेती शुरू की, जिससे उनको काफी ज्यादा आमदनी हुई।

बाजार में कितने रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा खरबूजे का बीज

यही कारण है, कि इस वर्ष शिव शर्मा ने 120 बीघे जमीन में खरबूजे की खेती की है। इससे उन्होंने मात्र 2 माह के अंदर ही लागत को हटाकर 18 लाख रुपये का फायदा हुआ है। उनके खेत में आज भी 50 मजदूर प्रतिदिन कार्य करते हैं। विशेष बात यह है, कि शिव शर्मा खरबूज के बीज का व्यवसाय करता है। उसने बताया है, कि एक बीघे से लगभग एक क्विंटल खरबूज के बीज प्राप्त हो जाते हैं। बीज के अतिरिक्त खरबूज की बिक्री भी होती है। उसने कहा है, कि खरबूज से बीज निकालने के उपरांत फल को फेंक दिया जाता है। अभी बाजार में 25 हजार रुपये प्रति क्विंटल खरबूजे का बीज बेचा जा रहा है।

हाथरस खरबूजे से बीज निकालने वाला सर्वोच्च केंद्र है

शिव शर्मा के मुताबिक, 24 वर्ष की आयु में उन्होंने खरबूजे की खेती चालू की थी। तब दोस्तों ने उसका काफी मजाक उड़ाया था। हालांकि, उसने हिम्मत नहीं हारी एवं अपना कार्य जारी रखा था। बतादें, कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में खरबूजे से बीज निकालने का सर्वोच्च केंद्र है। परंतु, अशोकनगर से भी हाथरस खरबूजे के बीज की आपूर्ति होती है। शिव शर्मा का कहना है, कि अभी उसके यहां प्रतिदिन 200 से 250 लोग खरबूज खरीदने हेतु आते हैं।

MERIKHETI